चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 27 फरवरी– 05 मार्च 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश चुनाव

तुम मुझे मारो मैं तुम्हें मारूं

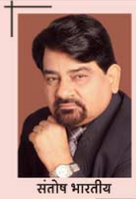

संतोष भारतीय

उत्तर प्रदेश में चुनावों के लिए वोट पड़ रहे हैं. पंजाब और गोवा के वोट पड़ चुके हैं. भारी संख्या में मतदान हुआ है. लोकतंत्र में लोगों का फैसला ही सर्वोपरी होता है, चाहे वो किसी की नज़र में सही हो, या किसी की नज़र में गलत हो. इस चुनाव में बहुत सारे अंतर्विरोध भी दिखाई दिए. हम आपको कुछ स्थितियां बताते हैं, ताकि आप खुद इस बात का फैसला कर सकें कि इन चुनावों में वोट पड़े हैं, तो फैसला किसके पक्ष में जाएगा.

बात शुरू करने या स्थितियों का जायजा लेने से पहले हम आपको दो घटनाएं बताते हैं. एक घटना में नाम है, एक घटना में संकेत है. जिनमें संकेत हैं, उन्हें आप समझें कि उसके पात्र कौन–कौन हैं.

एक अभिनेत्री, एक नेता और उत्तर प्रदेश

देश की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री अपने एक गहरे मित्र के साथ बैठी हुई थीं. दोनों की बातचीत राजनीतिज्ञों पर शुरू हुई, क्योंकि आजकल अभिनेत्री, अभिनेता और राजनेता न केवल हम प्याला–हम निवाला होते हैं, बल्कि अपनी परिधि और अपनी सीमाएं भी खुद बनाते हैं. इस अभिनेत्री ने अपने दोस्त से कहा कि चलो मैं तुम्हें एक खेल दिखाती हूं, जो रियल लाइफ ड्रामा है, पर शर्त ये है कि तुम चुप रहोगे. अगर सांस की आवाज भी फोन में आ गई, तो तुम्हारा सारा मजा किरकिरा हो जाएगा. उस दोस्त ने हामी भर दी. इस अभिनेत्री को यहां हम पीडी नाम देते हैं. पीडी ने देश के एक बड़े नेता को फोन मिलाया. ये नेता उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के उन 8 बड़े नेताओं में शामिल हैं, जो मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं. फोन पर इस नेता को जैसे ही पीडी की आवाज सुनाई दी, उन्होंने बहुत लरजते हुए स्वर में कहा कि आज तो मेरी शाम बन गई. लेकिन अगर आप मेरे पास होतीं, तो मैं बहुत सुकून से सोता. पीडी ने बहुत ही मधुर आवाज में इस नेता से बात की कि ऐसा क्या हो गया कि आपको मेरी आवाज से इतना सुकून हुआ. इस अंदाज में लगभग पांच मिनट तक फोन पर दोनों की बातचीत हुई. बातचीत खत्म होने के बाद पीडी का दोस्त थोड़ा भौचक्का था, क्योंकि पहले उसने पीडी से कहा था कि मुझे भरोसा ही नहीं होता कि तुम जो कह रही हो, वह सही है. इसका सबूत पीडी ने अपने दोस्त को दे दिया था, बातचीत करते हुए फोन को स्पीकर पर लगाकर. दोस्त ने कहा कि अब मुझे बताओ कि ये सब बात क्या है और कहां तक पहुंची है? पीडी ने पहले तो बताने से मना कर दिया, लेकिन इसके बाद सारी घटनाएं उसने अपने दोस्त को बताईं.

पीडी के सेक्रेटरी ने पीडी से कहा कि आज मुझे थोड़ा सा गंवार दिखने वाला उत्तर प्रदेश का एक आदमी मिला, वो आपसे मिलना चाहता है. पीडी ने उससे कहा कि मैं किसी से नहीं मिलूंगी, तुम किसी का भी प्रस्ताव ले के आ जाते हो. तो सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, वो डायमंड की पांच कैरेट की अंगूठी और पांच कैरेट के इयर रिंग्स आपको गिफ्ट करना चाहता है. पीडी ने फौरन कहा कि उसे बुला लो. अगले दिन वो व्यक्ति पीडी से मिला और पीडी को गिफ्ट दिया. गिफ्ट देने के बाद उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी की ब्रांड एंबेसडर बनें. उस शख्स को यहां हम एसएन कहेंगे. ये उत्तर प्रदेश के एक शहर का बड़ा बिल्डर है, या अपकमिंग बिल्डर है. उसने पीडी से कहा कि आप अगर मेरी कंपनी की ब्रांड एंबेसडर बनेंगी, तो मेरे बनाए हुए मकान ज्यादा अच्छी तरह से बिक जाएंगे. पीडी ने हामी भर दी. उसके बाद ये शख्स पीडी को महंगे–महंगे तोहफे भेजने लगा. एक दिन इस शख्स ने कहा कि मैं आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहता हूं. पीडी ने उसे बुला लिया.

एसएन ने पीडी से कहा कि एक शख्स (एक बड़ा राजनेता) आपसे मिलना चाहता है. पीडी ने नाम सुना, तो मिलने की हामी भर दी. एसएन ने कहा कि कल शाम को वो शख्स मुंबई में होगा और वहां आपसे मुलाकात करेगा. पीडी ने कहा कि मुलाकात में क्या मैं अपने मैनेजर को साथ ला सकती हूं. एसएन ने कहा, जरूर ले आइए. अगले दिन कोलाबा के ताजमहल होटल के प्रेसिडेंशियल सुइट में रात 9 बजे पीडी की मुलाक़ात उस शख्स से हुई. मुलाक़ात में 10 मिनट के बाद पीडी ने अपने मैनेजर को

इशारा किया और मैनेजर सुइट के ड्राइंग रूम में बैठ गया. इस बड़े राजनेता और पीडी के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसमें उसने पीडी की बहुत तारीफ की. इस दौरान उस शख्स ने पीडी से कहा कि मैं तुम्हें मूनलाइट यानी चांदनी रात में ताजमहल दिखाना चाहता हूं. पीडी मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखती रह गई. उस शख्स ने पीडी से यह भी पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं. पीडी ने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं. उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी में बहुत खुश रहें, सुखी रहें. यह मुलाक़ात लगभग डेढ़ घंटे चली, फिर खाने–पीने के बाद पीडी अपने मैनेजर के साथ घर आ गई. अगले दिन से इस शख्स ने पीडी को बहुत अपनेपन के मैसेजेज भेजने शुरू किए. इसके दो हफ्ते के बाद एसएन ने पीडी से कहा कि आपको एक फंक्शन में लखनऊ में आना है, आपके वो मित्र आपको आमंत्रित कर रहे हैं. एसएन ने पीडी से ये भी कहा कि वे आपके प्यार में वशीभूत हो गए हैं और आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं. पीडी ने कहा कि पागल हो गए हो, वो इतने बड़े हैं, शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं. तो एसएन ने कहा कि इससे क्या हुआ. बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं, बहुत से लोगों को बच्चे हैं, लेकिन वो प्यार करते हैं. पीडी को उसके ऊपर भरोसा नहीं हुआ. उसे लगा कि ये गॉसिप है. हालांकि वो स्पेशल हवाईजहाज से तय समय पर लखनऊ पहुंची. लखनऊ में कोई कार्यक्रम नहीं था. एक बड़े पॉश गेस्ट हाउस में पीडी की मुलाक़ात उस शख्स से हुई. उस शख्स ने पीडी से कहा कि पीडी मैं चाहता हूं कि मैने आपको चाहा है, तो आपको जिंदगी में कभी दु:ख नहीं हो. बताइए आप कहां रहती हैं. पीडी ने बताया कि मैं एक छोटे फ्लैट में रहती हूं, लेकिन एक बड़ा फ्लैट खरीदना चाहती हूं. उस शख्स ने पूछा कि उस फ्लैट की कीमत कितनी है, तो पीडी ने कहा कि वो 32 करोड़ का फ्लैट है. अब इस शख्स के चेहरे पर चिंता दिखने लगी. इसने कहा कि 32 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास कितना पैसा है? पीडी ने कहा कि 12 करोड़ मेरे पास है, लेकिन बाकी 20 करोड़ नहीं है. इस व्यक्ति ने पीडी को 20 करोड़ देने का वादा कर लिया. इस वादे को उसने अगले 4 दिनों में निभाया. उसने पीडी से ये भी कहा कि मैं आपको मुंबई में एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद के दूंगा, जिसका किराया आएगा 15–16 लाख रुपया महीना. शायद इस व्यक्ति ने ये प्रॉपर्टी भी खरीद के पीडी को दे दी और उसके बाद उसने जिस तरह से पीडी को मैसेजेज भेजने शुरू किए– मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा. इससे पीडी परेशान हो गई और उसने एसएन से कहा कि कृपा कर मेरा इनसे पिंड छुड़वाइए. वो पिंड अभी छूटा नहीं है.

जाट आपका साथ नहीं देगा...

दूसरी घटना, चुनाव की घोषणा हो गई, टिकटों के बंटवारे शुरू हुए, तो अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं की अपने जाट मंत्रियों सहित एक मीटिंग बुलाई. मीटिंग में उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि जाट नाराज हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने सौ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था. किसी भी तरह से जाटों को अपने साथ लाना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग–अलग जिलों के जितने जाट नेता आए थे, वे अपने यहां के चौधरी माने जाते हैं. उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि इस बार जाट आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने अजित सिंह को अपने साथ नहीं लिया. जाटों को लगता है कि अजित सिंह के राजनीतिक एकांतवास के पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और जाट पूरे तौर पर अजित सिंह के साथ हैं. अमित शाह ने कहा कि किसी भी तरह से जाटों को साथ रखिए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मंत्रियों सहित जाट नेता अमित शाह से यह साफ कह कर चल दिए कि इस बार वे जाटों को अपने साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ रखने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे.

ये दो घटनाएं दो तरह के संकेत देती हैं. एक तो, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने वादे से हटती है और कैसे अपना गठजोड़ बनाने में विफल रहती है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा समुदाय उससे दूर चला जाता है. इसका अगला संभावित कदम लोकसभा चुनाव में

(शेष पृष्ठ 2 पर)

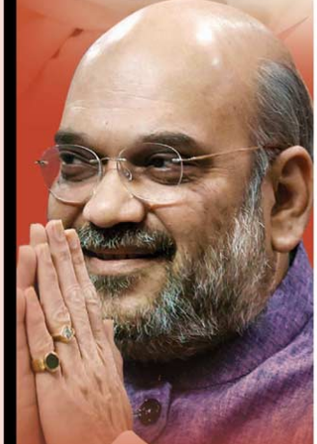

अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं की अपने जाट मंत्रियों सहित एक मीटिंग बुलाई. मीटिंग में उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि जाट नाराज हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने सौ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था. किसी भी तरह से जाटों को अपने साथ लाना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग–अलग जिलों के जितने जाट नेता आए थे, वे अपने यहां के चौधरी माने जाते हैं. उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि इस बार जाट आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने अजित सिंह को अपने साथ नहीं लिया.

झारखंड : टाटा का चांटा | P-3

महीना वैलेंटाइन का और चर्चा ब्रेकअप की | P-4

क्या कहता है इन नेताओं का टैरो कार्ड | P-6

तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें मारूं

पृष्ठ 1 का शेष

हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है. दूसरा यह कि उत्तर प्रदेश के अगले आठ संभावित मुख्यमंत्रियों में किस तरह के लोग हैं, जो अपनी मानवीय कमज़ोरियों को बिना किसी संकोच के पूरा करने के लिए अपनी स्थिति का फायदा उठाते हैं.

बसपा और मुस्लिम समाज

सबसे पहले हम बहुजन समाज पार्टी को लेते हैं. हमारे सर्वे में शुरू में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे दिखाई देती थी. लेकिन बहुजन समाज पार्टी से कई लोग, पार्टी छोड़कर चले गए और वो भी तब, जब चुनाव नजदीक आ गया था. उन्होंने लोगों के बीच कई अलग-अलग तर्क दिए. लेकिन जो पार्टी में हैं, उनमें एक सज्जन मंत्री भी रहे. उन्होंने अपने किसी दोस्त से कहा कि मैंने दो टिकट मांगे थे और उन दो टिकटों के लिए मुझे 10 करोड़ रुपए देने पड़े. उन्होंने अपने मित्र से कहा कि तब मुझे लगा कि मैं क्यों इस पार्टी में हूं. जिसके लिए मैंने सब कुछ किया और मुझे भी अपने और एक दूसरे टिकट के लिए पार्टी को 10 करोड़ देने पड़ रहे हैं. इस तरह की घटनाएं बहुत सारे लोगों के साथ घटीं और जो अच्छे उम्मीदवार थे, उनकी जगह उन लोगों को टिकट मिला, जो उम्मीदवार शायद दलित समुदाय के वोट के लिए बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं. पूरे चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने मुस्लिम समाज को अपने पास न तो बुलाया, न तो उनसे मंत्रणा की और न ही उनके सवालों को हल करने का कोई वादा किया. उल्टे मुस्लिम समाज या इस समाज के नेता बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में अपीलें करने लगें, क्योंकि उन्हें लगा कि अखिलेश यादव के अंतर्विरोध की वजह से कहीं भारतीय जनता पार्टी को बढ़त ना मिल जाय. अगर मुस्लिम समुदाय अखिलेश यादव और मायावती में बंट गया, तब भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित हो जाएगी. अखिलेश यादव ने सफलता पूर्वक उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच यह संदेश पहुंचा दिया कि अगर मायावती जी ये चुनाव जीतती हैं और कुछ सीटें कम रह जाती हैं, तो उनका गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगा. इस प्रचार का दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि मायावती जी को सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करनी पड़ी कि मैं भले सरकार ना बना पाऊं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार नहीं बनाऊंगी.

सपा-कांग्रेस गठबंधन की कमज़ोरी और ताक़त

दूसरी ताकत, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ी बनकर उभरी है, वो अखिलेश यादव हैं. अखिलेश यादव इस समय अति आत्मविश्वास से लबालब हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी की राजनीतिक दिशा एक झटके में मोड़ दी है. मुलायम सिंह यादव 30 साल तक कांग्रेस के विरोध की राजनीति करते रहे. हालांकि कांग्रेस सरकार को समर्थन भी देते रहे, सरकार भी चलवाते रहे. लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कभी कांग्रेस की प्रशंसा नहीं की. अखिलेश यादव ने एक झटके में कांग्रेस का साथ लिया और राहुल गांधी के साथ सीटों का समझौता कर लिया. इस समझौते के पीछे राहुल गांधी कम और प्रियंका गांधी ज्यादा थी. प्रियंका गांधी ने किसी भी तरह से अखिलेश यादव को समझाया और तैयार किया कि वो कांग्रेस के साथ समझौता करें.

प्रियंका गांधी के विश्वासपात्र प्रशांत किशोर का भी इसमें बड़ा रोल रहा.

अखिलेश यादव के साथ इस चुनाव में उत्तर प्रदेश का नौजवान दिखाई दे रहा है. समाजवादी पार्टी के चुने हुए एमएलए भी अखिलेश यादव के साथ हैं. लग रहा है कि अखिलेश यादव बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे. लेकिन अखिलेश यादव के साथ दो अंतर्विरोध हैं. अखिलेश यादव पिछले तीन सालों से समाजवादी पार्टी को नौजवानों की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने हर विधान सभा में एक नौजवान तैयार किया और उसे पिछले चार साल में उसे पैसे से मजबूत किया. उसे ठेके दिलवाए, ताकि वो किसी के प्रति आश्रित न रहे. उस व्यक्ति ने अपने चुनाव क्षेत्र में जम कर काम किया. लेकिन जैसी गतिविधिया हुईं, जिस तरह की घटनाएं घटीं और चुनाव आयोग में विधायकों के शपथपत्र की आवश्यकता पड़ी, तो अखिलेश यादव ने मौजूदा सभी विधायकों से वादा किया या उन्हें ये वादा करना पड़ा कि वे उन्हें टिकट देंगे. अखिलेश यादव ने ज्यादातर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया. इसका परिणाम ये हुआ कि वो सारे लोग टिकट से वंचित रह गए, जो पिछले 3-4 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहे थे और जिन्हें अखिलेश यादव ने ही मजबूत बनाया था. उनमें से अधिकांश समाजवादी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं. दूसरी तरफ, जब अखिलेश यादव अपने पिता से सत्ता छीन रहे थे, तब मुलायम सिंह यादव ने दो बयान दिए. पहला बयान कि अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी हैं और दूसरा ये कि मैं इस गठबंधन को सही नहीं मानता और मेरे समर्थक कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ें. इस घोषणा के बाद बहुत सारे लोग, लगभग 50 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए. हालांकि, मुलायम सिंह यादव ने ये वादा किया था कि वे उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे. लेकिन मुलायम सिंह यादव किसी के लिए भी चुनाव प्रचार में अभी नहीं गए हैं. ये दो स्थितियां अखिलेश यादव के लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं. एक तीसरी अंतर्धारा है कि शिवपाल यादव को जिस तरह से मात मिली, उससे शिवपाल यादव के बहुत सारे समर्थक चुनाव से दूर खड़े हैं. हालांकि सिर्फ शिवपाल यादव के समर्थक ही दूर नहीं खड़े हैं, मुलायम सिंह के 40 साल के राजनीतिक साथी और उनकी प्रशंसा करने वाले लोग भी चुनाव से दूर खड़े हैं. ये तीन चीजें अखिलेश यादव के पूर्ण रूप से सत्ता प्राप्त करने में आड़े आ सकती हैं.

कांग्रेस पार्टी का गठजोड़ समाजवादी पार्टी से हुआ और इसमें प्रियंका गांधी का बहुत बड रोल रहा. सीटें भी लगभग बंट गईं और कांग्रेस सिर्फ 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. लेकिन इस समझौते में इतनी देर हो गई कि उत्तर प्रदेश की किसी भी रैली में कांग्रेस के लोग शामिल नहीं हुए (उन रैलियों को छोड़ कर जिनमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ बोलने वाले थे). दूसरा तथ्य, कांग्रेस के समर्थक वोट समाजवादी पार्टी को नहीं पड़े, बल्कि जहां कांग्रेस नहीं लड़ रही है, वहां कांग्रेस का वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया. तीसरी चीज, मुसलमानों में बंटवारा हुआ और मुसलमानों की बड़ी संख्या बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों में अखिलेश और राहुल गांधी के गठबंधन के साथ गई. कांग्रेस की परेशानी ये है कि बहुत सारी जगहों पर उम्मीदवार ही नहीं मिले, तो उसे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव में उतारना पड़ा, क्योंकि उसे अपने 105 लोगों की संख्या पूरी करनी थी.

लखनऊ के ताज होटल में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पहली प्रेस कांफ्रेंस में लोगों ने ध्यान नहीं दिया. वहां पर राहुल गांधी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बेताब थे. अखिलेश यादव ने अपना संबोधन राहुल जी बोल कर किया और राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि अखिलेश एक अच्छा लड़का है. अखिलेश ने उनकी तरफ अचंभे से देखा और इस वाक्य के बाद उन्होंने राहुल जी की जगह राहुल कहना शुरू किया. ये बताता है कि दोनों के कार्यकर्ता एक हो कर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. इसलिए कांग्रेस की सीटें 35 से 45 के बीच रहने की उम्मीद है. जबकि प्रशांत किशोर का कहना है और उन्होंने प्रियंका गांधी को इस बात पर प्रजेंटेशन भी दिया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 76 सीटें जीत रही है. लेकिन, प्रियंका गांधी ने सिर्फ गांधी परिवार के पारंपरिक सीट रायबरेली क्षेत्र में ही प्रचार करने का फैसला किया. जबकि, वे खबर आ रही थी कि वह पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन करेंगी. प्रियंका शायद इस पशोपेश में पड़ी रहीं कि अगर वो कैंपेन करती हैं और कांग्रेस को सीटें नहीं आती हैं, तो उनके अपने राजनीतिक भविष्य को ले कर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा. इस पशोपेश से राहुल गांधी का कोई लेना-देना नहीं है. राहुल गांधी इस चुनाव में साधु-संत वाली भाषा में उन सवालों पर ज्यादा बात करते दिखाई दिए, जिनका चुनाव से कोई मतलब नहीं है.

भाजपा की दुविधा

भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा तय नहीं कर पाई है, जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके. लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सभा में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का भाषण दिया और उन्हें वहां जैसी प्रतिक्रिया मिली, उससे दिल्ली में बैठे पार्टी अध्यक्ष को ये निर्णय लेना पड़ा कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर घुमाया जाए. योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया. उनके दिल्ली पहुंचने से पहले ये फैसला हो गया था कि उन्हें स्थायी रूप से प्रचार के लिए एक हेलिकॉप्टर दिया जाए, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाएं. जब वे दिल्ली आए, तो उनसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, खास कर पार्टी अध्यक्ष ने कह दिया कि हम घोषणा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जीतते हैं, तो आप हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे. योगी आदित्यनाथ दिन-रात भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं. योगी द्वारा उठाए गए सवाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ये आशा दे गए कि चुनाव में ध्रुवीकरण हो जाएगा और मुसलमानों के खिलाफ सारे हिंदू भाजपा को वोट देंगे. हालांकि अब तक ये ध्रुवीकरण नहीं हो पाया है. सारी कोशिशों के बाद भी, शुरू के तीन-चार फेज तक जनता ने ध्रुवीकृत होने से मना कर दिया है. अब आखिरी चरण के लिए कुछ ताकतें ध्रुवीकरण की कोशिशें कर रही है.

भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और बड़ा कैंपेनर नहीं है. उन्हीं की सभाओं में भारी भीड़ हो रही है. वे जैसे भाषण दे रहे हैं, उससे ये माना जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को स्पष्ट विजय मिलने वाली है. लेकिन यहां पर सन 1957 के चुनाव को याद रखना चाहिए, जब भारतीय जनसंघ की सभाएं हो रही थीं और अटल विहारी वाजपेयी की सभाओं में लाखों लोग आते थे. बाद में अटल जी ने एक बातचीत के दौरान, जिसमें मैं शामिल था, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी से कहा कि हम ये सोच रहे थे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरी सभाओं में जितनी भीड़ हो रही थी, उतने ही हमारे वोट कम हो रहे थे. ये बात मैं इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ग्रामीण क्षेत्र के लोग नाराज हैं. खास कर किसान, जिन्हें इस नोटबंदी से काफी परेशानियां झेलनी पड़ी. व्यापारी वर्ग हमेशा भाजपा का समर्थक रहा है, लेकिन आज उसका एक बड़ा तबका भाजपा से नाराज है. नोटबंदी से उनका खुदरा व्यापार बहुत ज्यादा दबाव में आ गया और उन्हें उनलोगों को अपने यहां से हटाना पड़ा, जिन्हें वे नगद पैसा दे कर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काम में लाते थे. व्यापार पर जिस तरह की सख्ती प्रधानमंत्री मोदी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, वो व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा है. व्यापारियों की नाराजगी का दूसरा कारण यह भी है. उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व पिछड़ों को दे दिया गया है. इससे उनका परंपरागत ब्राह्मण समाज सौ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है. भारतीय जनता पार्टी को अजित सिंह के साथ गठबंधन न करने का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है. भारतीय जनता पार्टी को कुछ मुस्लिम वोट भी मिलते, लेकिन भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव में नहीं उतारा. इसलिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भले ही देखने में बहुत मजबूत लगे, पर ये परेशानियां चुनाव में उसके सामने आ रही हैं और लोगों को उसके पक्ष में वोट देने से रोक रही है.

सरकार किसकी बनेगी..

अगर यही स्थिति रहती है, तो इसमें शंका है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को बहुमत मिले और अगर ऐसा होता है, यानी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट यानी हंग विधान सभा उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी. तब सरकार किसकी बनेगी? इसका सीधा जवाब है कि तब भारतीय जनता पार्टी और मायावती जी की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी. अखिलेश यादव के बारे में एक आम धारणा है कि उन्होंने संघर्ष नहीं देखा है, समाजवाद नाम उनका रटा हुआ है, लेकिन समाजवादी मूल्यों में उनकी आस्था कम है. उन्होंने जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, सरकार बनाने के लिए वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं. अगर मायावती की संख्या कम हुई, तो राहुल गांधी अखिलेश यादव का साथ छोड़ कर मायावती से भी हाथ मिला सकते हैं और उनकी सरकार बनवा सकते हैं. राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस में ये संदेश या इशारा दिया भी कि वे मायावती को बहुत हानिकारक नहीं मानते हैं. अगर चुनाव के बाद ऐसी कोई स्थिति आती है, तो मायावती साथ समझौता करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी.

भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अगर चुनाव नहीं जीतते हैं, जिनमें संगीत सोम भी शामिल हैं, तो उत्तर प्रदेश का फैसला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया माना जाएगा. ऐसी स्थिति में भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह के भविष्य पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ने लिए हैं. अमित शाह की कोशिश राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश में पार्टी का चेहरा बनाने की थी, लेकिन राजनाथ सिंह बहुत सफाई से उनके हाथ से निकल गए.

उत्तर प्रदेश का चुनाव देश के आने वाले चुनावों पर भी असर डालेगा, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश शामिल हैं. 2019 के ऊपर तो निश्चित तौर पर इसका असर होगा. यह चुनाव उन रेखाओं को साफ तौर पर सामने लाएगा, जिसके आस-पास अखिलेश यादव-राहुल गांधी अपनी रणनीति तय करेंगे.

प्रियंका गांधी और नीतीश कुमार, ये दो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं. प्रियंका गांधी कांग्रेस की पूरी रणनीति बनाने में, मुद्दे तय करने में, मदद पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही हैं. दूसरी तरफ, नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ताकि सेकुलर वोटों का बंटवारा न हो. हालांकि अगर वे 50-60 सीटों पर चुनाव लड़ते, तो भी उनके पास भी 6-8 सीटें होतीं. लेकिन उन्होंने वैसा ही साहसिक फैसला लिया, जैसा फैसला उन्होंने कांग्रेस को बिहार में 40 सीटें दे कर लिया था.

अखिलेश यादव की एक बात सही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का भविष्य तय करेगा. ये बात लगभग सभी लोग दबी जुबान से कर रहे हैं. मैं ये तो नहीं कहता कि यह चुनाव देश का भविष्य तय करेगा, लेकिन देश के भविष्य की दिशा तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी को अपनी बहुत सारी नीतियों पर फिर से सोचने पर विवश करेगा. भारतीय जनता पार्टी अगर ये चुनाव जीत जाती है, तो फिर समाजवादी पार्टी हो या देश की दूसरी पार्टियां, उन्हें 2019 के लिए एक दबाव के तहत एक साथ आने पर विवश होना पड़ेगा. उस समय अगर राहुल गांधी परिस्थितियों के ऊपर सारा बोझ डाल देंगे, तब वे विपक्ष के एकमात्र नेता नहीं कहलाएंगे, उनके सामने कई सारे और नेता खड़े हो जाएंगे, जिस स्थिति का फायदा सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होगा. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 52
27 फरवरी- 05 मार्च 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

झारखंड सरकार को 'टाटा' से साढ़े चार हज़ार करोड़ का नुक़सान

टाटा का चांटा

प्रशान्त शरण

'राम नाम जपना, पराया माल अपना' यह उक्ति टाटा घराने पर बिल्कुल सटीक बैठती है. टाटा ने जमशेदपुर में कारखाना स्थापित करने के लिए चालीस वर्षों की लीज पर 1956 में बिहार सरकार से कौड़ियों के भाव पर जमीन ली. लीज देने में सरकार की ओर से कई शर्तें रखी गई, जिसे टाटा कंपनी ने स्वीकार करते हुए लीज पर जमीन ली. लेकिन टाटा कंपनी ने लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अन्य व्यवसायिक घरानों को सबलीज पर वह जमीन देकर अरबों रुपयों की कमाई की. नियंत्रक एवं महालेखाकार ने अपने ऑडिट में टाटा का यह कारनामा पकड़ा और बताया कि लीज की जमीन को ऊंचे दामों पर सबलीज कर टाटा ने केवल राजस्व के रूप में सरकार को 4,700 करोड़ रुपये की चपत लगाई और व्यवसायिक एवं अन्य लोगों से जमीन के एवज में हजारों करोड़ रुपए कमाए. इतना ही नहीं, टाटा ने अपने कोल ब्लॉक वेस्ट बोकारो कोलियरी में कम उत्पादन, अवैध उत्खनन एवं खराब क्वालिटी दिखाकर सरकार को लगभग चार सौ करोड़ रुपए का चूना लगाया है. ऐसा भी नहीं है कि टाटा के इस कारनामे के बारे में कोई अधिकारी या मंत्री नहीं जानता है. शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को छोड़ दें, तो झारखंड गठन के बाद से अब तक राज्य का मुख्यमंत्री बनने वाले सभी कोल्हान क्षेत्र से ही संबंधित थे. जाहिर है, सभी मुख्यमंत्रियों को पूरी तौर से इस चोरी की जानकारी थी, लेकिन सबने चुप्पी साधे रखी और इसी का फायदा यह कंपनी उठाती रही.

इन सब के बावजूद कौशल विकास से जुड़ी योजनाएं और अन्य बड़ी सरकारी योजना इस कंपनी को दी जा रही है और इससे कंपनी मंदी के दौर में भी मालामाल होती जा रही है. वैसे कंपनी का कोई भी अधिकारी इस पर बातचीत करने से कतरा रहा है. इधर राज्य के भू-राजस्व एवं निबंधन मंत्री अमर बाउरी का कहना है कि कंपनी ने अगर महालेखाकार के ऑडिट रिपोर्ट शर्तों का उल्लंघन किया है, तो इस मामले की जांच कराई जाएगी. जीरो टॉलरेन्स एवं जीरो करप्शन की बात करने वाले मुख्यमंत्री इस मामले में चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं. रघुवर दास जमशेदपुर से विधायक हैं और राजनीति में आने से पहले इस कंपनी में काम कर चुके हैं. जाहिर है, टाटा समूह उनके राजनीति में आने का फायदा उठा रहा है. रघुवर मंत्रिमंडल के संसदीय कार्य मंत्री एवं जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कहा कि सीएजी ने रिपोर्ट में जो बाते कही है, मामला उससे भी ज्यादा बड़ा है. उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपनी लीज की जमीन को सबलीज में दूसरी कंपनियों को दे दिया, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है. इस मामले को मैंने विधानसभा में भी उठाया था, जिसके बाद एक समिति भी बनी थी, लेकिन सदन स्थगित हो जाने के कारण कुछ नहीं हो सका. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी हुई है. जमशेदपुर के तत्कालीन उपायुक्त अमिताभ कौशल ने राज्य सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन इसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

झारखंड के अलग होने से पहले संयुक्त बिहार के कोल्हान में कारखाना स्थापित करने के लिए टाटा समूह ने राज्य सरकार से जमीन मुहैया कराने का अनुरोध किया. बिहार सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 1956 में टाटा को 12,708 एकड़ जमीन लीज पर दे दी. जमीन लीज एग्रीमेन्ट में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि कंपनी जिस जमीन का उपयोग नहीं करेगी, उसे राज्य सरकार को वापस कर देगी, लेकिन किसी अन्य को सबलीज पर नहीं दे सकती. लीज की अवधि खत्म होने के बाद जब टाटा ने लीज के नवीनीकरण के लिए बिहार सरकार से अनुरोध किया, तो राज्य सरकार ने उसे प्रति एकड़ की दर से राजस्व जमा करने का निर्देश दिया, जिसकी राशि हजारो करोड़ रुपये थी. बिहार सरकार के डिमांड के बाद टाटा ने लीज नवीनीकरण के मामलों में चुप्पी साध ली. झारखंड गठन के बाद टाटा ने पुनः लीज नवीनीकरण के लिए झारखंड सरकार से अनुरोध किया. राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी ने भी लीज की राशि जमा करने को कहा. इसके बाद अर्जुन मुण्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए टाटा ने 12,708 एकड़ की जगह 10,852 एकड़ जमीन के लीज नवीनीकरण के लिए अनुरोध किया. 2005 में अर्जुन मुण्डा ने लीज नवीनीकरण हेतु आदेश दिया. राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी. राज्य सरकार ने कहा कि टाटा कंपनी प्रतिवर्ष बीपीएल परिवारों के स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपये, नेशनल गेम्स के लिए 150 करोड़ रुपये का सहयोग करेगी. इस शर्त के अनुसार टाटा को 450 करोड़ रुपये राज्य सरकार के पास जमा करने थे, लेकिन उसने अभी तक ये राशि नहीं जमा किया है.

लीज पर ली गई जमीन में से लगभग ढाई हजार एकड़ से भी अधिक जमीन टाटा ने अन्य व्यवसायिक घरानों को सबलीज पर दे दी. इससे एक तरफ टाटा ने अरबों रुपया कमाया, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार को साढ़े चार हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया. सबलीज पर दिए गए जमीन पर धड़ल्ले से व्यवसायिक भवन, अपार्टमेन्ट, शिक्षण संस्थान एवं कारखाने खड़े हो गए. इन जमीनों एवं इन पर खड़े हुए फ्लैटों की रजिस्ट्री भी हुई.

सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में टाटा लीज और खास महल जमीन की अनियमितता को अत्यंत गंभीर बताते हुए राज्य सरकार को राशि वसूलने को कहा है. सीएजी ने कहा है कि 69 एकड़ जमीन का अता-पता नहीं है, जबकि टाटा स्टील ने पूरी जमीन से 1856 एकड़ कम कर लीज नवीनीकरण का अनुरोध किया. इस तरह टाटा ने दो हजार एकड़ जमीन दूसरे को बेच दी. इसके साथ ही टाटा स्टील ने अपने कोल ब्लॉक में घोटाला किया जिसके कारण राज्य सरकार को 446 करोड़ का नुकसान हुआ. टाटा ने वेस्ट बोकारो कोलियरी से अस्वीकृत कोयले की बिक्री की और अधिक मूल्य पर बेचे गए कोयले का रेट कम दिखाकर सरकार को चूना लगाने का काम किया. सीएजी की रिपोर्ट आते ही राज्य सरकार ने वेस्ट बोकारो कोलियरी को 440 करोड़ का डिमांड भेजकर इसे अविलंब जमा करने का निर्देश दिया है. अगर कंपनी अपने सेल का विस्तृत ब्यौरा एवं टैक्स जमा नहीं करती है, तो कंपनी पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.

इससे पूर्व टाटा लीज मामले में राष्ट्रपति शासन के दौरान घोटाले की जांच हेतु राजस्व पर्षद के सदस्य देवाशीष गुप्ता के नेतृत्व में एक जांच कमिटी का गठन किया गया था. इस कमिटि ने अपनी रिपोर्ट में सबलीज को अवैध करार दिया था एवं जिन्हें भूमि सब लीज पर दी गयी थी, उनके भी नाम बताए थे. 2010 में तत्कालीन सचिव ने इस मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई करते हुए निगरानी या अन्य जांच एजेंसी से इस मामले की जांच कराने की अनुशंसा की थी, लेकिन सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई.

अब यह सवाल उठ रहा है कि इस मामले में किसी भी सरकार ने टाटा के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की. कार्रवाई करने के बदले सरकार द्वारा इस आद्यौगिक समूह को उपकृत करने का ही काम किया गया. सीएजी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार क्या कार्रवाई करती है, अब यह देखना है. ■

feedback@chauthiduniya.com

टाटा सबलीज की सीबीआई जांच हो: बाबूलाल

भाजपा सरकार उद्योगपतियों की सरकार है एवं टाटा समूह के इशारे पर तो मुख्यमंत्री एवं अधिकारी नाचते हैं और यही कारण है कि टाटा समूह राज्य में अपनी मनमर्जी से काम करती है, उसे सरकार से कोई डर नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने टाटा सबलीज घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर इस मामले को राज्य सरकार सीबीआई को नहीं सौंपती है, तो वे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ राज्यपाल से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाय. मरांडी का कहना है कि कैग की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार और भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग ने भी सबलीज में हुई अनियमितताओं को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही टाटा समूह की ओर से लीज शर्तों का उल्लंघन किया जाता रहा है. यही कारण है कि बिहार सरकार ने लीज नवीनीकरण से साफ इंकार कर दिया था. झारखंड गठन के बाद मेरे मुख्यमंत्री बनने पर भी टाटा कंपनी के प्रतिनिधि आए. उस दौरान लीज नवीनीकरण के लिए हजारो-करोड़ रुपए का आकलन किया गया था, पर इस दौरान मेरी सरकार गिर गई. 4 फरवरी, 2005 को अर्जुन मुण्डा के शासनकाल में लीज नवीनीकरण हुआ. उस दौरान भी लीज नवीनीकरण के लिए अनेक शर्तें रखी गई, लेकिन टाटा ने इसे पूरा नहीं किया. राष्ट्रपति शासनकाल के दौरान तत्कालीन राजस्व पर्षद के सदस्य देवाशीष गुप्ता ने भी इस सबलीज को अवैध करार दिया था, लेकिन उस रिपोर्ट पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना दुःखद है. ■

टाटा सबलीज घोटाले की जांच करेगी लोक लेखा समिति

टाटा सबलीज घोटाले की जांच विधानसभा की लोक लेखा समिति करेगी. लोक लेखा समिति के सदस्य कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि झारखंड को चारागाह बनाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि लोक लेखा समिति इस मामले में ऐतिहासिक निर्णय लेगी. टाटा स्टील हो या अन्य इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कमेटी सबको बेनकाब करेगी और मामले को अंजाम तक पहुंचाएगी. जल्द ही पूरे मामले को टेकओवर किया जाएगा. टाटा ने सबलीज कर राज्य सरकार को 4700 करोड़ रुपये का चूना लगाया है. विधानसभा की लोक लेखा समिति की ओर से राज्य सरकार के अलावा सभी संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया जाएगा. इस संबंध में जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी. स्टीफन मरांडी इस समिति के अध्यक्ष हैं. पूर्व में राजस्व पर्षद के सदस्य रहे देवाशीष गुप्ता, कोल्हान प्रमण्डल के तत्कालीन आयुक्त अरुण एवं जमशेदपुर के तत्कालीन उपायुक्त अमिताभ कौशल की रिपोर्ट का संज्ञान भी इस समिति द्वारा लिया जाएगा. इन तीनों ने टाटा द्वारा किए गए सबलीज को अवैध करार देते हुए इन जमीनों को नीलाम कर राशि जमा कराने की अनुशंसा की थी, पर सभी रिपोर्टों को ठंढे बस्ते में डाल दिया गया. ■

सीएजी का सवाल

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह खुलासा किया कि टाटा समूह ने लीज शर्तों का खुलेआम उल्लंघन कर राज्य सरकार को 4,700 करोड़ रुपये की चपत लगाई. टाटा कंपनी की ही वेस्ट बोकारो कोलियरी ने भी राज्य सरकार को चूना लगाया है. महालेखाकार ने दामोदर वैली निगम को भी दोषी पाते हुए कहा कि डीवीसी ने भी लीज शर्तों का उल्लंघन कर 30 करोड़ का चपत लगाया है. सीएजी ने पाया कि पट्टाकृत भूमि के अनियमित हस्तान्तरण के कारण राज्य सरकार को 974-78 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है.

महालेखाकार सी नेदुनपिजेयिम के अनुसार टाटा स्टील ने अपने लीज वाले जमीन पर एक सीमेन्ट प्लान्ट लगाया था. नवम्बर 1999 में प्लान्ट क्षेत्र की 122-82 एकड़ भूमि का पट्टा लाफार्ज इंडिया को हस्तांतरित दर दिया. वहीं 469.38 एकड़ भूमि को 1279 व्यक्तियों या कंपनियों को दे दिया. इस भूमि पर व्यवसायिक भवन एवं अपार्टमेन्ट बना दिया गया. इससे राज्य सरकार को सीधे तौर पर 3,376 करोड़ के राजस्व की क्षति हुई. महालेखाकार का मानना है कि इन सभी बातों की जानकारी जमशेदपुर के उप-समाहर्ता एवं राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास थी, पर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. इससे स्पष्ट है कि इसमें राज्य सरकार एवं अधिकारियों की भी मिली-भगत थी. महालेखाकार का यह भी कहना है कि वेस्ट बोकारो कोलियरी ने कोयला उत्पादन को कम और खराब क्वालिटी का दिखाकर राज्य सरकार को लगभग चार सौ करोड़ रुपए के राजस्व का चपत लगाया, जबकि इसका कोयला उच्च क्वालिटी का था और इसका पूरा उपयोग टाटा स्टील ने किया. ■

महीना वैलेंटाइन का और चर्चा ब्रेकअप की

सरोज सिंह

बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों एक नए समीकरण वाली सरकार की चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है. ऐसे तो, जब नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने उसी दिन से यह बात चर्चा में आ गई कि यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और जल्द ही बिहार में एक नए समीकरण वाली सरकार बन जाएगी. लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो महागठबंधन की सरकार ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए मजबूती से अपना पहला साल पूरा किया. गठबंधन सरकार ने यह संदेश भी दिया कि महागठबंधन बेमेल नहीं है, बल्कि यह काफी आगे तक जाने वाला सत्ता समीकरण है. लेकिन इधर हाल की कुछ राजनीतिक घटनाओं ने वैकल्पिक सरकार की चर्चाओं को एक बार फिर हवा दे दी है. चर्चाओं के बाजार से जो एक और बात सामने आ रही है, वो यह कि पांच राज्यों के चुनाव परिणामों से बिहार की राजनीति बहुत प्रभावित होगी. अगर ये परिणाम भाजपा के खिलाफ गए, तो यहां दो तरह की संभावनाएं जन्म लेंगी. पहला, जिसे ज्यादा लोग मानते हैं कि मौजूदा महागठबंधन की सरकार और मजबूती से चलेगी, जबकि दूसरी चर्चा यह है कि चूंकि इन चुनावों से नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया है, इसलिए लालू प्रसाद अपनी तमाम राजनीतिक ताकत और अनुभवों का उपयोग करते हुए राजद के नेतृत्व में बिहार में एक वैकल्पिक सरकार देने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर चुनावी फैसले मोटे तौर पर भाजपा के पाले में चले गए, खासकर अगर भाजपा यूपी में सरकार बनाने में सफल हो गई, तो बिहार एक बार फिर से एक नए राजनीतिक प्रयोग का गवाह बन सकता है. चर्चाओं पर गौर करें, तो कहा जा सकता है कि राज्य में एक बार फिर भाजपा व जदयू गठबंधन वाली सरकार बन सकती है.

राजनीतिक चर्चाओं में जिन विकल्पों पर बात हो रही है, उन्हें सूबे में चल रही राजनीतिक गतिविधियों से जोड़कर इसकी गंभीरता का आंकलन करना ठीक रहेगा, ताकि पता चल सके कि इन चर्चाओं में दम है भी या नहीं. बात लालू यादव से ही शुरू करते हैं. वैसे तो लालू यादव अपने दोनों बेटे तेजप्रताप और तेजस्वी की राजनीतिक हैसियत बढ़ाने में सक्रिय हैं, लेकिन तेजस्वी से इन्हें कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं. यूपी में अखिलेश यादव का कद और रूतबा जिस तरह बढ़ा है, उसे देखकर लालू यादव प्रभावित हैं. यह बात अब किसी से छिपी भी नहीं है कि लालू यादव की दिली इच्छा है कि तेजस्वी को बिहार में नंबर एक की कुर्सी पर बैठा दिया जाए. यह कैसे संभव हो इसके लिए लालू यादव पहले दिन से ही माहौल बनाने और सही मौके के इंतजार में जुटे हुए हैं. सार्वजनिक तौर पर भले ही वह कई बार नीतीश कुमार को दही का टीका लगा चुके हैं, पर अंदरखाने यह कोशिश है कि तेजस्वी को नंबर एक बना दिया जाए. लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस को लेकर आ रही थी. राहुल गांधी से लालू के रिश्ते कितने कड़वाहट भरे हो गए थे इसे सभी जानते हैं, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू यादव ने हाल के दिनों में कई मुद्दों पर सोनिया गांधी का जमकर पक्ष

लिया. इससे राजनीतिक हवा काफी बदली है. इधर यूपी में कांग्रेस और सपा के गठबंधन को अमलीजामा पहनाने में भी लालू यादव सक्रिय रहे. सपा में जब पारिवारिक कलह चरम पर था, तब ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा था जब वह अखिलेश और मुलायम सिंह से बात नहीं कर रहे थे. लालू यादव का आंकलन है कि यूपी में सपा और कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए. अगर वाकई में ऐसा हुआ, तो लालू यादव बिहार के सियासी शतरंज में अपनी बिसात बिछाना शुरू कर देंगे. चर्चाओं पर भरोसा करें तो लालू यादव ने अपने दूतों के जरिए कुछ छोटी पार्टियों और दूसरे दलों के अपने समर्थक विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है. मौजूदा विधानसभा का अंकगणित भी लालू प्रसाद का हौसला बढ़ा रहा है. मौजूदा विधानसभा में राजद के 80, कांग्रेस के 27 और निर्दलीय चार विधायक हैं. लालू यादव जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके अनुसार राजद, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर उनके पास 111 विधायक हैं. बहुमत के लिए 12 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जिसे लालू यादव दो रास्तों से पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं. लालू यादव का अनुमान है कि यूपी में चुनाव हारने के बाद भाजपा के सहयोगी दलों का मोह नरेंद्र मोदी के प्रति कम हो जाएगा. ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और रामविलास पासवान का झुकाव भी नई सरकार के गठन में हो सकता है.

अब यह बात भी छुपी हुई नहीं हैं कि चाहे वह रामविलास पासवान हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों मंत्रियों को दिल्ली में बहुत आजादी नहीं दी गई है. उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा में लोजपा के दो, रालोसपा के दो और हम के एक विधायक हैं. माले के तीन विधायकों को नई सरकार को बाहर से समर्थन देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सहयोगी दलों ने अगर अभी हां नहीं कहा है, तो न भी नहीं कहा है. सभी यूपी के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. जोड़तोड़ के माहिर खिलाड़ी लालू यादव ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है. सभी दलों में लालू यादव के कई समर्थक विधायक हैं. अगर भाजपा के सहयोगी दल नहीं माने, तो लालू यादव दूसरे दलों के अपने 15 समर्थक विधायकों का इस्तीफा भी उन्हें नई सरकार में मंत्री बनाने की शर्त पर करा सकते हैं. यह बिहार के लिए कोई नई घटना भी नहीं होगी.

हालांकि, जब सत्ता परिवर्तन की बिसात बिछती है, तो दूसरी तरफ का खिलाड़ी भी अपनी चाल चलता है. लालू यादव की राजनीति के रग-रग से वाकिफ नीतीश कुमार भी चुप नहीं बैठे हैं. हाल के दिनों में नीतीश कुमार के कुछ फैसलों और बयानों ने साफ संकेत दिया है कि आज की तारीख में भाजपा के प्रति इनके दिल में बेहद कटुता नहीं है. नरेंद्र मोदी के प्रति नीतीश कुमार की आक्रामकता भी पहले से कम हुई है. तमाम कयासों को झुठलाते हुए नीतीश कुमार ने नोटबंदी में नरेंद्र मोदी का साथ दिया. यूपी में अपने चुनाव अभियान को विराम देकर भी नीतीश कुमार ने यह आभास कराया कि इनका दिल बदल रहा है. बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि बिहार में एक बार फिर भाजपा और जदयू का गठबंधन हो सकता है. बस सही वक्त का इंतजार हो रहा है. गौरतलब है कि मौजूदा विधानसभा में जदयू के 71 और भाजपा के 53 विधायक हैं. इसमें अगर निर्दलीय और सहयोगी दलों के विधायकों को भी साथ कर लिया जाए, तो नीतीश कुमार के पास 133 विधायक हो जाएंगे, जो बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा होगा. जानकार बताते हैं कि भाजपा के प्रति नीतीश कुमार की नरमी यूं ही नहीं है. इससे नीतीश कुमार एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं. पहला शिकार तो लालू यादव ही हैं. नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि केवल भाजपा का भूत ही लालू यादव की राजनीतिक और प्रशासनिक महत्वाकांक्षाओं को काबू में रख सकता है.

अभी हाल में ही राजद के दो मजबूत नेता बूलो मंडल और सुरेंद्र यादव ने यह ऐलान कर सनसनी फैला दी कि राजद के लाखों लाख कार्यकर्ता और बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है. इस तरह की बयानबाजी राजद की ओर से अक्सर होती रहती है. रघुवंश सिंह जैसे वरिष्ठ राजद नेता भी बार-बार नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहते हैं. नीतीश कुमार इन बयानों पर भले ही सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनका होमवर्क जारी रहता है.

जहां तक भाजपा का सवाल है, तो पार्टी के ज्यादातर नेता चाहते हैं कि सूबे में एक बार फिर जदयू के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई जाए. इसकी सबसे बड़ी वजह 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को बताई जा रही है. जानकारों की राय है कि अगर मौजूदा महागठबंधन बना रहा, तो फिर एनडीए के लिए 2019 में 10 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो जाएगा. फिलहाल नरेंद्र मोदी का जादू उतार पर है और दूसरी तरफ महागठबंधन का सामाजिक समीकरण रोज मजबूत हो रहा है. अगर समय रहते भाजपा ने महागठबंधन में सेंध नहीं लगाया, तो आने वाला वक्त भाजपा के लिए मुश्किल भरा हो सकता है. नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व में जिस तरह से नीतीश कुमार को

तवज्जो दिया, इससे भी साफ है कि दोनों नेताओं के रिश्ते बहुत तेजी से सुधर रहे हैं. एक अन्य घटनाक्रम में नीतीश कुमार ने अपने विश्वासी संजय झा को दिल्ली में पार्टी के कार्य का जिम्मा दे दिया है. संजय झा इन दिनों अपना ज्यादा वक्त दिल्ली में ही बिता रहे हैं. भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ संजय झा की नजदीकियां सभी जानते हैं.

इधर कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी के नाम का सार्वजनिक तौर पर समर्थन करें. लेकिन जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, उन्हें पता है कि दबाव में कोई फैसला लेना नीतीश कुमार की फितरत नहीं है. नीतीश कुमार के रुख को लेकर कांग्रेस बेचैन है. 2019 का समर नजदीक आ रहा है. ऐसे में अगर राहुल गांधी को लेकर बिहार में कोई भ्रम की स्थिति बनती है, तो इसके नुकसान का अंदाजा लगाना सहज है. इसलिए बिहार के सभी सियासी दलों को 11 मार्च को आने वाले चुनाव नतीजों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है. अब कोई भी सियासी खिलाड़ी सत्ता परिवर्तन की बिसात पर अपनी चाल 11 मार्च के बाद ही चलेगा. हालांकि इस बीच सियासी गलियारों में सत्ता परिवर्तन के बादल और घने होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

क्या भाजपा ने कश्मीर में अपना एजेंडा फिलहाल रोक दिया है?

हारून रेशी

एक ऐसे वक्त में जब घाटी में फिर से हालात ख़राब होने की अफवाहें गश्त कर रही हैं, नई दिल्ली की एक घोषणा से राज्य सरकार को राहत मिली है. केंद्र की तरफ से कहा गया है कि अभी न तो कश्मीरी पंडितों के लिए पृथक कॉलोनियां बसाने की कोई योजना विचाराधीन है और न ही जम्मू क्षेत्र में रह रहे पश्चिमी पाकिस्तान के हिन्दू शरणार्थियों को पहचान-पत्र दिए जाने की कोई योजना है. कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में अलग से बस्तियां बसाने, पूर्व सैनिकों के लिए कॉलोनियों का निर्माण करने और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को यहां की स्थाई नागरिकता देने की कथित योजनाएं पिछले कई वर्षों से कश्मीरी जनता के लिए बेचैनी का कारण बनी हुई है. अलगाववादी कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि कश्मीर में विभिन्न योजनाओं के बहाने नई दिल्ली यहां की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही है. उनका आरोप है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों और पूर्व सैनिकों के नाम पर अलग बस्तियां और कॉलोनियां स्थापित करके उनमें दूसरे राज्यों के बाशिंदों को बसाने की योजना बनाई जा रही है. उनका ये भी आरोप है कि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता देने की कोशिश की जा रही हैं, ताकि इस मुस्लिम बहुल राज्य में आबादी का अनुपात बदला जा सके. विश्लेषकों का मानना है कि जुलाई 2016 में घाटी में जो हिंसक लहर फैली थी, उसके पीछे की वास्तविकता भी जनता की असहजता ही थी. कई महीनों तक चली इस हिंसा में कश्मीरी लोगों के जान व माल की काफी क्षति हुई थी. वरिष्ठ पत्रकार और रोज़नामा चट्टान के संपादक ताहिर मुहीउद्दीन कहते हैं कि बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पूरी घाटी में जो लहर चली, उसका एक कारण कश्मीरियों का यह संदेह भी था कि नई दिल्ली यहां की डेमोग्राफी को बदलने की योजना बना रही है. लोगों को लगा कि भाजपा

राज्य में अपने कट्टरपंथी एजेंडे को लागू कर रही है. इसी संदेह की वजह से यहां की जनता में सरकार और नई दिल्ली के खिलाफ़ गुस्सा पनपा था. बुरहान वानी की मौत इस गुस्से को सामने लाने का एक जरिया बन गई.

उल्लेखनीय है कि पिछले कई हफ्तों से एक बार फिर घाटी में ये अफवाहें उड़ रही हैं कि सरकार इन योजनाओं को अमल में लाने के लिए काम कर रही है. राज्य सरकार की ओर से पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को निवास प्रमाण-पत्र देने की घोषणा ने लोगों के संदेह को और मज़बूत किया. यह अफवाह भी है कि यहां के अवामी हलकों में हालात दोबारा ख़राब हो जाने की संभावना है. हालांकि केन्द्र सरकार के ताज़ा स्पष्टीकरण के बाद दोबारा हालात ख़राब होने की संभावना कम हो जाएगी. पिछले दिनों केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने संसद में बयान देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में कश्मीर पंडितों के लिए अलग कॉलोनियां बसाने की सरकार की तरफ से कोई योजना के विचाराधीन नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को पहचान-पत्र उपलब्ध कराने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है. उल्लेखनीय है कि विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन करने वाले 20 हज़ार हिन्दू परिवार फिलहाल जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं. इन शरणार्थियों को यहां का स्थाई निवासी बनाने की मांग कई दशकों से की जा रही है, लेकिन कश्मीर की अलगाववादी पार्टियों के साथ-साथ मुख्यधारा की पार्टियां भी इस मांग का विरोध कर रही हैं. यही कारण है कि अभी तक किसी भी सरकार ने इस मांग को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटाया है. लेकिन जब से भाजपा राज्य की सरकार में भागीदार बनी है, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि पूर्व सरकारों के उलट ये सरकार शरणार्थियों को यहां की नागरिकता देने की मांग पूरी करेगी. भाजपा कई अवसरों पर इन्हें जम्मू-कश्मीर की नागरिकता दिलाने की प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है. 2014 में प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात में उनसे वादा किया था कि उनकी सरकार इस मांग को पूरा करेगी. इतना ही नहीं मोदी सरकार ने इस आरंभिक दौर में ही राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को नई दिल्ली तलब करके उन्हें जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और पूर्व सैनिकों के लिए कॉलोनियां बनाने के लिए ज़मीन को चिन्हित करने का आदेश दिया था. जब राज्य सरकार ने इस आदेश को अमल में लाने की तैयारियां शुरू की, तो कश्मीर में इसका कड़ा विरोध शुरू हो गया. यहां तक कि पाकिस्तान सरकार ने भी भारत पर विवादित राज्य की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की. इसके बाद राज्य सरकार ने इन योजनाओं को अमल में लाने का काम सुस्त कर दिया.

बहरहाल, केन्द्र सरकार के ताज़ा स्पष्टीकरण से संभव है कि कश्मीरी जनता की इच्छाओं का निवारण होगा. ताहिर मुहीउद्दीन कहते हैं कि केन्द्र सरकार के इस नए रुख से राज्य सरकार को काफ़ी राहत मिली है. इससे जनता की कशमकश भी काफी हद तक दूर होगी. लेकिन कुछ विश्लेषकों को लगता है कि यह विश्वास करना काफी मुश्किल है कि सरकार में सहयोगी भाजपा राज्य के बारे में अपनी योजनाओं को त्याग देगी. राजनीतिक विश्लेषक ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के बारे में भाजपा की नीति और रुख़ जगज़ाहिर है. भाजपा राज्य को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म करना चाहती है. यह मुद्दा भाजपा के राष्ट्रीय चुनावी घोषणापत्र में भी शामिल रहा है. भाजपा राज्य का पूरी तरह से भारत में विलय करना चाहती है. राज्य की सरकार में शामिल होने के बाद भाजपा ने पीडीपी को दबाव में लाकर कई काम करवाए. अभी सरकार के चार साल बाक़ी हैं. संभव है कि भाजपा अपनी योजनाओं को अमल में लाने के लिए सही समय का इंतज़ार कर रही है. हालांकि भविष्य में क्या होगा, इस बार में कुछ भी विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता. ■

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा चुनाव- 2017

जानें क्या कहती है ज्योतिषीय गणना

डॉ. कुमार गणेश
(लेखक अंक ज्योतिषी एवं बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ हैं)

उत्तर प्रदेश : भाजपा का चमत्कारिक प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार पहले से कहीं अधिक दिलचस्प है. कांग्रेस व सपा ने चुनावी गठबंधन किया है. भाजपा बहुत उम्मीदों के साथ मैदान में है, वहीं रालोद अकेले ही कूद पड़ी है. इस गणना में राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदेशाध्यक्षों को सम्मिलित किया गया है, साथ ही प्रमुख दलों को लिया गया है. शेष पार्टियों व निर्दलियों को 'अन्य' में सम्मिलित किया गया है. हमने भारतीय जनता पार्टी और उसके चुनावी गठबंधन के साथियों को 'भाजपा+' व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 'भाराकां' लिखा है.

इस तरह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से बनती नहीं दिख रही है. इस सरकार को विदा होना होगा. हालांकि अखिलेश के ख़ुद के अंक अच्छे हैं, मगर समाजवादी पार्टी के ख़राब अंकों का ख़ामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा. इस आंकलन से एक और बात उभर कर सामने आती है कि सपा-कांग्रेस के चुनावी गठबंधन का कांग्रेस को बड़ा लाभ होने जा रहा है, जबकि सपा को लाभ की बजाय हानि ही उठानी पड़ रही है. एक लम्बे अर्से बाद भाजपा चमत्कारिक प्रदर्शन कर नम्बर एक के स्थान पर बैठती दिख रही है. इसलिए उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर इस बार नया मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है. हाँ, यदि यह 'नया मुख्यमंत्री' कोई 'पुराना यानी पूर्व मुख्यमंत्री' हो, तो अचम्भा नहीं होना चाहिए.

गणनीय अंक

उत्तर प्रदेश	मूलांक- 8	भाग्यांक- 6
आयु	अंक- 5 (68 वां)	नामांक- 9
दिन	अंक- 3	
मतगणना	मूलांक- 2	भाग्यांक- 6
दिन	अंक- 8 वर्षांक- 1	चलित- 3
विधान सभा	अंक- 8 (17 वीं)	

विधानसभा सीटों की संख्या- 403

सपा	109 सीटें (कम-अधिक 11)
बसपा	88 सीटें (कम-अधिक 9)
भाजपा+	167 सीटें (कम-अधिक 17)
भाराकां	39 सीटें (कम-अधिक 4)
अन्य	20 सीटें (कुल सीटों की 5%)

उत्तराखण्ड : बाज़ी फिर भी कांग्रेस के हाथ

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर की गई इस गणना में राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्षों को सम्मिलित किया गया है. शेष दलों व निर्दलियों को हमने 'अन्य' के अन्तर्गत लिया है. तो आइए, देखते हैं कि इस गणना से उत्तराखण्ड की क्या तस्वीर उभर कर आती है?

गणनीय अंक

उत्तराखण्ड	मूलांक- 1	भाग्यांक- 2
आयु	अंक- 2 (11 वां)	नामांक- 8
दिन	अंक- 2, 7	
मतगणना	मूलांक- 2	भाग्यांक- 6
दिन	अंक- 8 वर्षांक- 1	चलित- 3
विधान सभा	अंक- 3 (तीसरी)	

इस गणना के अनुसार कांग्रेस ही बहुमत प्राप्त करती हुई दिख रही है. अतः यह बात साफ है कि इस बार उत्तराखण्ड विधान सभा चुनाव में कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है. उसे इस बार किसी से समर्थन नहीं मांगना नहीं पड़ेगा.

विधानसभा सीटों की संख्या- 70

कांग्रेस	38 सीटें (कम-अधिक 4)
भाजपा	32 सीटें (कम-अधिक 3)
अन्य	04 सीटें (कुल सीटों की 5%)

पंजाब : इस बार कांग्रेस की बल्ले-बल्ले

पंजाब में इस बार चुनाव त्रिकोणीय है. सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन व कांग्रेस के बीच कूद कर आम आदमी पार्टी ने इस बार के दंगल को बहुत दिलचस्प बना दिया है. पंजाब को लेकर की गई इस गणना में राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदेशाध्यक्षों को सम्मिलित किया गया है, साथ ही प्रमुख दलों को लिया गया है. शेष पार्टियों व निर्दलियों को 'अन्य' में सम्मिलित किया गया है. हमने भारतीय जनता पार्टी को 'भाजपा', भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 'भाराकां' व आम आदमी पार्टी को 'आआपा' लिखा है.

इस प्रकार यह साफ़ है कि इस बार पंजाब की सत्ता का चेहरा बदलने जा रहा है. दस बरसों से लगातार सत्ता में रहने वाला अकाली-भाजपा गठबंधन सत्ता से बाहर होगा और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सत्ता पर काबिज होने के सबसे नजदीक रहेगी. अब यह देखना है कि कांग्रेस कम पड़ने वाली सीटों की कमी किस तरह पूरी करेगी? बहुत संभव है कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और आआपा साथ आ जाएं.

गणनीय अंक

पंजाब	मूलांक- 1	भाग्यांक- 7
आयु	अंक- 6 (51 वां)	नामांक- 5
दिन	अंक- 9	
मतगणना	मूलांक- 2	भाग्यांक- 6
दिन	अंक- 8 वर्षांक- 1	चलित- 3
विधान सभा	अंक- 6 (15 वीं)	

विधानसभा सीटों की संख्या- 117

शिअद	20 सीटें (कम-अधिक 2 सीटें)
भाजपा	06 सीटें (कम-अधिक 1 सीट)
भाराकां	49 सीटें (कम-अधिक 5 सीटें)
आआपा	42 सीटें (कम-अधिक 4 सीटें)
अन्य	06 सीटें (कुल सीटों की 5%)

मणिपुर : त्रिशंकु विधान सभा

पिछले विधानसभा के उपचुनाव में दो सीटें जीतने से उत्साहित भाजपा इस बार सरकार बनाने का मंसूबा साधे हुए है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी सत्ता जारी रखने के मूड में है. इधर तृणमूल कांग्रेस अपने विधायकों के कांग्रेस में चले जाने का ज़बर्दस्त दंश भूला नहीं पा रही है. हमने इस गणना में राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदेशाध्यक्षों को सम्मिलित किया है, साथ ही प्रमुख दलों को लिया गया है. शेष पार्टियों व निर्दलियों को 'अन्य' में सम्मिलित किया गया है. हमने भारतीय जनता पार्टी को 'भाजपा', नगा पीपल्स फ्रंट को 'नपिफ़' व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 'भाराकां' लिखा है.

इस त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है. भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में पहली बार भारी-भरकम जीत दर्ज करने जा रही है. तृणमूल कांग्रेस भी सम्मानजनक संख्या में सीटें ले कर अपने घावों पर मरहम लगा लेगी. नगा पीपल्स फ्रंट इस बार बड़े घाटे में रह सकता है. हालांकि वास्तविक तस्वीर तो मतगणना के परिणाम आने पर ही सामने आ पाएगी.

गणनीय अंक

मणिपुर	मूलांक- 1	भाग्यांक- 7
आयु	अंक- 6 (51 वां)	नामांक- 5
दिन	अंक- 9	
मतगणना	मूलांक- 2	भाग्यांक- 6
दिन	अंक- 8 वर्षांक- 1	चलित- 3
विधान सभा	अंक- 6 (15 वीं)	

विधानसभा सीटों की संख्या- 60

भाराकां	24 सीटें (कम-अधिक 2)
भाजपा	20 सीटें (कम-अधिक 2)
तृणमूल	13 सीटें (कम-अधिक 1)
नपिफ़	03 सीटें
अन्य	03 सीटें (कुल सीटों की 5%)

गोवा : त्रिशंकु विधान सभा

गोवा में इस बार एक तरफ़ जहां भाजपा का महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी से गठबन्धन टूट चुका है, वहीं आरएसएस के बाग़ी नेता सुभाष वेलिंगकर ने अपने नए दल गोवा सुरक्षा मंच का मगोपा व शिव सेना के साथ महागठबंधन किया है. इस गणना में राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदेशाध्यक्षों को सम्मिलित किया गया है, साथ ही प्रमुख दलों को लिया गया है. शेष पार्टियों व निर्दलियों को 'अन्य' में सम्मिलित किया गया है. हमने भारतीय जनता पार्टी और उसके चुनावी गठबन्धन के साथियों को 'भाजपा+', भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 'भाराकां', महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी को 'मगोपा', शिव सेना को 'शिसे', गोवा सुरक्षा मंच को 'गोसुम' व आम आदमी पार्टी को 'आआपा' लिखा है. 'भाजपा+' के अन्तर्गत भाजपा व उसके सहयोगी कैथोलिक स्ट्रींगहोल्ड को लिया गया है. भाजपा 36 सीटों व कैथोलिक स्ट्रींगहोल्ड 04 सीटों चुनाव पर लड़ रही है.

गणनीय अंक

गोवा	मूलांक- 3	भाग्यांक- 2
आयु	अंक- 3 (30 वां)	नामांक- 2
दिन	अंक- 8	
मतगणना	मूलांक- 2	भाग्यांक- 6
दिन	अंक- 8 वर्षांक- 1	चलित- 3
विधान सभा	अंक- 7 (7 वीं)	

इस तरह यह स्पष्ट है कि इस बार गोवा विधान सभा का स्वरूप त्रिशंकु रहेगा. यहां गठबंधन सरकार देखने को मिलेगी. यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस और आआपा सरकार बनाने के लिए साथ आ जाएंगे?

विधानसभा सीटों की संख्या- 40

भाजपा+	07 सीटें (कम-अधिक 01)
भाराकां	14 सीटें (कम-अधिक 01)
आआपा	12 सीटें (कम-अधिक 01)
शिसे	01 सीट
मगोपा	05 सीटें
गोसुमं	01 सीटें
अन्य	02 सीटें (कुल सीटों की 5%)

टाइगर रिज़र्व के बाद नई मुसीबत बना केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट

विकास के सपने के बीच विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर ग्रामीण

कुमार कृष्णन

छतरपुर-मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के गंगऊ प्रवेश द्वार मतौर से 20-25 किलोमीटर अंदर पन्ना टाइगर रिज़र्व के कोर जोन में बसा हैं, ग्राम पंचायत पल्कोहं और खर्यानी, जिसकी जनसंख्या लगभग 5000 है. यहां कभी गोंड राजा का वानव गढ़ का किला हुआ करता था. पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में ऐसे गांवों की संख्या 49 है. यहां के ग्रामीणों का जीविकोपार्जन कई मायनों में पन्ना टाइगर रिज़र्व पर निर्भर है, अथवा इससे प्रभावित है. यहां प्रवेश द्वार मतौर से अंदर जाने के लिए वन विभाग की अनुमति लेना जरूरी है. स्थानीय निवासियों को भी गेट पर नाम दर्ज करवाना होता है. प्रवेश द्वार से पल्कोहं तक कच्ची सड़क है, जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं. लेकिन फिर भी लोग छोटी गाड़ियों से आते-जाते हैं. टाइगर रिज़र्व के अधिकारी सड़क की मरम्मत और पक्कीकरण का कार्य नहीं करने देते हैं. रास्ते में गंगऊ बांध है. यह बांध अंग्रेजों ने 1909 से 1915 के दौरान केन नदी पर बनवाया था. जो अभी तक बांदा जिला को पानी पिला रहा है. बांध आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में ही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक 1915 में पल्कोहं, डोडन, खर्यानी और कुछ दूसरे गांवों की कृषि भूमि इस बांध में जलमग्न हो गई थी. उसके बाद से स्थानीय लोग डूब क्षेत्र के पीछे केन नदी के किनारे खेती करने लगे. बरसात में तो फसल पानी में डूब जाती है, लेकिन रबि की फसल, खासकर सरसों और गेहूं की अच्छी ऊपज होती है. जमीन इतनी उर्वर है कि खेतों में कभी खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि जंगली जानवरों से खेती को नुक़सान पहुंचता है. पल्कोहं गांव में पहुंचने पर पता चला कि यहां आठवीं तक की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र हैं, लेकिन आगे की पढाई, इलाज व बाजार के लिए 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है.

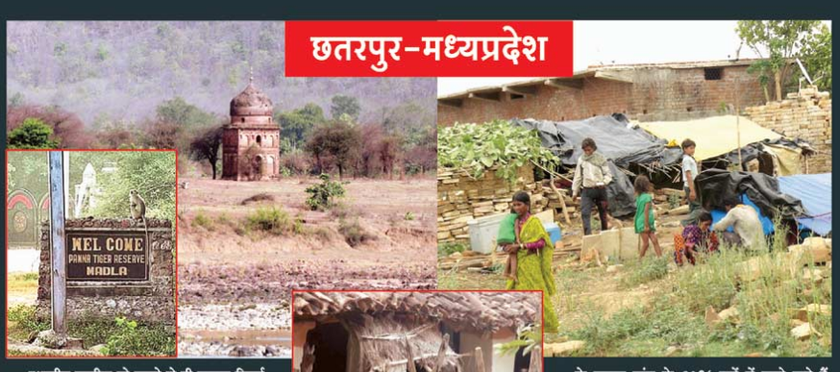

स्थानीय ग्रामीण तो पहले से ही टाइगर रिजर्व के कारण डर और संकट के साए में जी रहे हैं, अब केन-बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना का प्रस्तावित बांध इनके लिए नई समस्या लेकर आया है. केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के कारण करीब 7.2 लाख पेड़ और 90 वर्ग किलोमीटर में फैले पन्ना बाघ अभयारण्य के डूब जाने की आशंका है. करीब 9000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से 13.42 लाख लोगों को पेयजल मुहैया कराने की योजना है. साथ ही इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की 6.75 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलने की भी बात कही जा रही है. नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थाई समिति ने केन-बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रस्तावित जलप्लावित क्षेत्र के दायरे में पूरा वन क्षेत्र आ जाएगा. इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के धौदान गांव में एक डैम का निर्माण होना है, जिसमें ये तीनों गावों डूब रहे हैं. जन सुनवाई में तीनों गावों वालों ने इस शर्त पर सहमति दी है कि उन्हें वाजिब पैसा दिया जाए, ताकि वे कहीं दूसरी जगह जाकर बस सकें. ग्रामीणों का कहना है कि जब से टाइगर रिज़र्व बना है, तब से हमारे तमाम विकास कार्य रुक गए हैं. गांव में किसी भी तरह के रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं. जंगली वस्तुओं को इकट्ठा कर उन्हें बेचने, जंगल में पशु चराई करने और मछली पकड़ने जैसे पारम्परिक कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. यहां मनरेगा के अंतर्गत भी काम नहीं मिलता है. रोजगार की इन समस्याओं के कारण गांव के 80% घरों में ताले लगे हैं. फसलों की बिजाई के बाद लोग सपरिवार रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं. अब तो घरों पर तालों के साथ-साथ घर के बाहर आंगन में बाड़ भी लगाई जाती है.

पल्कोहं के ग्रामीणों ने बताया कि 1998-99 तक हम अपनी खेतिहर जमीन के लिए राजस्व विभाग को सालाना 50 रुपया प्रति एकड़ बोली देते थे. बाद में इसे बढ़ा कर तीन साल के लिए 200 रुपया कर दिया गया था. लेकिन टाइगर रिजर्व बनने के बाद बोली लेना बंद कर दिया गया और अब हमारी कृषि भूमि को वन विभाग अपना कह रहा है. हमें कहा जा रहा है कि खेती बंद कर भूमि खाली करें. 1998-99 से पहले कुछ ग्रामीणों को जमीन के पट्टे भी दिए गए थे, लेकिन अब पटवारी कह रहे हैं कि उनके पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं. पल्कोहं के सरपंच जमना यादव ने बताया की इस गांव में 17 जातियों के लोग रहते हैं. जिनमें मुख्य रूप में कोइदा आदिवासी, बसुर, कोरी, डिमर (सभी दलित) और यादव हैं. यहां के ज्यादातर आदिवासी और दलित भूमि हीन हैं. ऐसे लोगों का जिविकोपार्जन वन उत्पादों जैसे कंद, फल, जड़ीबुटी, चिरोंजी, गोंद, तेंदु पत्ता, नदी से मछली पकड़ना, पशुपालन और दस्तकारी इत्यादि पर निर्भर था. टाइगर रिजर्व इनके लिए अभिशाप बन कर आया है. इनके सभी निस्तार अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं. लोगों का कहना है कि वन उत्पादों के लिए जंगल में जाने, मछली पकड़ने और पशुओं के गांव से बाहर जाने पर वन विभाग ने जुर्माना करता है, साथ ही पशुओं को कांजी घर में बंद कर दिया जाता है.

हिमालय नीति अभियान के गुमान सिंह बताते हैं कि यहां के सरपंचों को भी वन अधिकार कानून के बारे में पता नहीं है. छतरपुर यहां का जिला मुख्यालय है. आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई 2014 को विशेष अभियान के दौरान 8,238 व्यक्तिगत और 1,124 सामुदायिक वन अधिकार के दावे जिला स्तर पर प्राप्त हुए थे. जिनमें से 497 व्यक्तिगत और 240 सामुदायिक दावे मान्य किए गए. अब सवाल यह उठता है कि जब पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया गया, तो इन दो पंचायतों में वन अधिकार कानून लागू कराने का कार्य क्यों नहीं किया गया. जिला संयोजक ने बताया कि यह क्षेत्र टाइगर रिजर्व में पड़ता है. परन्तु असली मसला तो केन-बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना है, जिस कारण यहां वन अधिकार कानून लागू करवाने की पहल नहीं की गई. इस परियोजना में टाइगर रिज़र्व के कोर ज़ोन की ही 4,100 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी, जिस पर वन विभाग ने सहमति दे दी है. अब सवाल यह उठता है कि किसी अच्छे जगह पर विस्थापन के लिए वाजिब मुआवजे की मांग कर रहे लोगों का सपना क्या पूरा होगा? ■

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा चुनाव 2017

क्या कहता है इन नेताओं का टैरो कार्ड

अलंकृता मानवी

इस चुनाव में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं समेत उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नेताओं की भूमिका क्या रहेगी, बता रही हैं, टैरो कार्ड रीडर अलंकृता मानवी .

लेखिका मशहूर टैरो कार्ड रीडर हैं. आप भी अगर टैरो कार्ड के ज़रिए अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो संपर्क करें- 9717002199

राष्ट्रीय नेता

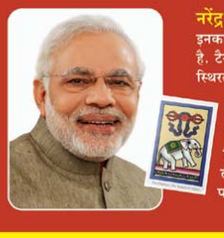

नरेंद्र मोदी

इनका कार्ड है, एलीफैंट यानी हाथी. हाथी ताकत और शुभ का प्रतीक है. टैरो विधा के मुताबिक, पांच राज्यों के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी में स्थिरता आएगी. इनकी ताकत में इजाफा होगा. जाहिर है, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी एक अजेय योद्धा की तरह उभर कर सामने आए थे. उसके बाद होने वाले कई विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को उन्हीं के नाम पर जीत मिली. हालांकि, दिल्ली और बिहार में पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ा. लेकिन इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद निश्चित तौर पर उनकी राजनीति में एक स्थिरता आएगी.■

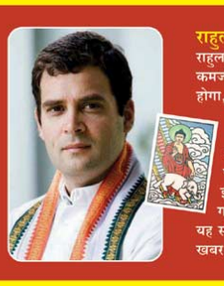

राहुल गांधी

राहुल गांधी का कार्ड बताता है कि इस वक्त वे भावनात्मक रूप से कमजोर हुए हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है या होगा, लेकिन अंत में परिणाम अच्छा नहीं आएगा. उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहयोग की आवश्यकता है. मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखें, तो इस वक्त राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए जी-जान लगाए हुए हैं. लेकिन लगातार पराजय की वजह से कांग्रेस पार्टी का मनोबल गिरा हुआ है. हालांकि अन्य दलों के सहयोग से इन्हें बिहार में सफलता मिली थी. अब उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी सपा के साथ गठबंधन कर के चुनावी मैदान में उतरे हैं. अगर यह सहयोग बरकरार रहता है, तो उम्मीद है कि इनके लिए कोई अच्छी खबर आएगी.■

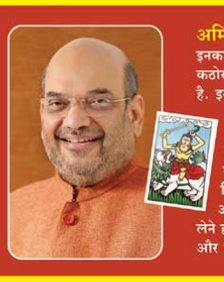

अमित शाह

इनका कार्ड कहता है, वक्त आ गया है कि अमित शाह कुछ मजबूत, कठोर और प्रमुख निर्णय लें. इनके लिए चुनौतीपूर्ण समय आने वाला है. इनके आस-पास नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है और इन्हें सलाह देने वाले लोग सही सलाह नहीं दे रहे हैं. जाहिर है, ऐसी स्थिति में गलतियां होने की गुंजाइश भी ज्यादा रहती है. 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जिस तरह से टिकट वितरण (खास कर उत्तर प्रदेश में) किया है, उसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं. निश्चित तौर पर यह आस-पास फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा का ही असर है. ऐसे में अमित शाह को आने वाले समय में कठोर निर्णय लेने ही होंगे. अगर वे कठोर निर्णय नहीं लेते हैं, तो उनके लिए चुनौतियां और भी बढ़ जाएंगी.■

प्रियंका गांधी

इनके कार्ड के मुताबिक, इन्हें वरिष्ठ लोगों से सलाह लेने की जरूरत है. अभी भी इनमें परिपक्वता का आना बाकी है. अगर ये वरिष्ठों से सलाह लेती हैं और अपनी राजनीति में परिपक्वता लाती हैं, तो भविष्य में इनके लिए बेहतर होगा.■

उत्तर प्रदेश

अखिलेश यादव

इनके कार्ड का नाम है, तारा द वर्ल्ड कार्ड. इस कार्ड की व्याख्या के मुताबिक अखिलेश यादव भयभीत नजर आ रहे हैं. हालांकि ये जितना डर रहे हैं, उतना बुरा परिणाम भी नहीं आएगा. ये थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. इनका एक कार्ड न्यूट्रल कार्ड है, जो इनके मुख्यमंत्री बनने के अवसर को काफी कम कर देता है. इनका एक कार्ड ओल्ड मैन कार्ड भी है, जो बताता है कि नकारात्मकता की वजह से ही घर में पिता के साथ इनका झगड़ा हुआ, इसका भी बुरा असर इन पर हो सकता है.■

शिवपाल सिंह यादव

इनका कार्ड लिमिटेशंस दिखा रहा है. यानी अभी ये जहां हैं, वहां पर एक सीमा के भीतर बंधे हुए हैं. अगर ये इस सीमा से बाहर निकलते हैं, तो इनके लिए फायदेमंद होगा. शिवपाल अगर अपनी मौजूदा पार्टी से बाहर निकलते हैं, तो इनका सियासी भविष्य उज्ज्वल रहेगा.■

योगी आदित्यनाथ

इनका कार्ड बताता है कि इस चुनाव में इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ेगा. अगर ये सावधानी पूर्वक काम नहीं करते हैं, तो इनका बहुत नुकसान होगा. अभी इन्हें उचित सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता है.■

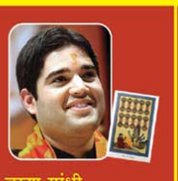

वरुण गांधी

इनका कार्ड बता रहा है कि अगर ये डिवाइन प्रोटेक्शन (दैवीय आशीर्वाद) लेते हैं, तो कुछ समय के बाद इनके लिए बेहतर समय आएगा.■

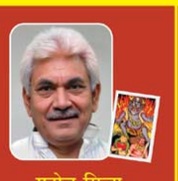

मनोज सिन्हा

इनके कार्ड का नाम है, डेविल कार्ड. इनके साथ अतीत में अच्छा नहीं हुआ है. भविष्य में अगर ये अन्य लोगों के समर्थन से चलेंगे, तो इनके लिए बेहतर होगा.■

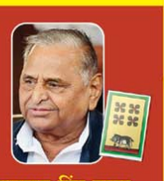

मुलायम सिंह यादव

इनका कार्ड मिसफॉर्च्यून कार्ड है. यह नकारात्मकता को दिखाता है. इन्हें सहयोग की आवश्यकता है. नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही इनका समय अभी खराब चल रहा है.■

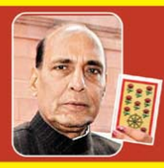

राजनाथ सिंह

इनका पहला कार्ड नकारात्मकता दिखाता है, लेकिन एक अन्य कार्ड भी है, जिसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड कहते हैं. यह कार्ड इनके लिए शुभ संकेत दे रहा है. उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद इनकी भूमिका में बदलाव आ सकता है और राजनाथ सिंह एक महत्वपूर्ण रोल में सामने आ सकते हैं.■

मायावती

इनके कार्ड का नाम है मिसफॉर्च्यून कार्ड. यह कार्ड इस चुनाव में इनके लिए डाउनफॉल दिखाता है. अगर, इन्हें कहीं से प्रोटेक्शन (साथ-सहयोग) मिले, तो कुछ अच्छा हो सकता है.■

महेश शर्मा

इनका कार्ड बताता है कि इन्हें अपने अंदर नकारात्मकता नहीं आने देना चाहिए. इनका कार्ड प्यार और दया दिखाता है. ये अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो अच्छा रहेगा, लेकिन नकारात्मकता की वजह से ऐसा होता नहीं दिख रहा है.■

केशव मौर्या

इनका पहला कार्ड मदर कार्ड है, जो अच्छा है. लेकिन इस चुनाव को ले कर इनके मन में भय है. इन्हें ये भय हटाना चाहिए. अगर ये उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर में बने रहना चाहते हैं, तो इन्हें काफी मेहनत करनी होगी. हालांकि इनका सियासी भविष्य अच्छा है.■

शेखावाटी महोत्सव 2017

शेखावाटी महोत्सव में कमल मोरारका के साथ चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय व अन्य अतिथि

राजस्थान की धरती भारतीय संस्कृति और विरासत की अमूल्य धरोहर है. आज जब आधुनिकता की दौड़ में अतित पीछे छूट रहा है, इस समय मोरारका फाउंडेशन के द्धारा प्रति वर्ष आयोजित किया जाने वाला शेखावाटी महोत्सव लोक संस्कृति और विरासत को जिंदा रखने की एक कामयाब कोशिश है. ऐतिहासिक हवेलियों के लिए प्रख्यात नवलगढ़ में पिछले दो दशक से ज्यादा समय से अनवरत जारी शेखावाटी महोत्सव न सिर्फ आधुनिकता के साथ गौरवशाली अतित के समन्वय का शानदार उदाहरण है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और विरासत से अवगत कराने का एक माध्यम भी है. इस साल 09 से 12 फरवरी के बीच हुए 22वें शेखावटी महोत्सव में भी राजस्थानी कला-कौशल, पकवान व भाव-भंगिमा का अद्भूत समायोजन देखने को मिला. कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं आयोजन की झलकियां.

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

इफली बजाकर कार्यक्रम का उद्घाटन करते स्थानीय विधायक राजकुमार शर्मा

कार्यक्रम में कमल मोरारका के साथ अन्य अतिथि

कमल मोरारका व भारती मोरारका के साथ अतिथि

भाव नृत्य प्रस्तुत करतीं स्कूली बच्चियां

अतिथियों के सामने करतब दिखाता घोड़ा

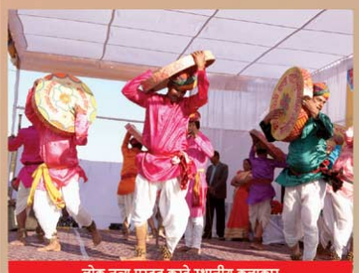
लोक नृत्य प्रस्तुत करते स्थानीय कलाकार

अतिथियों को माला पहनाता ऊंट

बच्चियों की पेंटिंग का अवलोकन करतीं श्रीमती भारती मोरारका

लोकगीत पर करतब दिखाता ऊंट

बैंड के साथ स्कूली बच्चे

बच्ची को अवार्ड देते संतोष भारतीय, रीना भारतीय व श्रीचंद्र जैन

अवार्ड देते संतोष भारतीय, रीना भारतीय व श्रीचंद्र जैन

अवार्ड देते संतोष भारतीय व रीना भारतीय

अवार्ड देते किसान मंच के अध्यक्ष विनोद सिंह

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

लोकतंत्र में अहंकार काम नहीं करता

यह दावा गलत है कि 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ और हम ही सब कुछ कर रहे हैं. दरअसल, आपका स्टैंडर्ड रोज़-बरोज़ गिरता जा रहा है. बहरहाल, 11 मार्च को पता चल जाएगा कि हवा किस दिशा में बह रही है. मैं समझता हूं कि यह देशहित में होगा कि मतदाता भाजपा को सबक सिखाएं. उसे हरा कर नहीं, बल्कि एक सीमित स्तर तक लाकर. उनका अहंकार बहुत अधिक है, वह निश्चित रूप से कम होना चाहिए. लोकतंत्र में अहंकार काम नहीं करता. इंदिरा गांधी का आपातकाल विफल हो गया था. फ़िलहाल हम लोग अभी अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहे हैं. हर नौकरशाह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है. हर मंत्री, राज्य मंत्री, हर कोई अपनी सीमा से अधिक बात कर रहा है. यह जितनी जल्द ख़त्म होगा, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा.

पिछले दिनों तमिलनाडु राजनीतिक ड्रामे का केंद्र रहा. विधायक दल की चुनी हुई राजनेता को शपथ ग्रहण से रोक कर राज्यपाल ने वहां निम्न स्तर का एक नया मानक स्थापित किया है. ये बहुत कमज़ोर बहाने हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है या विधायकों को एक रिसोर्ट में बंधक बना कर रखा गया है. राज्यपाल यह बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति में आईबी उन्हें हर चीज़ से बाख़बर रखती है. उन्हें ख़बर थी कि रिसोर्ट में रखे गए विधायक बंधक नहीं थे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से वहां थे. लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार के दबाव में (जिसमें गृह मंत्रालय, पीएमओ और प्रधानमंत्री स्वयं शामिल थे) वे राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि शशिकला को उस पद से वंचित रखा जाए, जिसके लिए उनके विधायकों ने उन्हें चुना है.

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से शशिकला मुख्यमंत्री नहीं बन सकीं. लेकिन बाद की घटनाएं आदर्श न्याय (पोएटिक जस्टिस) साबित हुईं. यहां राज्यपाल को वो काम करना पड़ा, जो वे नहीं करना चाहते थे. जब शशिकला द्वारा मनोनीत व्यक्ति को उसी रिसॉर्ट के विधायकों ने अपना नेता चुना, तो राज्यपाल को उसे शपथ दिलाना पड़ा. अब सवाल यह उठता है कि उनके उस ग्रैंड स्कीम का क्या हुआ, जिसमें वे पन्नीरसेल्वम को विधायकों की बहुमत का समर्थन हासिल करने का मौक़ा दे रहे थे? एआईएडीएमके के कुल 134 विधायकों में से 124 विधायकों ने शशिकला के उम्मीदवार को चुना. यह तथ्य राज्यपाल की शर्मिंदगी के लिए काफी है कि उनका फैसला इतना कमज़ोर था या केंद्र सरकार के दबाव में इतना पक्षपातपूर्ण था, जो उनके पद की मर्यादा के लिए तो ठीक नहीं ही था, केंद्र सरकार के लिए भी ठीक नहीं था.

> यहां राज्यपाल को वो काम करना पड़ा, जो वे नहीं करना चाहते थे. जब शशिकला द्वारा मनोनीत व्यक्ति को उसी रिसॉर्ट के विधायकों ने अपना नेता चुना, तो राज्यपाल को उसे शपथ दिलाना पड़ा. अब सवाल यह उठता है कि उनके उस ग्रैंड स्कीम का क्या हुआ, जिसमें वे पन्नीरसेल्वम को विधायकों की बहुमत का समर्थन हासिल करने का मौक़ा दे रहे थे? एआईएडीएमके के कुल 134 विधायकों में से 124 विधायकों ने शशिकला के उम्मीदवार को चुना.

विडंबना यह है कि भाजपा, कांग्रेस को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश करती है और कहती है कि हम उससे अलग हैं, लेकिन हक़ीक़त में वो वही काम कर रही है, जो कांग्रेस किया करती थी. दरअसल, भाजपा वो काम और अधिक भद्दे तरीके से कर रही है. कांग्रेस कम से कम कुछ लाज-लिहाज़ रखती थी और परदे में काम करती थी. बहरहाल, अब यह अध्याय समाप्त हो चुका है. तमिलनाडु की राजनीति अपने पुराने ढर्रे पर आ गई है. देखते हैं आगे क्या होता है.

दूसरा मामला नए सेनाध्यक्ष बिपिन रावत से जुड़ा हुआ है. एक सेनाध्यक्ष कितना नीचे जा सकता है, उन्होंने भी इसका रिकॉर्ड स्थापित किया है. सेनाध्यक्ष को बहुत अधिक बात नहीं करनी चाहिए. वे जितना कम बात करेंगे, उतना ही अच्छा होगा. उन्होंने एक बयान जारी किया है कि कश्मीर में छात्रों द्वारा पत्थरबाज़ी से ये समझा जाएगा कि वे आतंकवादियों के भागने में मदद कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. यह पूरी तरह से गैरज़रूरी, भड़काऊ, शरारतपूर्ण और उत्तर प्रदेश में भाजपा को फायदा पहुंचाने की नियत से दिया गया बयान है. सौभाग्यवश भारत के लोग होशियार हैं, उनपर ऐसी चीज़ों का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता और वे यूनिफॉर्म को बहुत गंभीरता से नहीं लेते. चाहे आर्मी चीफ हों या पुलिस चीफ, उन्हें अपने काम पर ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए. पूर्व दिल्ली पुलिस चीफ बीएस बस्सी ने भी कुछ ऐसा ही किया था. उन्होंने एक चुने हुए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को आम बहस की चुनौती दी थी.

मुझे नहीं मालूम कि मोदी कौन सा मानक स्थापित कर रहे हैं. शायद वे समझ रहे हैं कि वे देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं. अपने हर भाषण में वे कहते हैं कि आज़ादी के बाद से 70 साल तक कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया. मुझे नहीं मालूम कि वे किस दुनिया में जीते हैं? आज हम जो भी हैं, जिसमें एक दिन में 104 उपग्रह अन्तरिक्ष में भेजना शामिल है, इसका श्रेय किसी न किसी रूप में जवाहरलाल नेहरु और इंदिरा गांधी को भी जाना चाहिए. जिन्होंने कुछ संस्थाएं बनाईं, जिनमें इसरो, डीआरडीओ और बाकी कई संस्थाएं शामिल हैं. ये संस्थाएं 26 मई 2014 के बाद वजूद में नहीं आई हैं. बेशक भारत के लोग होशियार हैं, वे इन सब बातों में विश्वास नहीं करते. ज़ाहिर है कोई भी पार्टी दशकों तक सत्ता में रहेगी, तो उससे गलतियां भी होंगी और वो चुनाव हारेगी और फिर बाद में जीतेगी भी. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह चलता रहता है. यह दावा गलत है कि 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ और हम ही सब कुछ कर रहे हैं. दरअसल, आपका स्टैंडर्ड रोज़-बरोज़ गिरता जा रहा है. बहरहाल, 11 मार्च को पता चल जाएगा कि हवा किस दिशा में बह रही है. मैं समझता हूं कि यह देशहित में होगा कि मतदाता भाजपा को सबक सिखाएं. उसे हरा कर नहीं, बल्कि एक सीमित स्तर तक लाकर. उनका अहंकार बहुत अधिक है, वह निश्चित रूप से कम होना चाहिए. लोकतंत्र में अहंकार काम नहीं करता. इंदिरा गांधी का आपातकाल विफल हो गया था. फ़िलहाल हम लोग अभी अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहे हैं. हर नौकरशाह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है. हर मंत्री, राज्य मंत्री, हर कोई अपनी सीमा से अधिक बात कर रहा है. यह जितनी जल्द ख़त्म होगा, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

जम्मू की ख़ामोश बहुमत को सलाम

शुजात बुख़ारी

पिछले कुछ हफ़्तों के घटनाक्रम ने सबका ध्यान जम्मू-कश्मीर के तीन क्षेत्रों में से एक जम्मू पर केन्द्रित कर दिया है. पहली घटना डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की जन्म तिथि पर छुट्टी के प्रस्ताव को लेकर खड़े विवाद से संबंधित है. इस प्रस्ताव पर कश्मीर में तीखी प्रतिक्रिया हुई है, जिसकी पृष्ठभूमि यह थी कि डोगरा वंश ने तकरीबन सौ वर्ष के शासनकाल में कश्मीर पर निरंकुशता के साथ शासन किया. ऐसे घावों को कुरेदने से तकलीफ़ होती है. छुट्टी का यह मुद्दा अभी विधान परिषद् तक प्रस्ताव के रूप में सीमित ही है कि क्षेत्रीय राजनीति में निहित एक और पहलू सामने आ गया, जो बज़ाहिर उतना महत्वपूर्ण नहीं है. फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने एक हड़ताल बुलाई है, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएमएससीएल) द्वारा एक बाहरी व्यक्ति (यानी जम्मू-कश्मीर के गैर-निवासी) को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का विरोध किया है.

शायद बहुत ही कम लोग होंगे, जिन्हें यह जानकारी होगी कि जम्मू में अभी आर्टिकल 370 चिंता का विषय होगा. एक लंबे समय तक इस मुद्दे का संबंध केवल कश्मीर से रहा है. दरअसल भाजपा ने न सिर्फ राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सत्ता पाने के लिए एक प्रभावी चुनावी हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया है. 1998 में जब भाजपा पहली बार केंद्र में सत्ता में आई (हालांकि एक छोटी अवधि के लिए) और फिर 1999 में वापस सत्ता हासिल की, तो उसके दो मुख्य मुद्दे थे. पहला, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और दूसरा, जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को समाप्त करना. हालांकि बहुमत के अभाव में भाजपा को इन मुद्दों को त्यागना पड़ा, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए उसे ऐसी पार्टियों की मदद लेनी पड़ी, जो शायद सेक्युलर थीं. लेकिन भाजपा ने इन मुद्दों को कभी नहीं छोड़ा और ये दोनों मुद्दे विचारधारा का आधार बने रहे. भाजपा जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में पूर्ण एकीकरण की पक्षधर है और इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा, राज्य और केंद्र के बीच संवैधानिक रिश्ते को परिभाषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान को समाप्त करना चाहती है.

जम्मू-कश्मीर में चुनावों के दौरान भाजपा धर्म के मुद्दे को उठाती रही है, क्योंकि जम्मू हिंदू बहुल क्षेत्र है. हालांकि पीर पंजाल और चिनाब क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं. आर्टिकल 370 की समाप्ति भी हमेशा पार्टी के चुनाव अभियान के केन्द्र में रहा है. आर्टिकल 370 की वजह से

> दरअसल, राज्य में कांग्रेस का जो नुक़सान था, वही भाजपा का फायदा था. कांग्रेस पहले ही भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुकी थी. कांग्रेस ने 2002 से 2008 तक पीडीपी के साथ और 2009 से 2014 तक एनसी के साथ गठबंधन सरकार बना कर राज्य में ध्रुवीकरण का बीज भी बोया. परंपरागत रूप से कांग्रेस जम्मू क्षेत्र की अधिकांश सीटों पर जीतती आई है और कश्मीर की पार्टियों एनसी और पीडीपी के साथ गठबंधन करती आई है. हालांकि लद्दाख में भी इसकी उपस्थिति मजबूत है, लेकिन इसने हमेशा खुद को जम्मू के रक्षक के रूप में पेश किया है. अपने 12 वर्ष के शासनकाल में कांग्रेस के मंत्रियों ने यह लक्ष्य बना लिया था कि जम्मू में कोई भी मुसलमान किसी महत्वपूर्ण पद पर न आए.

विकास में राज्य के पिछड़ जाने की अवधारणा और कश्मीर घाटी के मुसलमानों के वर्चस्व के इर्द-गिर्द तैयार की गई धार्मिक भावना ने जम्मू में धीरे-धीरे भाजपा को चुनावी लाभ देना शुरू कर दिया है. 2014 के आम चुनाव के ध्रुवीकरण ने मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफलतापूर्वक दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचा दिया. जम्मू में भी इसका खास असर देखने को मिला और दिसम्बर 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें जीत ली. 2008 के चुनावों में भाजपा को इसकी आधी सीटें मिली थीं. भाजपा ने मोदी लहर और अच्छे दिनों के वादे के साथ जम्मू जीत लिया और 23 प्रतिशत वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी. हालांकि पीडीपी को उससे थोड़ा कम, 22.7 प्रतिशत वोट मिला.

दरअसल, राज्य में कांग्रेस का जो नुक़सान था, वही भाजपा का फायदा था. कांग्रेस पहले ही भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुकी थी. कांग्रेस ने 2002 से 2008 तक पीडीपी के साथ और 2009 से 2014 तक एनसी के साथ गठबंधन सरकार बना राज्य में ध्रुवीकरण का बीज भी बोया. परंपरागत रूप से कांग्रेस जम्मू क्षेत्र की अधिकांश सीटों पर जीतती आई है और कश्मीर की पार्टियों एनसी और पीडीपी के साथ गठबंधन करती आई है. हालांकि लद्दाख में भी इसकी उपस्थिति मजबूत है, लेकिन इसने हमेशा खुद को जम्मू के रक्षक के रूप में पेश किया है. अपने 12 वर्ष के शासनकाल में कांग्रेस के मंत्रियों ने यह लक्ष्य बना लिया था कि जम्मू में कोई भी मुसलमान किसी महत्वपूर्ण पद पर न आए. लिहाज़ा जम्मू में उसका सांप्रदायिकतावाद अंततः भाजपा की मदद कर गया.

अब फार्मासिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल की तरफ वापस लौटते हैं. इस हड़ताल ने दो दिनों के लिए जम्मू में अपने कारोबार को ठप्प रखा. यह हड़ताल एक ऐसी कहानी कह रही है, जो अब तक न तो कही गई है और न ही सुनी गई है. राजनीतिक दावपेंच और भावनाओं के शोषण से इतर इस एक घटना ने उस सिद्धांत की हवा निकाल दी है, जिसने जम्मू में भाजपा की राजनीति को आधार दिया था. हालांकि इसके फायदे-नुक़सान के पहलुओं और आर्थिक हित (जिसने फार्मासिस्टों को निगम के आदेश के खिलाफ विद्रोह करने पर मजबूर किया) पर अलग से बहस हो सकती है. लेकिन यह क्षेत्र की असली चिंता और राज्य की विशेष पहचान के बारे में बहुत कुछ कह जाती है. हो सकता है, यह केवल व्यावसायिक हितों के साथ जुड़ा हो, लेकिन आख़िरकार यह व्यापारियों की एक बड़ी राजनीतिक अभिव्यक्ति है, जो दिखाती है कि धारा 370 उनके लिए कितनी पवित्र है. यह पहला मौक़ा नहीं है, जब लोगों ने राज्य के विशेष दर्जे पर अपनी चिंता जताई हो, पूर्व में भी राज्य की नागरिकता का प्रमाण-पत्र जम्मू में मुद्दा रहा है, हालांकि इस तरह के प्रमाण-पत्र हजारों की संख्या में राज्य के गैर निवासियों को गुप्त रूप से दिया गया है.

इस से इतर कि जम्मू दलों के लिए राजनीतिक फुटबॉल बन गया और राजनीतिक दलों ने इसका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया है, यह विद्रोह उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाला है, जो इस मुद्दे को विवादास्पद बना कर अब तक लोगों का शोषण करते रहे हैं. प्रोफेसर रेखा चौधरी जैसी प्रतिष्ठित राजनीति शास्त्री ने जम्मू को हमेशा ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के चश्मे से देखे जाने पर अपनी आपत्ति जताई है. उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि वहां हाशिए के तत्वों से परे भी बहुत कुछ है.

गौरतलब है कि फार्मासिस्टों की हड़ताल से पहले भी जून 2016 में सरकार को राज्य के एक गैर-निवासी को दिए गए खनन लीज के विवादास्पद आदेश को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था. विधानसभा में हंगामे के बाद सरकार ने अनुबंध को रद्द कर दिया था. उस समय भी यही चिंता व्यक्त की गई थी कि विशेष राज्य के दर्जे को कमज़ोर किया जा रहा है.

हालांकि पैंथर्स पार्टी जैसी पार्टियां भी हैं, जो जम्मू के साथ भेदभाव का नारा लगा कर भाजपा की जगह लेने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन मौजूदा घटनाक्रम ने ऐसी ताकतों को अप्रासंगिक बना दिया है. अब जागो जम्मू और रोहिंग्या मुसलमानों को भगा दो का नारा भी कारगर साबित नहीं होगा. लेकिन असल मुद्दा यह है कि क्या हुर्रियत सहित सभी कश्मीरी पार्टियां आगे आकर जम्मू की इन भावनाओं को मजबूती प्रदान करेंगी, जो दरअसल छुपी होती हैं और आर्थिक हितों का नुकसान होने पर प्रकट होती हैं. यह एक साझा मुद्दा है कि राज्य की विशेष पहचान की रक्षा की जाए और सभी दलों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए. अब चुनावी राजनीति इसे सफल होने देगी यह नहीं यह कहना मुश्किल है. लेकिन भाजपा के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि आर्टिकल 370 समाप्त करने का उसका नारा भविष्य में कारगर साबित नहीं होगा. राज्य की पहचान और विशेष दर्जा को लेकर अपनी चिंता ज़ाहिर करने के लिए जम्मू की खामोश बहुमत को सलाम किया जाना चाहिए. ■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.
feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक फैसले की पद्धति को खत्म कर दिया है

उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने कई सारी मुश्किलें हैं, जिसमें एक बड़ी मुश्किल नोटबंदी है. नोटबंदी ने सरकार की तैयारियों का मजाक उड़ा कर रख दिया है. देश में नोटों की साइज को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ कि यह कैसी तैयारी थी कि सारी की सारी मशीनें दो महीने तक लोगों को परेशानी में डाले रहीं. देश में एक लाख 30 हजार बैंकों की शाखाएं हैं और दो लाख 60 हजार एटीएम मशीनें हैं. ये एटीएम मशीनें दो महीने तक बिल्कुल काम नहीं कर पाई क्योंकि नोटों की साइज को बहुत बेअक्ली के साथ बदला गया. इसके बाद, पैसे देने के लिए तीन लाख 90 हजार शाखाओं और एटीएम की जगह सिर्फ एक लाख 30 हजार शाखाएं और एटीएम ही काम कर रहे थे. यही कारण था जिसकी वजह से जनता त्राहि-त्राहि कर उठी. लोगों को दूसरी परेशानी इससे हुई कि आपने पैसे निकालने की लिमिट बना दी. तीसरी गलती सरकार से ये हुई कि उसने रुपये बदलने के लिए दो महीने का समय दे दिया. इससे कालाधन खत्म नहीं हुआ. कालाधन खत्म होता, अगर सरकार यह कह देती कि एक हफ्ते के भीतर जिसको जितना पैसा बदलना है, बदल ले. उन्होंने इसकी जगह दो महीने का टाइम दे दिया और एक आदमी को दो लाख रुपये तक बदलने की छूट दे दी. देश में कुछ ही समय पहले आपने 40 करोड़ जनधन एकाउंट खुलवा दिए. इन सारे अकाउंट्स में दो लाख की अनुमति के हिसाब से पैसे पड़े और यही हुआ कि सबसे पहले कालाधन इन एकाउंट्स में जमा हुआ. नकली नोट इन अकाउंट्स में जमा हुए और सरकार का कालेधन के खिलाफ अभियान का अभिप्राय यहीं पर समाप्त हो गया. हमारे देश की व्यवस्था ये है कि अगर कोई विधायक या सांसद अपने क्षेत्र में पैसे बदलवाना चाहे, तो उसके लिए पंचायतों के सदस्य या ग्राम प्रधान सबसे अच्छा रास्ता हैं. उन्हें कितने भी पैसे दीजिए, वो अपने नीचे के लोगों के जनधन एकाउंट में उन पैसों को एडजस्ट कर उन पैसों को वापस भी निकाल सकते हैं. कह सकते हैं कि देश में पहली बार सामूहिक समाजवाद जैसा आया. जिनके पास कालाधन था, उन लोगों ने 25 प्रतिशत देकर 75 प्रतिशत पैसा वापस पा लिया. उनके पुराने नोट बदल गये, उनका कालाधन बदल गया और तथाकथित आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने वाला पैसा भी बदल गया. कह सकते हैं कि पहली बार ऊपर का पैसा नीचे तक बंटा. जिसके पास सौ करोड़ थे, उसने 25 करोड़ नीचे वालों को दे दिए और 75 करोड़ अपने वापस ले लिए. अब इस चीज में सरकार को कुछ नहीं मिला. हुआ ये कि जितना सरकार ने पैसा कानूनी तौर पर छापा था और बाजार में फेंका था, उससे ज्यादा बैंकों के पास वापस आ गया. चूंकि कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बैंक उस पैसे को लेते चले गए. अगर सरकार ने थोड़ा दिमाग लगाया होता, तो इस स्कीम को थोड़े दिनों के लिए लागू करते, नोटों का साइज नहीं बदलते, सारे एटीएम चालू रखते, अगर संभव होता तो वे देश में लॉकरों पर नजर डालते. देश के बड़े लोगों का सारा कालाधन बैंक लॉकर्स में है. देश में कुल 26 लाख लॉकर्स हैं. सवा सौ करोड़ लोगों को लाइन में लगाने की जगह इन 26 लाख लॉकरों पर अगर मोदी सरकार ध्यान देती तो शायद सही रूप में कालाधन वापस आ सकता था. सरकार ये फैसला करती कि बैंक मैनेजर, जिसका लॉकर है वो, समाज का एक प्रबुद्ध व्यक्ति, पुलिस का आदमी इन सब की उपस्थिति में लॉकर खोला जाएगा. तब वो लॉकर खुलता, पंचनामा बनता, लोग लॉकरों से अपना सामान निकाल ले जाते. इससे सरकार को पता चल जाता

> मोदी जी के चुनाव जीतने के बाद तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अचानक गिर गये, जिससे सरकार को आठ लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्रतिवर्ष अलग से मिल रहा है. चाणक्य ने कहा था कि जनता से टैक्स इस तरह लेना चाहिए, जैसे मधुमक्खी फूलों से रस लेती है, न कि इस तरह कि उसे पेरकर बिल्कुल चूस लिया जाए. सरकार ने दूसरा रुख अपनाया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिरे, लेकिन भारत में नहीं गिरे. हमने उसकी जगह जनता पर टैक्स की भरमार कर दी. अगर खाना खाने जाएं तो 30 प्रतिशत टैक्स और मजे की चीज यह कि जो जनता इतना टैक्स दे रही है,

कि किस लॉकर से क्या निकला है? इसका परिणाम ये होता कि लोग बहुत सारे लॉकर तो खोलने ही नहीं आते, जिन्होंने बेनामी लॉकर ले रखे हैं, क्योंकि इसमें उनके रुपये, कागज, हीरे व जवाहरात रखे हैं. इससे सरकार को सचमुच कालाधन मिल सकता था. सरकार की नीयत पर तो सवाल नहीं उठाते, लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार की योजना सही नहीं थी. इस योजना के कारण देश अभी तक उबर नहीं पाया है. एक तरीके से छह महीने तक की संपूर्ण विकास दर उलझ गयी है और कह सकते हैं कि तीन महीने की तो जीडीपी बिगड़ गई. पुराने नोट जितने चलन में थे, उससे ज्यादा आ गए और नये नोटों को छापने का जो खर्चा पड़ा, वो अलग. सरकार को बिना टेंडर के नोट छपवाने पड़े और उन्हीं लोगों से नोट छपवाने पड़े जिन पर कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नकली नोटों को छापने का इल्जाम लगा था.

दूसरी एक बात समझ में नहीं आती है. मोदी जी के चुनाव जीतने के बाद तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अचानक गिर गये, जिससे सरकार को आठ लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्रतिवर्ष अलग से मिल रहा है. चाणक्य ने कहा था कि जनता से टैक्स इस तरह लेना चाहिए, जैसे मधुमक्खी फूलों से रस लेती है, न कि इस तरह कि उसे पेरकर बिल्कुल चूस लिया जाए. सरकार ने दूसरा रुख अपनाया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिरे, लेकिन भारत में नहीं गिरे. हमने उसकी जगह जनता पर टैक्स की भरमार कर दी. अगर खाना खाने जाएं तो 30 प्रतिशत टैक्स और मजे की चीज यह कि जो जनता इतना टैक्स दे रही है, उसे हम चोर कहने लगे, सरकार चोर कहने लगी. अब सवाल यह है कि सरकार को पिछली सरकारों के मुकाबले तीन साल में 20 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिले. ये 20 लाख करोड़ रुपये आखिर गए कहां? इनका सरकार ने क्या कोई हिसाब, किसी को दिया है? बस हर जगह टैक्स लगा रहे हैं. कीमत हर जगह बढ़ा रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो या तेल. बिना सोचे-समझे लोगों से पैसा निकालने की योजनाएं बनाई जा रही हैं. आप अगर ये कहें कि पैसा कहां गया, खुद सरकार को नहीं पता तो अतिश्योक्ति नहीं होगी. इतना टैक्स जनता दे रही है, इतना पैसा दे रही है, बढ़े हुए तेल से पैसा आ रहा है, कम कीमत की तेल से पैसा आ रहा है, फिर भी जनता को चोर बताया जा रहा है. टैक्स नहीं घटाया जा रहा है. इससे जनता में रोष है. जो टैक्स दे रहे हैं, उनमें रोष है.

पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में कांग्रेस के जितने भी निकाले हुए लोग थे, उनको अपनी पार्टी में ले लिया और अपनी पार्टी में जो 30-40 साल से काम कर रहे थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कोई भाव नहीं दिया. इतना ही नहीं, एक नई नीति बना दी कि जो हमारी बात नहीं माने, वो नेता पार्टी विरोधी है. जितने देश में वरिष्ठ नेता थे, उन पर अघोषित छाप लग गयी कि ये सब पार्टी विरोधी हैं. भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका संघ के तरीके से पहली बार अलग हुआ. संघ की पद्धति है कि वो शाखा के कार्यकर्ताओं की बात ऊपर बताता है, ऊपर वाला और ऊपर बताता है, ऊपर वाला और ऊपर बताता है. शायद यही वजह है कि किसी विषय पर देश के किसी हिस्से में संघ के स्वयंसेवकों से लेकर सरकार्यवाह तक एक ही उत्तर सुनने को मिलता है. मोदी जी ने इस सामूहिक या नीचे के फैसले की पद्धति को समाप्त कर दिया. वे अपने मन के हिसाब से फैसले ले रहे हैं, पार्टी के हिसाब से नहीं. दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का व्यवहार पार्टी के बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और शायद इसीलिए पार्टी के सांसद बहुत ज्यादा नाराज हैं.

इस नाराजगी और बिहार की हार की वजह से ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र लगभग समाप्त हो गया है. ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से बात करने पर पता चलता है.

> क्या गोवा और उत्तराखंड की जीत भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में दोबारा जीतने के लिए संजीवनी दे पाएगी. ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में सबसे बड़ा सवाल है. अब उत्तराखंड और गोवा में संघ के लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, जिनके खिलाफ मैं सारी जिंदगी रहा यानी कांग्रेस और मैं जितवा भी कांग्रेस के लोगों को रहा हूं. संघ के लोगों के मन का यह संदेह उनको पूरी तरह से चुनाव प्रचार करने से रोक रहा है. संघ पूरी तौर पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे रहा है. हालांकि संघ के एक पुराने विचारक का कहना है कि संघ हमेशा इसी तरीके से भोजन पर चर्चा करता है.

उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, तब यह पार्टी के लिए शुभ होगा. हो सकता है तब भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र शायद पुनः स्थापित हो और प्रधानमंत्री अपने साथियों, सहयोगियों व पार्टी के वरिष्ठ लोगों से राय मशविरा करना पुनः शुरू कर दें. उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव था, तब भारतीय जनता पार्टी को लगभग 42 प्रतिशत वोट मिले थे. अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को 42 प्रतिशत वोट मिलेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी के सात प्रतिशत वोट भी कम हुए तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी नहीं रह पाएगी.

मोदी जी के प्रति गुस्से का कारण समझना चाहिए. मोदी जी की बुनियादी कान्स्टीट्यूएंसी थी मध्यम वर्ग या कहें बनिया. ये लोग 50 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का समर्थन कर रहे थे, जो इस नोटबंदी के फैसले से सबसे ज्यादा आहत और नुकसान में हैं. आंकड़ों में तो मोदी जी जरूर ये दावा करेंगे कि टैक्स क्लेक्शन बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि भारत की तथाकथित बैंक व्यवस्था से ज्यादा व्यापार, जिसे हम दो नंबर का कहते हैं, उसमें होता रहा है. भारत में रोजगार का एक सबसे बड़ा साधन छोटे दुकानदार, छोटे व्यापार के जरिये उपलब्ध हो रहा था. कम से कम हर दुकान पर दो से तीन लोग काम करते थे. हर व्यापार में 15 से 20 लोग काम करते थे और उन्हें हर महीने नियमित रूप से वेतन मिलता था.

अब स्थिति ये है कि हम विदेशों को जबरदस्ती पैसे दे रहे हैं. पहले उपभोक्ता 100 रुपये दुकानदार को देता था, तो उसे 100 रुपये ही मिलते थे और उपभोक्ता को सामान भी 100 रुपये का ही मिलता था. संघ अब तक स्वराज और स्वदेशी की बात करता रहा. देश का पैसा देश में रहे, लेकिन एक फैसले से अचानक हमारे देश का पैसा विदेश में जाना शुरू हो गया. आज स्थिति ये है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सरकार कराना चाहती है, ये सभी क्रेडिट कार्ड विदेशी हैं. 100 रुपये उपभोक्ता की जेब से तो चले जाते हैं, लेकिन दुकानदार को सौ रुपये नहीं मिलते, 98 रुपये मिलते हैं. उसमें से दो रुपये विदेश चले जाते हैं. ये संघ की उस भावना के विपरीत है, जिसे संघ ने अपने स्वयंसेवकों को पिछले 50-60 साल से समझाया है. देशी, हिन्दुस्तान, देश का पैसा देश में रहे, पर सरकार के एक फैसले ने क्रेडिट कार्ड कंपनियों के जरिए प्रति 100 रुपये में दो रुपये विदेशों को भेजना शुरू कर दिया.

एक मोटे अनुमान के अनुसार, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार ये उधार की जीत होगी. अगर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से लोगों को नहीं तोड़ा होता, तो उत्तराखंड में 90 प्रतिशत जीत की संभावनाएं समाप्त हो जातीं. भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों का मानना है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और वहां या तो कांग्रेस या आम आदमी की सरकार बनेगी. उनका ये भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में संभवतः अखिलेश यादव और उनके साथी बाजी मारने जा रहे हैं. बीजेपी की संभावना गोवा में भी है, लेकिन क्या गोवा और उत्तराखंड की जीत भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में दोबारा जीतने के लिए संजीवनी दे पाएगी. ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में सबसे बड़ा सवाल है. अब उत्तराखंड और गोवा में संघ के लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, जिनके खिलाफ मैं सारी जिंदगी रहा यानी कांग्रेस और मैं जितवा भी कांग्रेस के लोगों को रहा हूं. संघ के लोगों के मन का यह संदेह उनको पूरी तरह से चुनाव प्रचार करने से रोक रहा है. संघ पूरी तौर पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे रहा है. हालांकि संघ के एक पुराने विचारक का कहना है कि संघ हमेशा इसी तरीके से भोजन पर चर्चा करता है. अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गयी, तो वे ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे कार्यकर्ताओं ने जी-जान लगाकर जिताया और अगर भारतीय जनता पार्टी हार गयी तो संघ के नेता सारी चर्चा करने के बाद ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की इन-इन नीतियों की वजह से हमने उसका साथ नहीं दिया. पर प्रश्न, संघ के साथ देने या नहीं देने का नहीं है, प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी की गलतियां क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा देगी या नुकसान देगी या जिन्हें समीक्षक भारतीय जनता पार्टी की गलतियां मानते हैं, वही कारण भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनकर उभरेंगे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सर पर जीत का सेहरा बांधेंगे. ■

editor@chauthiduniya.com

एसएफसी गोदामों से 21 करोड़ का अनाज घोटाला

सुनील सौरभ

ग़रीबों का 70 हज़ार क्विंटल अनाज खा गए भ्रष्टाचारी

दो सहायक गोदाम प्रबंधकों पर प्राथमिकी दर्ज

दक्षिण बिहार की राजनीतिक राजधानी और झारखंड की सीमा से सटे धार्मिक ऐतिहासिक धरोहरों को अपने दामन में समेटे नक्सल प्रभावित गया जिले में वैसे तो कोई सरकारी अधिकारी आना नहीं चाहता है, लेकिन ये भी सच है कि एक बार जो यहां आ गया, वह यहां से जाना भी नहीं चाहता है. यह स्थिति अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक की है. चौबीस प्रखंडों वाले इस जिले में आधे से अधिक प्रखंड नक्सल प्रभावित हैं. इसके बावजूद सरकारी कर्मी किसी भी सरकारी योजना की लूट, घोटाला और भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आते हैं. गया जिले के अधिकतर प्रखंडों के ग्रामीण विशेषकर दलित-महादलित वर्ग आज भी कम पढ़ा-लिखा और सीधा-साधा है. यही कारण है कि सरकारी कर्मी ऐसे लोगों को बरगलाकर उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ खुद उठाते हैं और घोटाला कर समूची राशि डकार जाते हैं. ऐसा ही एक मामला गया जिले के चार प्रखंडों में पकड़ा गया है, जिसमें बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 21 करोड़ राशि के 70 हजार क्विंटल अनाज का गबन किया गया है. इस मामले में बिहार राज्य खाद्य निगम के कई सहायक गोदाम प्रबंधकों पर संबंधित थानों में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बिहार खाद्य निगम महकमे में हड़कंप मच गया है. वहीं इलाके के समाजसेवियों का कहना है कि अगर एसएफसी की विजिलेंस टीम द्वारा गया जिले के एसएफसी गोदामों की सही तरीके से जांच की जाए, तो यह घोटाला अरबों तक पहुंच सकता है. 70 हजार क्विंटल यह अनाज गरीबों के बीच मुफ्त व रियायती दरों पर वितरण के लिए जन वितरण की दुकानों में भेजा जाना था.

इस मामले में गया जिले के कोंच व टिकारी प्रखंड के बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 30 हजार क्विंटल अनाज गायब होने का पता चला. एसएफसी की निगरानी टीम ने जब इसकी जांच की, तो अनाज के गबन की सच्चाई सामने आ गई. यह अनाज वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए था. जांच के दौरान कोंच प्रखंड के गोदाम में करीब दो करोड़ 36 लाख 19 हजार रुपए का 185 क्विंटल अरवा चावल, आठ हजार 493 क्विंटल उसना चावल और 291 क्विंटल गेहूं जब्त किया गया. इसी प्रकार टिकारी थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में छह करोड़ 45 लाख 60 हजार रुपए के अनाज गबन की बात सामने आई है. कोंच व टिकारी गोदाम से गबन किये गये अनाज के मामले में अवकाश प्राप्त सहायक गोदाम प्रबंधक गुमेश्वर शर्मा पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. वे दोनों गोदाम के प्रभारी थे. एफआईआर बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक शरद कुमार झा ने दर्ज कराया है. इससे पूर्व गोदामों में अनाज स्टॉक में अनियमितता की शिकायत पर इसकी विशेष जांच के लिए गया के जिला पदाधिकारी कुमार रवि ने भी एडीएम की अध्यक्षता में स्पेशल टीम का गठन किया था. यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि झारखंड की सीमा से लगे गया जिले के इमामगंज-डुमरिया प्रखंडों में 40 हजार क्विंटल अनाज के गबन का मामला सामने आ गया. विभागीय विजिलेंस की टीम ने जब जांच की तो डुमरिया प्रखंड के एसएफसी गोदाम से छह करोड़ रुपए के 22 हजार क्विंटल गेहूं तथा 10 हजार क्विंटल चावल के गोलमाल किए जाने का पता चला. वहीं इमामगंज प्रखंड के गोदाम से करीब पांच करोड़ रुपए के 9 हजार क्विंटल गेहूं व 9 हजार क्विंटल चावल का गबन किया गया. इस मामले में दोनों गोदामों के प्रभारी रहे प्रमोद कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. 70 हजार क्विंटल अनाज के गबन के मामले की जांच चल ही रही थी कि तभी 30 जनवरी 2017 को जीटी रोड पर डोभी थाना क्षेत्र के सूर्यमंडल के निकट गेहूं से लदा एक ट्रक पकड़ा गया. यह ट्रक झारखंड की ओर जा रहा था. इस ट्रक पर बिहार राज्य खाद्य निगम की छाप वाले बोरे में 203 क्विंटल गेहूं लदा था. इस अनाज को कालाबाजारी के लिए झारखंड ले जाया जा रहा था. यह गेहूं कैमूर जिले के मोहनिया के रवि गल्ला उद्योग नामक फर्म से लादी गयी थी. इस मामले में ट्रक चालक मो. जान को गिरफ्तार कर

झारखंड की सीमा से लगे गया जिले के इमामगंज-डुमरिया प्रखंडों में 40 हजार क्विंटल अनाज के गबन का मामला सामने आया है. विभागीय विजिलेंस की टीम ने जब जांच की तो डुमरिया प्रखंड के एसएफसी गोदाम से छह करोड़ रुपए के 22 हजार क्विंटल गेहूं तथा 10 हजार क्विंटल चावल के गोलमाल किए जाने का पता चला.

अनाज जब्त कर लिया गया.

इस संबंध में जानकारों का कहना है कि गया जिले के 24 प्रखंडों में जन वितरण की दुकानों में गरीबों में वितरित करने के लिए आवंटित अनाजों का अधिकतर हिस्सा कालाबाजार में चला जाता है. सभी अनाज झारखंड ले जाकर बेच दिया जाता है. जानकार तो यह भी बताते हैं कि पीडीएस के अनाज के गबन मामले में एसएफसी के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत रहती है.■

feedback@chauthiduniya.com

कैमूरांचल के वनवासी ख़ुद कर रहे सड़क का निर्माण

सरकार हुई फेल तो वनवासियों ने उठाया फावड़ा

सड़क निर्माण के लिए इन गांवों के निवासियों ने कई वर्षों तक राज्य सरकार को आवेदन भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अधिकारियों का रवैया देखकर ग्रामीणों ने स्वयं फावड़ा और कुदाल उठाने का फैसला किया. इतना ही नहीं, इनसे प्रेरित होकर नागाटोली, बभनतलाब आदि गांवों के युवाओं ने रोहतास गढ़ किला की तरफ जाने के लिए बौलिया से फांसीघर के बीच तीन किलोमीटर पहाड़ की कटाई कर रास्ता बनाने का संकल्प लिया. यहां पहुंचने के लिए पहले तीस किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था. हालांकि अभी इस सड़क का निर्माण रुका हुआ है. इस सड़क के बन जाने पर रोहतास गढ़ किला पर बाइक या कार से पहुंचा जा सकता है. यहां के निवासियों ने भी सड़क निर्माण के लिए सरकार को कई बार आवेदन दिया था. हालांकि दोनों सड़कें कच्चे निर्माण वाली ही हैं क्योंकि ग्रामीणों के पास न तो उतने संसाधन हैं और न ही पैसा.

ममता चौहान

feedback@chauthiduniya.com

धर्म और इतिहास के अनगिनत धरोहरों को अपने में समेटे कैमूरांचल की धरती ने अब अलग तरह की अंगड़ाई ली है. दुर्गम पहाड़ी और जंगलों में बसे गांवों के लोग सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अब स्वयं उठ खड़े हुए हैं. कहीं आपसी सहयोग से सड़क का निर्माण हो रहा है तो कहीं पाठशाला चलाई जा रही है. सरकार कुछ करे या नहीं, लेकिन ये वनवासी अब जागरूक हो गए हैं.

रोहतास जिला में चेनारी प्रखंड से लेकर नौहट्टा प्रखंड के अंतिम छोर और रोहतास के अंतिम गांव डुमरखोह के बीच चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने का बीड़ा अब पहाड़ व तलहटी पर बसे वनवासियों ने उठा लिया है. पौराणिक धर्म स्थली गुप्ता धाम जाने के लिए लोग सदियों से कैमूर पहाड़ी में घनघोर जंगलों के बीच से होकर वहां पहुंचते थे. यहां पहुंचने का एक और रास्ता पचौरा घाट से भी होकर जाता है. अगर दुर्गम पहाड़ी पर चार किलोमीटर का रास्ता बन जाए तो चालीस किलोमीटर की दूरी खत्म हो जाएगी. इस सोच के साथ पहाड़ी पर बसे औरइयां, भुड़कुडा, जारादाग और उरदाग गांवों के लोग आगे आए. यहां के निवासी चालीस किलोमीटर की लंबी यात्रा वाहनों से तय कर अपने गांव पहुंचते थे. फिर क्या था, इन गांवों के सैकड़ों युवा हाथ में कुदाल और फावड़ा लेकर पचौरा घाट से लेकर औरइयां गांव की चार किलोमीटर लंबी सड़क बनाने निकल पड़े. इसे बनाने में कई मुसीबतें भी आईं. कहीं कठोर चट्टानों को तोड़ा गया तो कहीं मिट्टी के ढेर हटाने पड़े. महाशिवरात्रि में गुप्ता धाम में लगने वाले मेले से पहले इस सड़क के निर्माण का संकल्प लेकर सैकड़ों युवा पत्थरों का सीना चीरने निकल पड़े. शाम तक इनका एक ही संकल्प होता था पत्थरों को काटकर समतल करना. अब यह सड़क लगभग तैयार हो चुकी है.

सड़क निर्माण के लिए इन गांवों के निवासियों ने कई वर्षों तक राज्य सरकार को आवेदन भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी. अधिकारियों का रवैया देखकर ग्रामीणों ने स्वयं फावड़ा और कुदाल उठाने का फैसला किया. इतना ही नहीं, इनसे प्रेरित होकर नागाटोली, बभनतलाब आदि गांवों के युवाओं ने रोहतास गढ़ किला की तरफ जाने के लिए बौलिया से फांसीघर के बीच तीन किलोमीटर पहाड़ की कटाई कर रास्ता बनाने का संकल्प लिया. यहां पहुंचने के लिए पहले तीस किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था. हालांकि अभी इस सड़क का निर्माण रुका हुआ है. इस सड़क के बन जाने पर रोहतास गढ़ किला पर बाइक या कार से पहुंचा जा सकता है. यहां के निवासियों ने भी सड़क निर्माण के लिए सरकार को कई बार आवेदन दिया था. हालांकि दोनों सड़कें कच्चे निर्माण वाली ही हैं क्योंकि ग्रामीणों के पास न तो उतने संसाधन हैं और न ही पैसा. परंतु इन ग्रामीणों के अदम्य साहस से अधिकारियों को यह संदेश जरूर मिला है कि उनकी काहिली और लचर रवैया ग्रामीणों के विकास का रास्ता नहीं रोक सकती है. सड़क निर्माण की पहल से ग्रामीणों को यह उम्मीद बंधी है कि भविष्य में यहां पक्की सड़कों का निर्माण भी जरूर होगा. शुरू में युवा वन विभाग के अधिकारियों के डर से छिप-छिपकर पहाड़ पर सड़क निर्माण में लगे थे. उन्हें डर था कि अधिकारी अकारण उन्हें किसी मामले में फंसा सकते हैं. इससे पहले भी वन विभाग के अधिकारियों के अड़ंगा लगाने से कैमूरांचल में कई विकास कार्य रुके पड़े हैं.

सड़क निर्माण की पहल से ग्रामीणों को यह उम्मीद बंधी है कि भविष्य में यहां पक्की सड़कों का निर्माण भी जरूर होगा. शुरू में युवा वन विभाग के अधिकारियों के डर से छिप-छिपकर पहाड़ पर सड़क निर्माण में लगे थे. उन्हें डर था कि अधिकारी अकारण उन्हें किसी मामले में फंसा सकते हैं. इससे पहले भी वन विभाग के अधिकारियों के अड़ंगा लगाने से कैमूरांचल में कई विकास कार्य रुके पड़े हैं.

इन प्रयासों से इतर जिले के दक्षिणी अंतिम छोर पर नक्सली इलाकों में युवाओं का एक भागीरथ प्रयास और दिखा. यहां कभी नक्सली जनअदालत लगाकर दोषियों को सजा देते थे. वहीं अब अब एक पेड़ की छांव के नीचे डुमरखोह गांव की प्रभा बहू की पाठशाला चलती है. इस गांव से तीन किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश और चार किलोमीटर की दूरी पर झारखंड राज्य की सीमा शुरू होती है. इस गांव के बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए छह किलोमीटर पैदल चलकर बेलदुरिया तक जाते थे. अब प्रभा के निजी प्रयास से इस गांव में स्कूल खुल गया है, जहां रोज पचास-साठ बच्चे पढ़ने आते हैं. इन विकास कार्यों के अलावा कैमूरांचल की धरती पर रोहतास गढ़ महोत्सव भी आयोजित किया जा सकता है. हालांकि अभी तक सरकारी स्तर पर उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है. हर साल फरवरी महीने में रोहतासगढ़ किले पर तीन दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव वनवासी समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है. उनका मानना है कि रोहतासगढ़ किला ही उनका असली तीर्थ है. यहां करम के तीन वृक्षों की पूजा के साथ इस महोत्सव की शुरुआत होती है. इस महोत्सव में देश के दक्षिणी हिस्से आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड आदि कई राज्यों से वनवासी यहां आते हैं. अगर रोहतासगढ़ किले पर आयोजित वनवासियों के इस महोत्सव पर सरकार ध्यान दे, तो इससे पर्यटन उद्योग और स्थानीय बाजार को भी लाभ होगा.

वनवासी कई अर्से से राजगीर महोत्सव, देव महोत्सव, मुंडेश्वरी महोत्सव आदि की तर्ज पर रोहतागढ़ महोत्सव मनाने की मांग कर रहे हैं. वनवासी इस महोत्सव के लिए स्वयं पहल कर इसे आयोजित करते हैं. अगर सरकार इस महोत्सव पर ध्यान दे, तो यह राजस्व उगाही का एक बड़ा केंद्र हो सकता है. इस क्षेत्र के विधायक ललन पासवान बताते हैं कि उनके अथक प्रयासों से इस क्षेत्र में विद्युतीकरण के कार्य शुरू हुए हैं. विधानसभा में सड़क निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों की लगातार मांग किए जाने के बाद भी सरकार का ध्यान इन क्षेत्रों पर नहीं है. उन्होंने कहा कि कैमूरांचल में अधौरा से लेकर यदुनाथपुर के बीच मुंडेश्वरी धाम, गुप्ता धाम, शेरगढ़ किला, तारांचंडी धाम, तुतला भवानी, रोहतासगढ़ किला, रोहितेश्वर शिव आदि स्थलों की एक पर्यटन सर्किट तैयार हो जाए, तो यह भूभाग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से कतई कम नहीं, परंतु ऐसा करने के लिए सरकार के पास दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए. वनवासियों द्वारा कराये गये विकास कार्यों पर विधायक ने कहा कि मैं उनके साथ खड़ा हूं. जिस तरह की सहायता होगी, जरूर की जाएगी. वहीं, समाजसेवी डॉ. एसएन आजाद का कहना है कि कैमूरांचल में जितना विकास होना चाहिए, उसका पांच फीसदी भी नहीं हो पाया है. अगर पचास फीसदी भी काम पूरा हो जाए तो यह जगह देश के दर्शनीय स्थलों में से एक होगा.■

बीएसएससी घोटाले के सूत्रधारों में उच्चाधिकारी से लेकर राजनेता भी शामिल

जांच की आंच नेताओं तक

चार चरणों में आयोजित होने वाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग के क्लर्क संवर्ग के दूसरे चरण की परीक्षा 5 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था. इस परीक्षा का प्रथम चरण 29 जनवरी को आयोजित किया गया था. पेपर लीक होने की सूचना मिलने पर भड़के परीक्षार्थियों ने आयोग के सचिव की पिटाई कर दी. सैकड़ों छात्रों ने 6 फरवरी को बीएसएससी के दफ्तर पर हमला बोल दिया. छात्रों के गुस्से को देखते हुए आयोग के दफ्तर के पास पुलिस बल का इंतजाम किया गया था, लेकिन छात्रों ने पुलिस के साथ झड़प होने के बाद आयोग का गेट तोड़ दिया.

राकेश कुमार

जब कानून के रक्षक ही गुनहगारों में शामिल हो जाएं, तो फिर कानून-व्यवस्था की मर्यादा तो तार-तार होती ही है, साथ ही जनता का विश्वास भी खो देती है. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा घोटाले में गिरफ्तार आयोग के सचिव परमेश्वर राम ने खुलासा किया है कि इसमें 36 राजनेताओं के साथ-साथ 9 आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं. छपरा जिले के निवासी और अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले अधिकारी परमेश्वर राम को अपने आकाओं पर भरोसा था. पहले तो उन्होंने पुलिस पर रौब डालने का प्रयास किया, लेकिन उनके कड़े रुख को भांपकर पूछताछ में सहयोग करने पर राजी हुए. परमेश्वर के खुलासे ने सबको चौंका दिया. उन्होंने बताया कि आयोग ने विगत पांच साल में हुई नियुक्तियों में भयंकर गड़बड़ियां की हैं. राजनेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों व नजदीकी लोगों की बहाली के लिए लाखों रुपए वसूले गए. परमेश्वर राम ने पुलिस अधिकारियों से कहा, 'मैं तो इस स्कैम का एक अदना सा खिलाड़ी हूं. हिम्मत है तो किंगपिन को पकड़िए, जिसके इशारे पर ये सब हो रहा है.'

चार चरणों में आयोजित होने वाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग के क्लर्क संवर्ग के दूसरे चरण की परीक्षा 5 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था. इस परीक्षा का प्रथम चरण 29 जनवरी को आयोजित किया गया था. पेपर लीक होने की सूचना मिलने पर भड़के परीक्षार्थियों ने आयोग के सचिव की पिटाई कर दी. सैकड़ों छात्रों ने 6 फरवरी को बीएसएससी के दफ्तर पर हमला बोल दिया. छात्रों के गुस्से को देखते हुए आयोग के दफ्तर के पास पुलिस बल का इंतजाम किया गया था, लेकिन छात्रों ने पुलिस के साथ झड़प होने के बाद आयोग का गेट तोड़ दिया. झड़प में छात्रों को मामूली चोटें भी आईं. इसके बाद छात्रों ने एसएससी के सचिव परमेश्वर राम की जमकर पिटाई कर दी. आयोग के बाहर बहुत देर तक छात्र नारेबाजी करते रहे. इससे पहले एसएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने पर आयोग के अधिकारियों ने लीपापोती का प्रयास किया था. उन्होंने इसे अफवाह बताकर पेपर लीक होने से ही इंकार कर दिया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भनक लगते ही मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया था. इसके बाद पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज के नेतृत्व में जांच दल का गठन किया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 फरवरी को इस परीक्षा के रद्द किए जाने की घोषणा कर दी थी. इस मामले में एसआईटी ने परमेश्वर राम समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया है. सचिव के आवास पर 7 फरवरी की देर रात एसआईटी की टीम ने छापेमारी की. इस दौरान एसआईटी को कई महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे, जिसकी जांच जारी है. परमेश्वर समेत सभी लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की. परमेश्वर राम की नियुक्ति पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने की थी. राज्य के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. अशोक चौधरी ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि उनके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार ने भी पूछताछ में परीक्षा एवं नियुक्ति में धांधली की बात स्वीकार की है. उन्होंने बताया कि उनसे कई मंत्रियों व अधिकारियों ने पैरवी के लिए संपर्क किया था. बहरहाल, एसआईटी ने अबतक 30 लोगों को इस घोटाले में पकड़ा है, जिसमें एवीएन स्कूल के संस्थापक रामाशीष सिंह यादव भी शामिल हैं. पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आरोप है कि यादव के तार लालू प्रसाद यादव से जुड़े हैं. लालू प्रसाद यादव ने मोदी के आरोपों को चुनौती दी है. जानकारी के मुताबिक रामाशीष सिंह यादव की नियुक्ति साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग में तीन दशक पहले तत्कालीन मंत्री डॉ. विजय सिंह की सिफारिश पर हुई थी. फिर वे लालू प्रसाद यादव के छोटे साले के संपर्क में आकर शराब के धंधे से जुड़े और करोड़ों की संपत्ति अर्जित की.

सूत्र बताते हैं कि आयोग में अपने उम्मीदवारों को सफल कराने की लंबी लिस्ट एक बड़े अधिकारी ने थमाई थी. मामले में कुख्यात रंजीत डॉन की संलिप्तता भी बताई जा रही है. पुलिस सूत्रों की मानें तो इस घोटाले के तार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से जुड़े होने की आशंका है. मैरिट घोटाले में गिरफ्तार लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी उषा सिन्हा भी मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा से संबंध रखते हैं. उषा सिन्हा नालंदा के हिलसा से जनता दल यू की विधायक रह चुकी हैं. उन पर कटाक्ष करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पिछले दिनों एक सभा में कहा था, 'मुझे अपने लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि कौन चोर है और कौन साधु. सूत्रों की मानें तो, 'साहब को जानकारी थी कि कई घोटालों का मास्टरमाइंड रंजीत डॉन, 3 राजनेता और एक रिटायर्ड पुलिस अफसर एक साथ मिले हुए हैं.'

तीसरे दर्जे के कर्मचारियों की बहाली के लिए बनाया गया बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपनी घोर लापरवाही की वजह से हमेशा विवादों में घिरा रहा है. आंकड़ों पर अगर गौर करें तो ऐसी शायद ही कोई परीक्षा हुई हो, जिसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई हो. सितंबर 2014 से अभी तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जितनी परीक्षाएं हुई हैं, सभी से जुड़े मामले कोर्ट में चल रहे हैं. बात चाहे एएनएम परीक्षा, जीएनएम, स्टेनोग्राफर, सीनियर साइंटिस्ट, जेल वार्डेन और सीआई की हो, सभी परीक्षाओं का मामला कोर्ट तक पहुंचा है. यही वजह है कि राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं हो पाती है. इन सब में सबसे ज्यादा परीक्षार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ती है. अभी तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही से पीटी का रिजल्ट, मुख्य परीक्षा, आरक्षण में गड़बड़ी, मेधा सूची में हेराफेरी जैसी शिकायतें कोर्ट पहुंची हैं. हाल में बीएसएससी की परीक्षा के पर्चा लीक मामले में एक बीएसएससी के कर्मी की संलिप्तता देखी गई है. इस मामले में आयोग के सचिव परमेश्वर राम ने कहा है कि उन्हें जिला प्रशासन या किसी अन्य एजेंसी से ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है, जिसके आधार पर जांच की जाए. मीडिया में छपी खबरों पर जांच नहीं हो सकती है.■

feedback@chauthiduniya.com

नशाबंदी : बंद करने होंगे कई छेद

वाल्मीकि कुमार

बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी सीमाक्षेत्र के इलाकों में शराब का अवैध कारोबार जारी है. सवाल यह है कि सामाजिक जागरूकता, प्रशासनिक सक्रियता व सख्त कानूनी पहरे के बावजूद नशे के कारोबार पर विराम क्यों नहीं लग रहा है? भारत-नेपाल की खुली सीमा कारोबारियों के लिए बेहतर व सुगम मार्ग साबित हो रही है? बिहार-झारखंड समेत अन्य राज्यों का रेल व परिवहन मार्ग इसमें मददगार साबित हो रहा है. क्या उंची पहुंच के कारण अधिकारी शराब के अवैध कारोबारियों पर हाथ नहीं डाल रहे हैं या फिर अकूत कमाई की नियत से खुद भागीदार बन गए हैं. इस खेल को समझने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर स्थित पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल व गोपालगंज समेत अन्य स्थानों की भौगोलिक संरचना एवं प्रशासनिक तैयारियों को भी ध्यान में रखना होगा.

नशाबंदी के बाद भी बिहार में कई जगहों से शराब बरामद होना इस बात की ओर इशारा करता है कि शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है. इसका मतलब यह है कि सरकारी तंत्र अब तक इसे पूर्ण रूप से रोकने में विफल रहा है. भारत-नेपाल सीमा से सटे बिहार के कई जिलों में कारोबारी खुली सीमा का फायदा उठा रहे हैं. पूर्वी चंपारण जिले के लोग बताते हैं कि नेपाल से प्रवाहित होकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली लालबकैया नदी कारोबारियों के लिए सुगम मार्ग बनी है. आस-पास के क्षेत्रों में नाव के सहारे प्रतिदिन भारी मात्रा में शराब की खेप पहुंचाई जाती है और उसे निर्धारित ठिकाने तक ले जाया जाता है. शिवहर जिले में सीतामढ़ी के बैरगनिया से सड़क मार्ग से नेपाल में बने शराब को आराम से पहुंचाया जा रहा है. वैसे कहने के लिए भारत-नेपाल की खुली सीमा पर एसएसबी के जवान तैनात रहते हैं. परंतु अवैध कारोबारी इनकी आंखों में धूल झोंककर मजे में शराब का धंधा कर रहे हैं. माना जा रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों का लाभ कारोबारी उठा रहे हैं. सीतामढ़ी जिले में बैरगनिया, सोनबरसा व भिट्ठा मोड़ पर थाना पुलिस के अलावा एसएसबी के जवान तैनात रहते हैं. गश्त के दौरान जवान जब शराब के कारोबारियों को रोकने का प्रयास करते हैं, तो वे सामान फेंककर नेपाल की सीमा में घुस जाते हैं. जवान फेंके गए सामान को जब्त तो कर लेते हैं, लेकिन तस्कर भाग निकलते हैं. मधुबनी जिले में साहरघाट के अलावा कई ऐसे स्थान हैं, जहां से नेपाली शराब लाकर बेचा जाता है. साथ ही इसी रास्ते से कारोबारी शराब का खेप दरभंगा से लेकर समस्तीपुर तक पहुंचा रहे हैं, जबकि समस्तीपुर रेल मंडल में रेलवे सुरक्षा बलों ने कई ट्रेनों में छापेमारी कर कई बार झारखंड से चोरी-छिपे शराब लेकर आने वालों को पकड़ने में कामयाबी पाई है. सड़क मार्ग का उपयोग कर कारोबारी समस्तीपुर से हाजीपुर होते हुए पटना तक शराब की खेप पहुंचाने में लगे रहते हैं. इधर गोपालगंज व मोतिहारी के अलावा सीतामढ़ी व समस्तीपुर के बीच स्थित मुजफ्फरपुर एक ऐसा शहर है, जहां चारों तरफ से आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध हैं. नशाबंदी के बाद इन जिलों में पुलिस अब केवल वाहनों की ही नहीं, बल्कि कागजात और सामान की जांच भी करने लगी है. कहीं-कहीं अवैध वसूली का मामला भी सामने आया है. हाल में वाहन चालकों से अवैध वसूली के मामले में सीतामढ़ी में कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है. इसके बावजूद पुलिस की कार्यशैली पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. लेकिन यह भी सत्य है कि अगर सरकारी तंत्र पूर्ण रूप से शराब पर नियंत्रण करना चाह ले, तब इस पर अंकुश लगाया जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

मायावती आईं तो फिर टूटेगा उत्तर प्रदेश

बांटो और राज करो

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश के लोगों में फिर से एक भय गहराने लगा है कि मायावती अगर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आईं तो यूपी फिर विभाजित होगा. विशाल उत्तर प्रदेश की अधिकतम लोकसभा और अधिकतम विधानसभा सीटों से कई नेता घबराते हैं. इनमें मायावती भी एक हैं. उत्तर प्रदेश को तोड़ कर उत्तराखंड बनाने से नए बने प्रदेश को क्या हासिल हुआ, इसे सब जानते हैं. केक की तरह राज्यों को बांट-बांट कर सत्ता सुख भोगने के अलावा बंटे हुए राज्यों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ. न उत्तराखंड को, न झारखंड को, न छत्तीसगढ़ को और न तेलंगाना को. नेताओं के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं मिला. अलग सरकारी तामझाम स्थापित करने का खर्च ऊपर से जनता के सिर थोप दिया गया. बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने अपने पूर्ववर्ती शासनकाल में भी उत्तर प्रदेश को अवध प्रदेश, पश्चिम प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव लाया था. यानि, उत्तर प्रदेश को तहस-नहस करने की योजना थी, लेकिन उस समय यह कार्यरूप नहीं ले सका. इस बार चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के पहले मायावती ने फिर से यूपी को विभाजित करने की अपनी पुरानी जिद पर जोर दिया. बात थोड़ी सी आई. मीडिया ने भी बहुत तवज्जो नहीं दिया. लेकिन भीतर-भीतर यह मामला गहरा रहा है. यूपी के और विभाजन की बात से प्रदेश के लोग आक्रांत हैं. कानून के जानकार इसे रोकने के लिए कानूनी युक्तियां तलाशने में लग गए हैं. लोग फिर से उन राजनीतिकों और राजनीतिक दलों को याद कर रहे हैं, जिनकी नीतियां प्रदेश को छोटा करने की राजनीति के खिलाफ रही हैं.

राजनीति की नब्ज पहचानने वाले कुछ समीक्षकों का आकलन था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बंटवारे का मसला उठेगा और इस चुनाव के जरिए विभाजन के सवाल पर जनमत-संग्रह जैसा भी हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यह और खतरनाक स्थिति है. ऐसी स्थितियों में सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी अपने मन-मुताबिक जनमत-संग्रह 'मैनेज' कराती है. आप याद करते चलें, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में पास कराया था. हालांकि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था. मायावती का वह विभाजन-कार्ड तो 2012 के चुनाव में नहीं चला और उनकी सत्ता धराशाई हो गई, लेकिन बृहत्तर प्रदेश में राजनीति का बेहतर भविष्य नहीं देखने वाली मायावती और उनके जैसे तमाम सूक्ष्मदर्शी नेता उत्तर प्रदेश को चार और भाग में तोड़ने का मौका तलाश रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश का अपना अस्तित्व भले ही धूल में मिल जाए. बसपा के अंदरूनी गलियारे में यह भी चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश के विभाजन का मायावती का लक्ष्य बसपा के घोषणा पत्र में शामिल होगा. लेकिन बसपा का कोई घोषणा पत्र ही नहीं आया. उत्तर प्रदेश के बंटवारे के पक्ष में मायावती यह तर्क देती रही हैं कि प्रदेश का विकास और कानून व्यवस्था उसके आकार में बड़े होने के कारण नहीं हो रहा है. वे अखिलेश यादव पर खराब कानून व्यवस्था के लिए लगातार प्रहार भी करती रही हैं और धीरे से यह भी कहती रही हैं कि बृहत्तर प्रदेश होने के कारण कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है. ऐसा कह कर मायावती अपनी मंशा जताती हैं. मायावती उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विभाजन को जरिया बनाने का कार्ड खेल रही हैं. अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने की नीयत का खुलासा करने के बजाय मायावती लोगों से यह कहती हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा करके राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में विकास की नीतियों और कार्यक्रमों को पहुंचाया जा सकता है. लेकिन ऐसा कहते हुए मायावती तमाम सद्यःविभाजित राज्यों के मौजूदा हालात पर रौशनी नहीं डालतीं.

अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने की नीयत का खुलासा करने के बजाय मायावती लोगों से यह कहती हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा करके राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में विकास की नीतियों और कार्यक्रमों को पहुंचाया जा सकता है. लेकिन ऐसा कहते हुए मायावती तमाम सद्यःविभाजित राज्यों के मौजूदा हालात पर रौशनी नहीं डालतीं.

मायावती का लक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश है. उत्तर प्रदेश को बांट कर उसे वे हरित प्रदेश बनाना चाहती हैं और वहां की सत्ता पर आधिपत्य चाहती हैं. राज्य के बंटवारे में भाजपा भी उनका साथ दे सकती है. उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे तमाम राज्यों को अस्तित्व में लाने की प्रक्रिया कांग्रेस के कार्यकाल में पुख्ता हुई और भाजपा के शासनकाल में मंजूर हुई. हरित प्रदेश की मांग का समर्थन राष्ट्रीय लोक दल भी करता है. अविभाजित उत्तर प्रदेश के मसले पर अब तक खड़ी समाजवादी पार्टी के साथ भविष्य में कांग्रेस भी खड़ी रहेगी, गठबंधन के बावजूद इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता. उत्तर प्रदेश में अभी 75 जिले और 18 मंडल हैं. मायावती की इस हालिया सफाई के भी निहितार्थ समझने की जरूरत है, जब वे यह कहती हैं कि यूपी में मूर्तियां और संग्रहालय स्थापित करने का काम बहुत हो चुका, अब दूसरी प्राथमिकताओं पर काम किया जाएगा. मायावती की दूसरी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों में सत्ताई-महत्वाकांक्षा को गहरा कर राज्य को चार भाग में बांटने की है. मायावती ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में बांटने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की बात कही है. मायावती का कहना है कि उनकी पार्टी छोटे राज्यों और छोटी प्रशासनिक इकाइयों के गठन की प्रबल समर्थक है. छोटी प्रशासनिक इकाइयां होने से कानून और व्यवस्था तथा विकास कार्यों की स्थिति को बेहतर बनाने में सुविधा रहेगी. इसी सोच के आधार पर उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कई मंडलों और जिलों का गठन किया था.

अगर उत्तर प्रदेश का बंटवारा होता है तो पश्चिम प्रदेश में पश्चिमी यूपी के 26 जिले आएंगे जबकि अवध में 13 जिले रहेंगे. बुंदेलखंड में 7 और पूर्वांचल में सर्वाधिक 29 जिले आएंगे. पश्चिम प्रदेश में आगरा, मेरठ और नोएडा जैसे जिले चले जाएंगे. अवध के हिस्से में लखनऊ और कानपुर जैसे जिले आ पाएंगे. पूर्वांचल के पास गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद रहेंगे. बुंदेलखंड के हिस्से में झांसी, बांदा और चित्रकूट आएंगे. जनसंख्या के मुताबिक उत्तर प्रदेश का स्थान दुनिया में पांचवां है. यूपी को फिर से तोड़ने की मांग उत्तराखंड के विभाजन के बाद ही तेज हो गई. हालांकि यूपी को उत्तराखंड समेत कई टुकड़ों में तोड़ने की मांग अर्सा पहले से उठ रही थी. उत्तराखंड बनने से चार लोकसभा क्षेत्र यूपी से अलग हो गए. अब चार अलग राज्य बनाने की मांग है, यानि यूपी छोटे से पांचवें (उत्तराखंड को शामिल करें तो छठे) राज्य के रूप में सिमट जाएगा. जब वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़ कर तेलंगाना बना, तब भी भाजपा नेता उमा भारती ने राज्य पुनर्गठन आयोग को फिर से बनाने की मांग की थी और कहा था कि अलग राज्य बनाने के जो अन्य प्रस्ताव वंचित रह गए हैं, उन पर भी विचार किया जाए. उमा भारती ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों को मिलाकर पृथक राज्य बनाने और उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में बांटने के मायावती के प्रस्ताव पर भी विचार किए जाने की मांग की थी.

(शेष पृष्ठ 13 पर)

बंटवारे पर क्या कहता है संविधान और क़ानून

संविधान के द्वारा राज्यों का श्रेणियों में विभाजन तात्कालिक उपयोगिता के आधार पर किया गया था. इस व्यवस्था से सभी संतुष्ट नहीं थे. जब केंद्र सरकार ने मद्रास राज्य की तेलुगू भाषी जनता की मांग पर 1952 में आंध्र को अलग राज्य बनाने का निर्णय किया तो स्थिति में अचानक ही बदलाव आ गया. एक अक्टूबर, 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के बाद भाषा के आधार पर नए राज्यों के पुनर्गठन की मांग भड़क उठी. विवाद गहराता देख वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई. इस आयोग में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष और पंडित एचएन कुंजरू और सरदार केएम पणिक्कर इसके सदस्य थे.

हालांकि संविधान निर्माण के बाद ही 27 नवम्बर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय आयोग का गठन किया और उसे इस बात की जांच-पड़ताल करने के लिए कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है अथवा नहीं. इस आयोग ने दिसम्बर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में आयोग ने प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया. 22 दिसम्बर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता वाले आयोग ने 30 सितम्बर 1955 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट दी और राज्यों के पुनर्गठन के बारे में अपने सुझाव रखे. फजल अली आयोग ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है. आयोग का कहना था कि राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता और पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए. ए-बी-सी-डी वर्गों में विभाजित राज्यों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इनकी जगह पर सोलह राज्यों व तीन केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाना चाहिए. संसद ने इस आयोग की सिफारिशों को कुछ बदलाव के साथ स्वीकार कर लिया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया. इस अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य और पांच केंद्र शासित प्रदेश थे. इसमें जिन 14 राज्यों का उल्लेख था, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा (वर्तमान में ओड़ीशा), पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल थे. जो पांच केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए थे, उनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह थे. ■

पृष्ठ 12 का शेष

किस राज्य में जाएंगे कौन से ज़िले

उत्तर प्रदेश का विभाजन चार विभिन्न राज्यों में हुआ तो कौन से जिले किस राज्य में जाएंगे इसे जान लेना भी जरूरी है. पूर्वांचल बना तो बिहार की सीमा से सटे 24 जिले इस राज्य में चले जाएंगे. इनमें वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती जैसे जिले उल्लेखनीय हैं. इसी तरह बुंदेलखंड राज्य बना तो तीन मंडल और 11 जिले चले जाएंगे. इनमें झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन जैसे जिले शामिल रहेंगे. पश्चिम प्रदेश बनने पर आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली जैसे जिले उसकी शोभा बनेंगे. अवध प्रदेश बना तो बाकी बचा हुआ लखनऊ, देवीपाटन, फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर इसके हिस्से आएगा. ■

क्या कहते रहे हैं नेता

समाजवादी पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कहते रहे हैं कि प्रदेश के बंटवारे की बात करने वाले लोग एकता के दुश्मन हैं. मुलायम ने उत्तराखंड के गठन का भी विरोध किया था. मुलायम हरित प्रदेश बनाने की मांग का भी कट्टर विरोध करते रहे हैं. तब मुलायम ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की नीति राज्यों के विभाजन के खिलाफ है. मुलायम ने कहा था कि प्रदेश का और बंटवारा सपा के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे. प्रदेश की जनता बंटवारा चाहने वाले दलों को सबक सिखा देगी, क्योंकि यह फैसला क्षुद्र मानसिकता का प्रतीक, जन-विरोधी और विकास विरोधी है. मुलायम के निवर्तमान होने के बाद अखिलेशकाल में भी सपा ने अपनी नीतियां वही रखी हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट कहा है कि वे उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होने देंगे. अखिलेश का कहना है कि देश की एकता के लिए बड़ा प्रदेश जरूरी है.

उत्तर प्रदेश के और बंटवारे पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ढुलमुल है. कभी उमा भारती कहती हैं कि नया राज्य गठन आयोग बना कर नए राज्यों के प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश में चार और नए राज्य बनाने की मांग पर विचार हो. जबकि भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता अव्वल तो मायावती के बयान को चुनावी स्टंट बताते हैं और कहते हैं कि यूपी को चार राज्यों में बांटने की कोई जरूरत ही नहीं है. भाजपा के नेता अलग किस्म के तर्क का जाल रचते हैं और कहते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग गठित कर उससे भागौलिक, सामाजिक और आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए नए राज्यों के बारे में संस्तुति मंगाई जाए. कांग्रेस ने छोटे राज्य बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा था तब बसपा ने इसका विरोध किया था. कांग्रेस छोटे राज्यों का समर्थन करती रही है. कांग्रेस भी राज्यों के बंटवारे के लिए द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किए जाने की मांग कर रही है. राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष गोपाल राय कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश और बुंदेलखंड में विभाजित करना अनिवार्यता है और समय की मांग है. इस मांग पर राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी और पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा की ओर से लखनऊ और दिल्ली में कई धरना-प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते रहे हैं. ■

राज्य बांटने की ज़िद जारी

केवल उत्तर प्रदेश को ही चार और टुकड़ों में बांटने की तैयारी नहीं है, देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग राज्य बनाने की मांग भी लगातार जारी है और कई जगह हिंसक शक्ल भी अख्तियार कर चुकी है. पूर्वोत्तर में बोडोलैंड बनाने की मांग अर्से से उठ रही है. असम से काट कर अलग राज्य बनाने की मांग भीषण हिंसक शक्ल भी अख्तियार कर चुकी है. बोडो जनजाति ब्रह्मपुत्र घाटी के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है. इसी तरह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड बनाने की मांग भी अर्से से हो रही है. बुंदेलखंड लगातार पिछड़ता जा रहा है. इसलिए इसे अलग राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है. दक्षिण-पश्चिम कर्नाटक के एक छोटे भाग से 'कुर्ग' के गठन की भी मांग हो रही है. यह मांग अब तक जोर नहीं पकड़ पाई है, लेकिन अंदर-अंदर सुगबुगा रही है. पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से से अलग कर गोरखालैंड के गठन की मांग भी पुरानी है. इसके गठन को लेकर तीव्र आंदोलन भी चलाए जाते रहे हैं. गोरखालैंड की मांग को वहां के नागरिकों का भी भरपूर समर्थन हासिल है. जन-दबाव के कारण ही पश्चिम बंगाल सरकार को दार्जीलिंग स्वायत्त परिषद की स्थापना कर अधिक अधिकार देने पड़े. इस आंदोलन ने कई बार हिंसक शक्ल भी अख्तियार किया. सुभाष घीसिंग गोरखालैंड आंदोलन के जुझारू नेता थे. उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को 'हरित प्रदेश' बनाने की मांग भी अर्से से हो रही है. इसी तरह पूर्वांचल की मांग भी बड़े राजनीतिक आंदोलन का शक्ल लेने की तैयारी में है. गुजरात के एक बड़े तटीय भाग से 'सौराष्ट्र' को अलग करने की मांग भी अर्से से उठती रही है. इस क्षेत्र में कई उद्योग धंधे फैले हुए हैं. समुद्री परिवहन का भी यह एक बड़ा केंद्र है. महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से से विदर्भ को अलग कर विदर्भ राज्य बनाने की मांग लगातार उठ रही है. कृषि की दृष्टि से विदर्भ, देश के पिछड़े इलाकों में गिना जा रहा है. अनाज की कमी, फसल चौपट होने और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण इस इलाके में किसानों की हर साल हो रही आत्महत्याएं अलग राज्य की मांग में आग में घी का काम कर रही हैं. आंध्र प्रदेश को काट कर जैसे ही पृथक तेलंगाना राज्य बना था, वैसे ही देश के अन्य भागों में छोटे राज्यों के निर्माण के लिए दशकों से चलते आ रहे आंदोलनों में जैसे नई जान आ गई. गोरखालैंड, विदर्भ, कार्बी आंगलांग, बोडोलैंड, पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश, हरित प्रदेश और बुंदेलखंड जैसे कई राज्यों की मांग सियासत का जरूरी हिस्सा बन गया. ऐसे में अब यह जरूरी हो गया है कि केंद्र द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करे और उसके जरिए नए राज्यों के पुनर्गठन के राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहलुओं का गहराई से अध्ययन कराए, ताकि भविष्य में नए और छोटे राज्यों के निर्माण के बारे में सुविचारित, सुस्पष्ट और सुदृढ़ नीति बने और उस पर अमल हो. उसके पहले नए राज्यों के विभाजन की मांग पर कोई सुनवाई न हो. ■

उत्तर प्रदेश के बंटवारे के पीछे विकास और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के तर्क बेमानी हैं, इसे आम नागरिक भी अच्छी तरह समझते हैं. यह सत्ता का उपभोग करने की एक निम्न स्तरीय राजनीतिक चाल है. बंटवारे के पीछे राजनीतिक दलों की मंशा एक के बजाय पांच राज्यों में अपना धंधा फैलाने की है. उत्तर प्रदेश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने की वकालत करने वाली बसपा नेता मायावती इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का हवाला देकर उसे अपने तर्कों का आधार देती हैं. लेकिन असलियत यह है कि अंबेडकर देश और राज्य को टुकड़ों में बांटने के सख्त विरोधी थे.

बंटवारा भारत का चरित्र बन चुका है. पहले देश बांटा और उसके बाद लगातार राज्यों को बांटते चले जा रहे हैं. तथाकथित आजादी के बाद रजवाड़ों के भारतीय गणराज्य में विलय के साथ ही नए राज्यों के गठन की जमीन तैयार होने लगी थी. वर्ष 1953 में स्टेट ऑफ आंध्र पहला राज्य बना, जिसे भाषा के आधार पर मद्रास स्टेट से अलग किया गया था. इसके बाद दिसंबर 1953 में जवाहर लाल नेहरू ने न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया. एक नवम्बर 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956 लागू हो गया और भाषा के आधार पर देश में 14 राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए. मध्य प्रांत के शहर नागपुर और हैदराबाद के मराठवाड़ा को बॉम्बे स्टेट में इसलिए शामिल किया गया, क्योंकि वहां मराठी बोलने वाले अधिक थे. इसके बाद लगातार कई राज्यों का भूगोल बदलता रहा और नए तर्कों व मानकों के आधार पर नए-नए राज्य बनते गए. त्रिपुरा को असम से भाषा के आधार पर अलग किया गया तो मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड का गठन नस्ल के आधार पर किया गया. सन 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बंटवारे के आधार भी विकास नहीं थे बल्कि असलियत में सत्ताई महत्वाकांक्षा, नस्ल और भाषा थी. धीरे-धीरे देश के कई भागों में इस मुद्दे ने जोर पकड़ा. नतीजतन आज भारत में 29 राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेश हैं. कई सामाजिक-राजनीतिक चिंतकों ने भी कहा कि विभाजित राज्य अधिकतर विफल ही रहे. छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इसका सटीक उदाहरण है. झारखंड में तो राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है और लगातार पिछड़ता ही जा रहा है. ऐसे में अगर पश्चिम प्रदेश, पूर्वांचल, अवध प्रदेश और बुंदेलखंड की सफलता के तर्क अनुभव की कसौटी पर रखे जाएं तो वे बेमानी और फर्जी ही साबित होते हैं. राज्य को छोटा कर देने से सिर्फ प्रशासनिक ढांचा बदल सकता है. लेकिन बेरोजगारी और गरीबी से लड़ने की कोई स्पष्ट नीति ही नहीं होगी तो प्रदेश को कितना भी छोटा कर दिया जाए, उससे कोई फायदा नहीं होगा. सामाजिक चिंतक मानते हैं कि राज्य के बंटवारे की बात राजनीतिक पार्टियां इसलिए करती हैं क्योंकि वह लोगों का ध्यान असली मुद्दे से भटकाना चाहती हैं. राज्यों का बंटवारा समस्या का हल नहीं है, बल्कि समस्या को और न्यौता देना है. ■

feedback@chauthiduniya.com

क्या कहते हैं आम लोग

उत्तर प्रदेश के और विभाजन पर आम नागरिकों के विचार भी खासे महत्वपूर्ण हैं, जिन पर राजनीतिक दल के नेताओं को विचार करना चाहिए. किसी फैसले पर पहुंचने के पहले आम लोगों की राय जान लेना और उस अनुरूप निर्णय लेना समझदारी भी है और लोकतांत्रिक भी. उत्तर प्रदेश को और बांटे जाने के मसले पर पूर्वांचल निर्यातक संघ के उपाध्यक्ष मुकुंद अग्रवाल कहते हैं कि नए राज्य का गठन तो ठीक है पर प्रदेश को चिंदी-चिंदी करना तो कतई ठीक नहीं है. जिस तरह राज्य बांटे जा रहे हैं, ऐसे बंटवारे का तरीका उचित नहीं है. यदि अलग राज्य बनता है तो विकास होना चाहिए. संसाधनों की लूट और बदहाली न हो. बंटवारा राजनीतिक इरादे से नहीं बल्कि सामाजिक नजरिए से हो. आइटी बीएचयू के प्रोफेसर केके श्रीवास्तव कहते हैं कि विकास का तर्क देकर प्रांत का विभाजन करना तर्कसंगत नहीं है. विकास के लिए पंचायतों को मजबूत करना होगा, स्वायत्तता देनी होगी. विभाजन की घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन इसके विकास का खाका प्रस्तुत किया जाता. विकास का आधार सिर्फ संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं बल्कि आपसी सहमति और सामंजस्य भी होना चाहिए. बीएचयू के ही विधि संकाय के प्रोफेसर डॉ. एके पांडेय कहते हैं कि अभी वह वक्त नहीं है कि प्रांत के विभाजन की बात हो. पूर्वांचल में न तो संसाधन है और न ही उद्योग धंधे. पहले वहां तमाम सुविधाएं बहाल की जानी चाहिए. गोरखपुर के व्यवसाई मनोज अग्रवाल कहते हैं कि छोटा राज्य होगा तो तरक्की होगी. पूर्वांचल जो टैक्स देता है वह यूपी में केंद्रित हो जाता है और उससे अन्य क्षेत्रों का विकास किया जाता है, पूर्वांचल उपेक्षित रह जाता है. लेकिन सरकार बंटवारे का जो तरीका अपनाती है, वह गलत है. इस पर बहस होनी चाहिए. व्यापक जनमत संग्रह किया जाना चाहिए.

साहित्यकार आचार्य रामदेव शुक्ल कहते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर तो प्रशासनिक इकाइयां जितनी छोटी होती हैं, शासन उतना अच्छा होता है, लेकिन जिस तरह राज्य बांटे जाते हैं, वह सैद्धांतिक नहीं, राजनीतिक होते हैं. देश में अनेक जगहों पर विभाजन की मांग की जा रही है. ऐसे में उचित होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर इसका अध्ययन कराया जाए कि किस प्रकार व किन आधार पर विभाजन किए जाएं. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवक्ता डॉ. अनुराग कहते हैं कि वह छोटे राज्यों के पक्षधर हैं लेकिन इसमें दो बातों पर विशेष ध्यान देना होगा. प्रशासनिक पहुंच आमजन तक हो और कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ आम जन को मिले. प्रमुख समाजसेवी लखनऊ निवासी अशोक गोयल कहते हैं कि राज्यों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने के पीछे राजनीतिक दलों का उद्देश्य महज सत्ता का उपभोग करना ही है. देश का विकास और खुशहाली अगर राजनीतिक पार्टियों की प्राथमिकता होती तो क्या आजादी का 70 साल बीत जाता? राजनीतिक दलों ने देश का मजाक बना डाला है. इतने राज्यों का बंटवारा किया, क्या मिल गया उन राज्यों के लोगों को? केवल और केवल नेताओं, नौकरशाहों, पूंजीपतियों और दलालों को इसका लाभ मिला. आम आदमी तो तब भी मरता था और अब भी मर रहा है. छोटे राज्य ही विकास का आधार होते तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्य अब तक हजार राज्यों में विभाजित हो चुके होते. 50 राज्यों वाले अमेरिका जैसे विशाल देश ने विकास की चरम स्थिति कैसे पा ली? चीन जैसे विशाल देश में विकास ने इतनी ऊंचाइयां कैसे पाईं? तो ये छोटे राज्यों से विकास की बातें, सब नेताओं की जालसाजियां हैं, आम लोग सब समझते हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा. ■

हिन्द की चादर, गुरु तेग बहादुर

चौथी दुनिया ब्यूरो

विजय गुप्त

कविता के किसी विधा में ऐतिहासिक गाथा बयान करने के अपने ख़तरे हैं. कई बार ऐसा होता है कि कविता पर पकड़ मज़बूत हुई तो कहानी के तार ढीले पड़ जाते हैं और यदि कहानी के सूत्र मज़बूत हुए तो कविता की धार मंद पड़ जाती है. लेकिन इस मामले में विजय गुप्त कामयाब दिखते हैं. यहां पाठक कहानी और कविता का आनंद एकसाथ उठा सकते हैं. किताब का हर अध्याय अपने आप में स्वतंत्र होने के साथ-साथ, एक-दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ भी है.

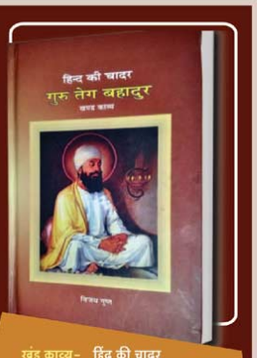

खंड काव्य- हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर
कवि- विजय गुप्त
प्रकाशक- स्वामी विवेकानंद बाल भारती (विद्यालय)
कीमत- 300 रुपए

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि साहित्य समाज का आईना होता है. साहित्य की सामाजिक उपयोगिता ऐसे में और बढ़ जाती है, जब उसका विषय वस्तु आम लोगों की भावनाओं से जुड़ा हो. लिहाज़ा गुरु तेग बहादुर के गौरवपूर्ण बलिदान का काव्यमय वर्णन 'हिन्द की चादर गुरु तेग बहादुर' हिंदी काव्य साहित्य को निश्चित रूप से समृद्ध करता है. यह काव्य खंड इतिहास के उन पन्नों से धूल हटाने का प्रयास है, जिन्हें धुंधला करने के लिए समय सदा प्रयासरत रहा है. विजय गुप्त ने इस कृति के लिए जो विषय वस्तु चुनी और जो रचनात्मक बुनावट तैयार की, वह निश्चित रूप से हिन्दी जगत में नएपन का अहसास दिलाता है. दरअसल कविता भी कहानी का एक रूप ही होती है. इसमें कुछ शब्दों में पूरी कायनात समा जाती है. उर्दू शायर मीर की एक पंक्ति इस तथ्य को बखूबी उजागर करती है : अक्षर तो हैं इश्क के दो ही, लेकिन है विस्तार बहुत. हिन्द की चादर में इश्क के दो शब्दों का विस्तार साफ़ दिखाई देता है. सीधी-सरल और सहज भाषा में लिखी यह कविता अपनी सादगी और सरलता से सीधे पाठकों के दिलों को स्पर्श करती है. एक आम पाठक की प्रतिक्रिया का अंदाजा किताब में शामिल राष्ट्रीय सिख संगत के चिरंजीव सिंह के संदेश से हो सकता है: (इस किताब की) एक बार पाठन शुरू करो तो अंत तक देखते ही रहने को मन उत्सुक रहता है. भाषा सरल है. विचार गहरा है. सिख इतिहास से अनभिज्ञ वर्ग के लिए यह उत्तम सेवा है. भाषा की सादगी और सरलता को काव्य खंड की शुरुआती पंक्तियों से समझा जा सकता है :

सिख धर्म का इतिहास श्रेष्ठ है,
जहां गुरु हुए महान.
त्याग, सत्य, समर्पण भाव से किया
जन-जन का कल्याण ..
अपनी मधुर वाणी से बांटा,
ईश्वर भक्ति का सुन्दर ज्ञान.
हर मानव को सीख दी सत्य की,
करो प्रभु नित्य ध्यान..
अपने कर्मों की उज्ज्वलता से पाओ,
तुम विश्व में मान.
अपने श्रेष्ठ कार्यों से हो,
अपनी सर्वत्र श्रेष्ठ सुन्दर पहचान..

कविता के किसी विधा में ऐतिहासिक गाथा बयान करने के अपने खतरे हैं. कई बार ऐसा होता है कि कविता पर पकड़ मज़बूत हुई तो कहानी के तार ढीले पड़ जाते हैं और यदि कहानी के सूत्र मज़बूत हुए तो कविता की धार मंद पड़ जाती है. लेकिन इस मामले में विजय गुप्त कामयाब दिखते हैं. यहां पाठक कहानी और कविता का आनंद एकसाथ उठा सकते हैं.

इस किताब का हर अध्याय अपने आप में स्वतंत्र होने के साथ-साथ, एक-दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ भी है. गुरु तेग बहादुर के जीवन के अनुभवों का क्रमवार विश्लेषण इस किताब का सार तत्व है, जो माले के मनकों की तरह आपस में गुंथा हुआ है. गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा और मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए बलिदान दिया था. उस बलिदान का उतम चित्रण यहां प्रस्तुत किया गया है:

शीश कटा कर झुका नहीं,
किसी भी अधर्म के आगे
जीतने वाला अंतरात्मा हार गया,
कितने थे वे अभागे.
जिनके बलिदान पर धर धर्राई,
कांप उठा आसमान
इतिहास के पन्नों पर अंकित है,
तुम्हारा बलिदान..

खंड काव्य के शुरू में कवि ने सिख धर्म के सभी गुरुओं का पुनर्स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. मध्यकाल में इस्लाम धर्म सत्ताधीशों की विस्तारवादी नीति का संवाहक बना था. वे लिखते हैं,

'इस्लाम चहूं ओर खूब बढ़े,
औरंगजेब ने चलाया था अभियान,
क्रूर शासक के हृदय में था,
बस निर्दयता और अभिमान.'

ऐसे समय में सत्य, आदर्श, नैतिकता, सामाजिक समरसता और गंगा-जमुनी तहजीब की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर आगे आए. औरंगजेब ने उन्हें तरह-तरह का भय दिखाया. उसने कहा, 'तुम खो गए, कट गए अगर, तो बिखर जाएगा सारा परिवार, उनके लिए केवल मृत्युदंड है, जो हमारी बात से करें इनकार.' गुरु तेग बहादुर भी कहां मानने वाले थे. वे जोश में कहते हैं, 'तुम अहंकार के ऊंचे बादशाह हो, भीतर से अज्ञानी, मूर्तियों को खंडित करनेवालों ने ली कितने जिंदों की कुर्बानी.' औरंगजेब गुस्से से उबलने लगता है और कहता है, ' प्राण चाहते हो गर अपने, हमारे कानून का मान करो, जितनी जल्दी हो झुक जाओ, तुरंत कबूल इस्लाम करो.

एक नन्हे कागज पर गुरुजी ने लिख दी एक ऐतिहासिक बात, उसे पास रखकर बोले, कुछ नहीं कर सकता अब जल्लाद, अपने बलिदान से देंगे, हम अपने राष्ट्र को जीने की सौगात.'

प्रबंध काव्य की एक प्रमुख विधा खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होता है, जबकि महाकाव्य में मुख्य चरित्र के जीवन वृत्त का समग्रता में चित्रण किया जाता है. हालांकि दोनों में ऐतिहासिक घटनाओं और चरित्रों का विशेष महत्व होता है. साहित्य के पुरोधा कहते हैं कि मुख्य चरित्र के किसी एक विशेष अंश पर केंद्रित होने के कारण खंड काव्य में विविधता और विस्तार की कमी होती है. लेकिन विजय गुप्त का खंड काव्य 'हिन्द की चादर गुरु तेग बहादुर' को पढ़ने के बाद कहीं भी एकाकी और एकरसता का भावबोध नहीं होता है. गुरु तेग बहादुर के विशेष गुणों को उभारने की कला में भी पाठकों को समग्रता का अहसास होता है. यही इस खंड काव्य को हिन्दी के अन्य खंड काव्यों से अलग करता है. भाषा शैली की बात करें तो उनकी भाषा काफी सरल, सरस और लच्छीली है. वे संवाद शैली में अपनी बातें रखते हैं, जो पाठकों को अंत तक एकसूत्र में बांधे रखता है. पदों में एक अलग तरह का प्रवाह पूरे खंडकाव्य को एकसूत्र में पिरोता है और आम पाठकों को भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से अंत तक रूबरू कराता चलता है. कह सकते हैं कि उक्त खंडकाव्य ने हिंदी साहित्य को विधागत स्तर पर समृद्ध किया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

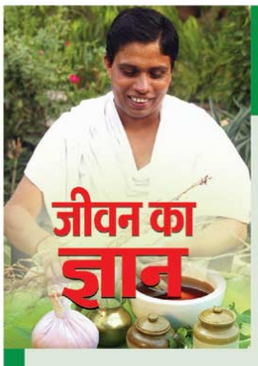

भूनिम्ब (कालमेघ)

परिचय

कालमेघ यकृत-विकारों तथा ज्वर की अत्यन्त उत्तम औषधि है. यह औषधि चिरायते जैसी, किन्तु चिरायते से हीन गुण धर्म वाली होती है. प्रायः चिरायते में इस औषधि का मिश्रण किया जाता है. यह संपूर्ण भारत के वन्य-प्रदेशों एवं मैदानी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश से आसाम, मिजोरम तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में प्राप्त होता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

❖ **उदर रोग-** भूनिम्ब, नीम छाल, त्रिफला, परवल पत्र, वासा, गिलोय, पित्तपापड़ा तथा भृंगराज आदि औषधियों से निर्मित क्वाथ 10 मिली में मधु मिलाकर पीने से अम्लपित्त रोग में लाभ होता है.

❖ 1-1 भाग भूनिम्ब, कुटकी, ब्योष सोंठ, मरिच, पीपल, नागरमोथा, इन्द्रयव, 2 भाग चित्रकमूल तथा 16 भाग कुटज की छाल के सूक्ष्म चूर्ण को मिलाकर 1-2 ग्राम मात्रा में लेकर गुड़ के शरबत के साथ खाने से ग्रहणी, गुल्म, कामला, ज्वर, पाण्डु रोग, प्रमेह, भोजन के प्रति अरुचि तथा अतिसार में लाभ होता है.

❖ समभाग वासा, गुडूची, हरड़, बहेड़ा, आंवला, कुटकी, भूनिम्ब तथा नीम की छाल के 10-20 मिली क्वाथ में मधु मिलाकर पीने से पाण्डु रोग, पित्तज-विकार, रक्तज-विकार और कामला रोग में लाभ होता है.

❖ समभाग परवल की पत्ती, नीम की छाल, भूनिम्ब, रास्ना तथा सप्तपर्ण की छाल से निर्मित 400 मिली क्वाथ मे 100 ग्राम सरसों के कल्क को मिलाकर, निरुहबस्ति देने से प्रमेह, अभिष्यंद तथा कुष्ठ रोग में लाभ होता है.

❖ **त्वचा राग-** भूनिम्ब, सैरेयक, पटोल आदि औषधियों से निर्मित क्वाथ आदि का प्रयोग करने से वमन, कुष्ठ, विष विकार, ज्वर, कफज रोग, कण्डू तथा प्रमेह रोग में लाभ होता है तथा दूषित व्रण का शोधन होता है.

❖ **फुंसिया-** 2 भाग भूनिम्ब तथा 1 भाग नीम छाल चूर्ण का विधिवत् क्वाथ बनाकर 10-20 मिली क्वाथ को तीन दिन तक पीने से फुंसियों का शमन होता है.

❖ समभाग भूनिम्ब तथा सोंठ के कल्क (2 ग्राम) को गुनगुने जल के साथ सेवन करने से त्रिदोषज शोथ एवं चिरकालिक शोथ का शमन होता है.

❖ मिट्टी के एक घड़े में भूनिम्ब के पत्ते बिछाकर, उस पर धनिया के पत्ते बिछाकर, पानी से भिगो कर रात भर छोड़ दें. प्रातः काल रस निकालकर सेवन करने तथा हाथ पैर पर लेप करने से दाह का शमन होता है.

❖ समभाग भूनिम्ब तथा सोंठ कल्क 1-2 ग्राम का सेवन कर उपर से पुनर्नवा क्वाथ 10-20 मिली पीने से सर्वांग शोथ का शमन होता है.

❖ **ज्वर-** चिरायता, निम्ब छाल, पिप्पली, कचूर, शुण्ठी, शतावरी, गुडूची तथा वृहती को समान मात्रा में लेकर, क्वाथ बनाकर 10-20 मिली पीने से कफज ज्वर का शमन होता है.

❖ **सामान्य दौर्बल्य-** 10-20 मिली भूनिम्ब पत्र क्वाथ या फाण्ट को पिलाने से दौर्बल्य का शमन होता है.

❖ **उदर-विकार-** 1-2 मिली कालमेघ पत्र-स्वरस को पिलाने से बालकों के पाचन संबंधी तथा अन्य उदर विकारों में लाभ होता है.

❖ **सर्पदंश-** भूनिम्ब के पत्रों को पीसकर दंश स्थान पर लेप करने से सर्पदंश तथा वृश्चिक दंशजन्य दाह, शूल आदि विष प्रभावों का शमन होता है.

विषाक्तता

❖ इस पौधे को अधिक मात्रा में तथा अधिक दिनों तक प्रयोग करने से दुष्प्रभाव होता है. दुष्प्रभाव स्वरूप शिरोघूर्णन, हृदस्पंदन, आध्मान, अरुचि, वमन जैसे लक्षण मिलते हैं. इसका लम्बे समय तक प्रयोग करने से आमाशयिक-विकार होता है.

❖ इसमें प्रजनन संस्थानगत विषाक्त प्रभाव तथा शुक्रजनन रोधक क्रिया देखी गयी है. साइटोकाइनेसिस के कारण स्पर्मेटोजेनिक कोशिका का विभाजन भी होता है.

❖ गर्भस्रावी प्रभाव के कारण गर्भावस्था में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए.

❖ इसकी अतिमात्रा आध्मान, अरुचि एवं वमन उत्पन्न कर सकती है. ■

प्रयोज्यांग : *पंचांग, पत्र, मूल तथा नवीन पत्र.*

मात्रा : *चूर्ण 1-3 ग्राम. स्वरस 5-10 मिली. क्वाथ 20-40 मिली. तरल सत्त 0.5-1 मिली या चिकित्सक के परामर्शानुसार.*

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

साईं भक्ति-प्रवाह

हरि अनंत, हरि कथा अनंता

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

अलौकिक और विचित्र हैं श्री साईं, जिन्हें अभी तक कोई अच्छी तरह से समझ नहीं सका. हर भक्त की यह आंतरिक इच्छा होती है कि वह अपने सद्गुरु के बारे में ज्यादा-से-ज्यादा जाने. बाबा के समय से लेकर आज तक जितनी किताबें, पत्रिकायें आदि छपी हैं, उनके बारे में पूर्ण विवरण किसी के पास उपलब्ध नहीं है. यह सब पढ़ने के बावजूद श्रद्धालु भक्तों में बाबा के बारे में और जानने की इच्छायें बढ़ती जा रही हैं. श्री साईं लीला पत्रिका और श्री दाभोलकर एवं श्री नरसिम्हा स्वामी की किताबों के अलावा विगत दशकों में विभिन्न भारतीय भाषाओं-मराठी, गुजराती और तेलुगु आदि में कई किताबें लिखी गयी हैं. इनमें से बहुत सी किताबें, जो बीसवीं शती के दूसरे-तीसरे दशक में मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थीं, एक बार मुद्रित होने के बाद उनका दूसरा मुद्रण नहीं हुआ. वस्तुतः बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले भक्त- जैसे कि रेगे, स्वामी, शरणानन्द जी, खापर्डे (डायरी) आदि द्वारा लिखी गई किताबें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. लेकिन इस प्रकार की किताबें बहुत कम संख्या में बाजार में उपलब्ध हैं.

भारत ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में बाबा के नाम का प्रचार और प्रसार अति तीव्र गति से हो रहा है. इसलिए समकालीन भक्तों द्वारा लिखी गई किताबों के पुनःमुद्रण और हिन्दी एवं अंग्रेजी में उनका रूपान्तरण करने की आवश्यकता महसूस हो रही है.

आज की यह आवश्यकता है कि बाबा पर लिखित किताबें, पत्रिकाओं की मुद्रित सामग्री एवं फोटो आदि को एकत्रित कर एक अच्छा पुस्तकालय बनाया जाए. आज के तकनीकी युग को देखते हुए कुछ लोगों ने बाबा से संबंधित वेबसाइट के माध्यम से बहुत सी सूचनाओं का पटल दुनिया के सामने खोलकर एक सराहनीय कार्य किया है. फिर भी, बाबा के बारे में गंभीर गवेषणा करने की आवश्यकता है. भारत और विदेशों के भी कुछ लेखकों (जैसे केविन शेफर्ड, मेरिया वॉरेन आदि) ने बाबा पर शोध-कार्य किए हैं. भारत में नरसिम्हा स्वामी, खेर, कामथ, भारद्वाज आदि कई भक्तों ने बाबा से संबंधित शोध-संबंधी तथ्यों को अपनी किताबों के जरिए जनमानस तक पहुंचाया है. ये लेखक अपने जीवन के कई दशकों में बाबा की सेवा करते रहे और इसका परिणाम अच्छा रहा. फिर भी भक्तों को बाबा से संबंधित जानकारी की कमी महसूस हो रही है. कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता. बाबा का आध्यात्मिक जीवन इतना बहुमुखी और विस्तृत था कि उसको एक यथार्थ रूप देने के लिए कम से कम एक एन्साइक्लोपीडिया की तरह की किताब की जरूरत होगी. पर एक एन्साइक्लोपीडिया बनाना कोई आसान काम नहीं है. विदेशों में प्रकाशित एन्साइक्लोपीडिया जैसा रूपाकार देने के लिए बाबा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों एवं दस्तावेजों को एक स्थान पर एकत्रित करना होगा. इस कार्य के लिए गहन शोध एवं बहुत परिश्रम की आवश्यकता है. इससे ज्यादा आवश्यक है- सद्गुरु के प्रति समर्पण का भाव.

बौद्धिक एवं शैक्षिक संस्थाओं में प्रचलित शोध की एक परंपरा और पद्धति है. आज की दुनिया में अगर बाबा के नाम का प्रचार और प्रसार करना हो तो शोधकर्ता को इस पद्धति को अपनाना पड़ेगा. भक्तों द्वारा मात्र भावात्मक रूप से लिखी गई किताबें कुछ भक्तों द्वारा आसानी से स्वीकार की जा सकती है, पर वे लोग जो खास तौर से विदेश में रहते हैं या बुद्धिजीवी वर्ग उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता. कहते हैं कि जिस भी देश में हम रहें, उस देश की संस्कृति के अनुसार हमें स्वयं को ढालना चाहिए. इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि इतिहास के जिस समय में हम कोई काम करें, तो उस काल के अनुसार हमें काम करना चाहिए. दासगुण महाराज ने ओवी शैली में श्री साईं के जीवन-चरित पर मराठी भाषा में लिखा था, जो कीर्तन के रूप में महाराष्ट्र में अत्यन्त लोकप्रिय हुआ था. पर इसका ज्यादा प्रसार तब हुआ, जब यह ग्रंथ-साहित्य के रूप में भारत की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुआ. इसके अलावा हिन्दी एवं क्षेत्रिय फिल्मों तथा टीवी सीरियल के माध्यम से भी बाबा का प्रचार-प्रसार हुआ है. आज अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बाबा के नाम और उनके दिव्य क्रिया-कलापों के विषय में प्रचार करना हो तो बाबा पर शोध करने वालों को चाहे विश्वविद्यालय के माध्यम से या किसी अन्य संगठन के जरिए इकट्ठा होना पड़ेगा और बाबा से संबंधित विषय-सामग्री एवं दस्तावेजों का परस्पर आदान-प्रदान करना होगा. हालांकि इस प्रकार का कार्य श्री शिरडी साईं संस्था द्वारा करना भी उचित होगा क्योंकि उनके पास आवश्यक पुराने दस्तावेज आदि मिलेंगे. सद्गुरुओं के व्यक्तित्व, लीला एवं बताए गए मार्ग से संबंधित विवरण का एकत्रीकरण एक अत्यन्त समयानुकूल आवश्यक पदक्षेप रहेगा. मैं समस्त साईं-भक्तों से यह निवेदन करता हूं कि वे इस कार्य में जुट जायें और मेरी यही प्रार्थना श्री साईं महाराज के चरण-कमल में है. ■

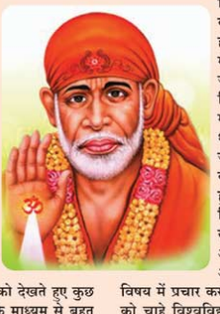

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बनें आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं. क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

भारतीय बैडमिंटन में अब लक्ष्य सेन ने दी दस्तक

विश्व जूनियर रैंकिंग में नम्बर वन बनकर बढ़ाया देश का मान

प्रकाश पादुकोण लक्ष्य के हुनर को चमका रहे हैं

चौथी दुनिया से ख़ास बातचीत में बोले सेन

दुनिया का शीर्ष खिलाड़ी बनना ही लक्ष्य

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारत में बैडमिंटन को लेकर अब अलग माहौल देखा जा सकता है. हाल के दिनों में भारतीय बैडमिंटन में सायना और सिंधु ने खूब नाम कमाया है. विदेशों में भारतीय बैडमिंटन की जमकर तारीफ हो रही है. एक ओर जहां महिला खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर पुरुष खिलाड़ी भी अपना दम-खम दिखाने में पीछे नहीं रहे हैं. अतीत में प्रकाश पादुकोण और गोपीचंद के खेल को दुनिया भर में सुर्खियां मिलती थी, लेकिन बाद में एकाध खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए, तो वैसी कामयाबी दूसरे भारतीय खिलाड़ियों में देखने को नहीं मिली है. मौजूदा समय में कश्यप व श्रीकांत जैसे खिलाड़ी उम्मीद बांध रहे हैं. इसी कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया है, जो विश्व बैडमिंटन में आने वाले समय में भारत का झंडा बुलंद कर सकता है. लक्ष्य सेन जैसे उभरते हुए सितारे में एक अलग तरह का हुनर देखा जा सकता है. विश्व जूनियर बैडमिंटन में नम्बर वन का तमगा हासिल करने वाले लक्ष्य सेन में अगला गोपीचंद अथवा प्रकाश पादुकोण बनने का दम-खम दिख रहा है. इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. जूनियर स्तर पर अपनी धाक जमाने वाले इस खिलाड़ी का अगला लक्ष्य है सीनियर लेवल पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना. हाल में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भारत के कई बड़े खिलाड़ियों को धूल चटाने वाले इस खिलाड़ी ने चौथी दुनिया से खास बातचीत में कहा कि अभी तो केवल शुरुआत है, आगे-आगे देखिए होता है क्या? उत्तराखंड से निकलने वाला बैडमिंटन का नया सितारा प्रकाश पादुकोण अकादमी में अपने खेल को नया मुकाम दे रहा है. लक्ष्य ने बेबाकी से कहा कि दुनिया का नम्बर वन शटलर बनना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है.

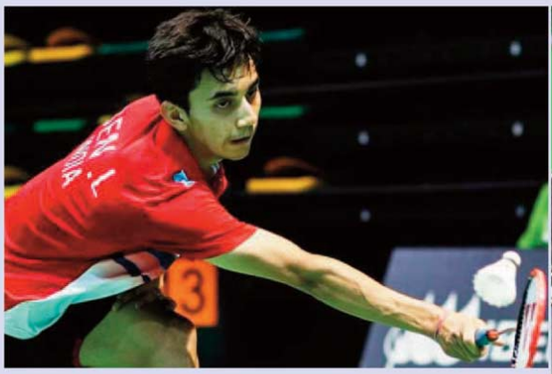

जूनियर स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उसने जूनियर विश्व रैंकिंग में नम्बर वन खिलाड़ी बनकर देश में बैडमिंटन का एक अलग प्रतिमान स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा दिया है. कुल मिलाकर देखा जाये तो आने वाले समय में लक्ष्य भारत में पुरुष बैडमिंटन में एक अलग नाम बनकर उभर सकते हैं.

लक्ष्य सेन की मानें तो वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है. कह सकते हैं कि लक्ष्य की रगों में बैडमिंटन का खून दौड़ रहा है. दरअसल बैडमिंटन का हुनर उनको विरासत में मिला है. पिता डीके सेन बैडमिंटन के कोच हैं, जबकि उनके भाई चिराग भी राष्ट्रीय स्तर के उभरते हुए खिलाड़ी हैं. पिता डीके सेन ने बताया कि एक टूर्नामेंट के दौरान बेंगलुरू में प्रकाश पादुकोण ने लक्ष्य की प्रतिभा को पहचाना. शुरू में कोच विमल कुमार ने बैडमिंटन की इस नयी प्रतिभा को प्रकाश पादुकोण अकादमी में रवा करना शुरू कर दिया था. पिता की मानें तो लक्ष्य शुरू से ही बैडमिंटन की ओर आना चाहता था. वे बेटे को हमेशा अभ्यास के लिए अपने साथ ले जाते थे. परिवार में शुरू से ही बैडमिंटन का माहौल रहा है, ऐसे में उनका लाडला शुरुआती दौर से ही बैडमिंटन में अपना हुनर तराशने में लग गया. पिता को उम्मीद है कि आने वाले समय में वह भारतीय बैडमिंटन को एक अलग पहचान दिला सकता है. महज दस साल की आयु में बैडमिंटन की ट्रेनिंग लेने वाले लक्ष्य का अपने भाई चिराग के साथ कोच विमल कुमार ने पहली बार ट्रायल लिया. इसके बाद विमल कुमार को भी लगने लगा कि लक्ष्य दूसरे खिलाड़ियों से अलग है. इसके बाद लक्ष्य ने भी अपने कोच को कभी मायूस नहीं किया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए पहले अंडर-13, इसके बाद 17 और अंडर-19 के जूनियर एकल का खिताब जीतकर साबित कर दिया कि वह इस खेल का सरताज बनने के लिए तैयार है. जानकारों की मानें, तो लक्ष्य के खेल में कुछ अलग अंदाज है, जैसे कि वह नेट पर विरोधी खिलाड़ियों की तुलना में मजबूत है, वहीं स्मैश में उसकी ताकत देखते ही बनती है. इसके साथ ही वह बड़ी रैली में दूसरे खिलाड़ियों से आगे है. लक्ष्य जब 11 साल का था, तब से ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ओजीक्यू उन्हें करियर में आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है.

दूसरी ओर लक्ष्य सेन ने खास बातचीत में बताया कि अभी उसने अपने करियर की शुरुआत की है, लेकिन उसका सपना है कि बैडमिंटन में शीर्ष स्थान हासिल करे. जूनियर विश्व रैंकिंग में नम्बर वन की कुर्सी हासिल करने वाले लक्ष्य ने बताया कि वह बैडमिंटन के लिए रोजाना सात से आठ घंटे अभ्यास करता है. जानकारों ने माना है कि उसमें काबिलियत है कि वह अगला गोपीचंद अथवा प्रकाश पादुकोण बन सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब वह बड़ी प्रतियोगिताओं में लगातार अपनी धमक दिखाता रहे. उसने बताया कि जिस तरह से क्रिकेट में विराट कोहली चमक रहे हैं, ठीक उसी तरह से वह बैडमिंटन में विश्व पटल पर चमकना चाहता है. लक्ष्य ने बताया कि सायना और सिंधु जैसे खिलाड़ियों को करीब से खेलते देखने से उन्हें अपने खेल में सुधार करने का अच्छा अवसर मिला है. लक्ष्य ने बताया कि उसका अगला लक्ष्य है जूनियर डच और जर्मन ओपन जैसी बड़ी प्रतियोगिता में खिताब जीतना. उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर के रहने वाले लक्ष्य सेन की उम्र अभी केवल 15 साल है. उनके अभी के खेल को देखकर उनके गुरु यानी प्रकाश पादुकोण की याद आती है. इसी उम्र के आसपास प्रकाश पादुकोण ने भी बैडमिंटन की दुनिया में कदम रखा था और जूनियर स्तर पर अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी थी. हाल में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में सौरभ वर्मा से हारने वाले लक्ष्य सेन ने खूब वाह वाही लूटी. बैडमिंटन के जानकारों की मानें तो आने वाले समय में लक्ष्य भारत को कई सुनहली कामयाबी दिला सकते हैं. इतना ही नहीं, मोदी बैडमिंटन में लक्ष्य का खेल खूब सराहा गया था. इस प्रतियोगिता में कई बड़े खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देकर उसने सबको चौंका दिया था. जूनियर स्तर पर पहचान बना चुके लक्ष्य ने पहली बार सीनियर लेवल पर साल 2016 में भी खूब नाम कमाया, जब ऑल इंडिया सीनियर सीरीज में उसने खिताब जीता था. इतना ही नहीं, जूनियर एशियन चैंपियनशिप में लक्ष्य ने कांस्य पदक भी जीता था. जूनियर स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उसने जूनियर विश्व रैंकिंग में नम्बर वन खिलाड़ी बनकर देश में बैडमिंटन का एक अलग प्रतिमान स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा दिया है. कुल मिलाकर देखा जाये तो आने वाले समय में लक्ष्य भारत में पुरुष बैडमिंटन में एक अलग नाम बनकर उभर सकते हैं. ■

बांग्लादेश का किया शिकार अब कंगारू तेरी बारी

भारतीय टीम अपनी जमीन पर लगातार विदेशी टीम के लिए खतरनाक साबित हो रही है. टीम इंडिया ने पहले न्यूजीलैंड को धोया, इसके बाद इंग्लैंड टीम की भी जमकर खबर ली. अब बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में विजय हासिल की है. भारत की इस जीत के बाद कंगारुओं के लिए अब खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अब भारतीय जमीन पर टेस्ट सीरीज खेलनी है. ऐसे में वह विराट की सेना से डरी हुई है क्योंकि उसे खौफ है कि कहीं टीम इंडिया 4-0 से उसका सफाया न कर दे. जानकारों की मानें तो विराट की सेना स्मिथ के लड़ाकों पर भारी पड़ सकती है. कंगारुओं के एकाध खिलाड़ी भले ही फॉर्म में होने का दावा करें, लेकिन भारत के स्पिन विकेट के आगे टिकना आसान नहीं होगा. कंगारुओं ने हाल में पाक को चित किया है, लेकिन भारत और पाक की टीम में जमीन आसमान का फर्क है. भारत की ताकत है स्पिन, जबकि ऑस्ट्रेलिया भले ही तेज गेंदबाजों पर नाज करे, लेकिन उसे भी मालूम है कि भारतीय विकेट पर केवल स्पिनरों का बोलबाला रहता है. दूसरी ओर भारतीय टीम लगातार कोहली की कमानी में नया कीर्तिमान स्थापित करने में लगी हुई है. बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में टीम इंडिया बल्लेबाजी में एक बार फिर रनों का अम्बार लगाने में कामयाब रही. विराट तो लगातार रनों का पहाड़ बना रहे हैं. क्रिकेट के कई दिग्गज अब विराट को सचिन से ही नहीं, बल्कि डॉन ब्रैडमैन से भी बड़ा खिलाड़ी आंकने लगे हैं. जानकारों की मानें, तो विराट अगर इसी तरह से रन बनाते रहे, तो वह सचिन के रिकॉर्ड को बौना साबित करने में देर नहीं लगायेंगे, साथ ही डॉन ब्रैडमैन जैसे बड़े खिलाड़ी को भी पीछे छोड़ सकते हैं. विराट बांग्लादेश के खिलाफ जीतकर बतौर कप्तान वे टीम इंडिया के तीसरे सफल कप्तान बन गये हैं. उन्होंने 15वीं जीत दर्ज कर अजहर को पीछे छोड़ दिया है. वह माही और दादा के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गये हैं. माही के 60 मैचों में 27, जबकि सौरभ के 49 मैचों में 21 टेस्टों के जीत का रिकॉर्ड है.

बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में विराट ने एक बार डबल सेंचुरी मारकर अपने बल्ले की हनक दिखाई. इतना ही नहीं, कप्तान बनने के बाद विराट में एक अलग तरह का आत्मविश्वास देखा जा सकता है. वह लगातार बल्ले से कमाल कर रहे हैं, साथ ही कमानी में उनकी कोई सानी नहीं दिख रही है. दूसरी ओर आर अश्विन की फिरकी को खेलना अब किसी बल्लेबाज के लिए खौफ का केंद्र बना हुआ है. टेस्ट क्रिकेट में आये दिन अश्विन अपने हुनर को तेजी से चमका रहे हैं. उनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं है लेकिन उनकी गेंदें इतनी तेजी से विकेट पर घुमती हैं कि लोग देखते रह जाते हैं. उनके लगातार मैच जिताऊ स्पैल टीम इंडिया के लिए नए प्रतिमान स्थापित करा रहे हैं. विराट की बल्लेबाजी के साये में कई और खिलाड़ी अपनी चमक दिखा रहे हैं. पुजारा भी पहले की तुलना में अब बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि गेंदबाजी में आर अश्विन की देखरेख में जडेजा भी कमाल की गेंदबाजी करते दिख रहे हैं. तेज गेंदबाजी में भी अच्छा विकल्प देखने को मिल रहा है. अतीत में कुम्बले व भज्जी की जोड़ी भारतीय विकेट पर कहर बनकर टूटती थी लेकिन अश्विन और जडेजा दो नये नाम दुनिया के धाकड़ बल्लेबाजों के लिए अब एक अबूझ पहेली बन गए हैं. दूसरी ओर कंगारू बेहतर तैयारी के साथ भारत कूच कर रहे हैं. ऐसे में विराट की सेना को थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि कंगारू वार करने से चूकते नहीं हैं. हां यह बात भी सत्य है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है. उसके पास अब पोंटिंग जैसा भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं है. अब यह देखना रोचक होगा कि युवा विराट की टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है. विराट का असली इम्तिहान अभी होना बाकी है. अगर कंगारुओं को विराट आसानी से रींद देते हैं, तो उनका विश्व क्रिकेट में कद और बढ़ जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

करीना ने डिलिवरी के बाद ख़ुद को बख़ूबी कैरी किया

अभिनेत्री करीना कपूर खान ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान और डिलिवरी के बाद ख़ुद को इस तरह कैरी किया कि हर कोई देखता रह गया. करीना ने इस दौरान किसी भी चीज को लेकर कोई हिचक नहीं दिखाई. हाल में करीना ने अपनी न्यूट्रिशियन रुजुता दिवेकर के साथ एक फेसबुक लाइव किया. इस मौके पर करीना ने प्रेग्नेंसी के बाद अपने फिटनेस और बेटे तैमूर के बारे में कई खुलासे किए. करीना ने बताया कि बेटे तैमूर की ख़ूबसूरती और फिटनेस का राज बेहतर खान–पान है. करीना कहती हैं कि यह माना कि तैमूर पठान का बेटा है, लेकिन उनके खाने–पीने के कारण बेटे की ख़ूबसूरती और फिटनेस में निखार आया है.

करीना ने आगे बताया कि जब वह प्रेग्नेंट थीं, तब वह खूब घी, दूध, पराठे और पिज्जा खाती थीं जिसकी वजह से तैमूर ख़ूबसूरत बच्चा है.■

मार्च में ये फिल्में करेंगी धमाल

साल 2017 की शुरुआत हो चुकी है. बॉलीवुड को दो महीने में ही रईस, काबिल और जॉली एलएलबी–2 जैसी 3 हिट फिल्में मिल चुकी हैं. इसके अलावा आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को एक से बढ़कर एक फिल्में देखने को मिलेंगी. मार्च महीने में एक–दो नहीं, बल्कि 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना दम–ख़म दिखाने को बेताब हैं. आइए जानते हैं कि मार्च में उन सात फिल्मों के बारे में, जो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होने को तैयार हैं. अब देखना है कि बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म का जादू दर्शकों के दिलों पर चलता है.

प्रवीण कुमार
feedback@chauthiduniya.com

कमांडो–2 | 3 मार्च

एक्शन हीरो विद्युत जामवाल अपने स्टंट और एक्शन की वजह से जाने जाते हैं. इससे पहले विद्युत जॉन अब्राहिम के साथ फिल्म फोर्स में शानदार एक्शन करते दिखाई दिए थे. विद्युत फिल्म *कमांडो–2* में भी जबरदस्त एक्शन करते नज़र आएंगे. कमांडो–2 इस साल 3 मार्च को रिलीज़ हो चुकी है. कमांडो–2, साल 2013 में आई फिल्म *कमांडो* का सिक्वल बताया जा रहा है. लेकिन इस फिल्म की कहानी कमांडो से एकदम अलग होगी. फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं विपुल अमृतलाल शाह.■

आ गया हीरो | 3 मार्च

एक लंबे अर्से के बाद गोविंदा की वापसी होने जा रही है. जी हां, बॉलीवुड के कॉमेडी किंग माने जाने वाले गोविंदा की कमबैक फिल्म *आ गया हीरो* भी 3 मार्च को रिलीज़ हो चुकी है. इस फिल्म में गोविंदा एक्शन हीरो के रोल में नज़र आ रहे हैं. वे एक्शन, डांस और ड्रामा के कॉम्बो पैक में दिखेंगे. प्रोमो में गोविंदा का अंदाज काफी आकर्षक नज़र आ रहा है. फिल्म को गोविंदा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिल्म का नाम पहले *अभिनय चक्र* रखा गया था. इस फिल्म में गोविंदा के अलावा आशुतोष राणा का भी अहम किरदार है.■

मशीन | 17 मार्च

निर्देशक अब्बास–मस्तान की बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान है. वह क्राइम थ्रिलर, एक्शन, कॉमेडी जैसी फिल्में बनाने में माहिर हैं. इस साल वे एक्शन फिल्म *मशीन* के जरिए अपने बेटे मुस्तफ़ा को लॉन्च कर रहे हैं. यह फिल्म 17 मार्च को रिलीज़ होगी. एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी इस फिल्म का प्रमुख हिस्सा हैं.

अब्बास–मस्तान खिलाड़ी, बाज़ीगर, बादशाह, एतराज, सोल्जर, अजनबी, रेस, रेस–2, किस–किस को प्यार करूं, जैसी फिल्में बना चुके हैं.■

फिल्लौरी | 24 मार्च

अनुष्का शर्मा उन अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने शाहरुख़, आमिर और सलमान तीनों के साथ काम किया है और तीनों के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. इस समय अनुष्का हिट फिल्में देने की गारंटी बन चुकी हैं. इस साल वे फिल्म *फिल्लौरी* से बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत करने जा रही हैं. फिल्म फिल्लौरी की ज्यादातर शूटिंग पंजाब में हुई है. फिल्लौरी एक लव स्टोरी फिल्म है, जिसमें अनुष्का शर्मा के साथ अभिनेता दलजीत दोसांझ, सूरज शर्मा के अलावा मेहरीन कौर भी हैं.■

बद्रीनाथ की दुल्हनिया | 10 मार्च

वरुण धवन और आलिया भट्ट की कैमिस्ट्री पर्दे पर ख़ूब जमती है. इस लिहाज से इनकी अगली फिल्म *बद्रीनाथ की दुल्हनिया* का बेसब्री से इंतजार हो रहा है. फिल्म की कहानी बद्रीनाथ (वरुण धवन) और वैदेही (आलिया भट्ट) के बीच प्यार पर आधारित है. फिल्म का बैकग्राउंड उत्तर प्रदेश का है. इससे पहले यह जोड़ी दो फिल्मों में एक साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर और हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम कर चुके हैं और दोनों ही फिल्में हिट रही थीं.■

अनारकली ऑफ आरा | 24 मार्च

फिल्म *अनारकली ऑफ आरा* की कहानी बिहार के आरा जिले की एक ऐसी गायिका स्वरा भास्कर के इर्द–गिर्द घूमती है, जो अश्लील गाने गाती है. कहानी में रोमांचक मोड़ तब आता है, जब अनारकली का सामना एक शक्तिशाली व्यक्ति से होता है जिसने उसका शोषण किया था. वह उसके सामने घुटने टेकने के बजाय उससे लड़ती है. अविनाश दास के निर्देशन में बनी फिल्म अनारकली ऑफ आरा 24 मार्च को रिलीज़ होगी. इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रिया और संदीप कपूर हैं.■

नाम शबाना | 31 मार्च

फिल्म चश्मे बद्दूर से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने बॉलीवुड में अभी तक ज्यादा फिल्में तो नहीं कीं, लेकिन तीन–चार फिल्मों में उन्होंने दमदार भूमिका निभाकर दर्शकों के दिल में जगह जरूर बना ली. उनकी इस साल आने वाली फिल्म *नाम शबाना* है. यह शबाना नामक एक महिला की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म रॉ एजेंट्स और हनी ट्रैप जैसे मामलों को सामने लाती है. माना जा रहा है कि यह फिल्म ऐसी महिला पर आधारित है जो सिस्टम का सहायक अंग है. फिल्म में मनोज वाजपेयी और अक्षय कुमार भी अहम किरदार में दिखाई देंगे.■

शाहरुख की ये फिल्म अप्पू राजा की तरह नहीं है!

शाहरुख का कहना है कि इस रोल की तुलना कमल हासन के अप्पू राजा वाले रोल से नहीं की जाए क्योंकि दोनों ही किरदार काफी अलग हैं.

रईस की सफलता के बाद शाहरुख खान अपने अगले प्रोजेक्ट पर ज़ोर–शोर से लग गए हैं और उनका अगला प्रोजेक्ट है भी शानदार. हालांकि अभी तक लोगों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में अफवाहें ही ज्यादा सुनी हैं, लेकिन अब शाहरुख ने ख़ुद ही इस फिल्म की डीटेल्स शेयर की हैं. आनंद एल राय की इस फिल्म में शाहरुख खान एक बौने का किरदार निभा रहे हैं और उन्होंने अपने रोल के बारे में खुलकर बात की. फिल्म का नाम बंधुआ बताया जा रहा है.

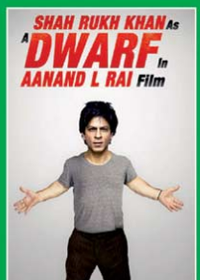

शाहरुख का कहना है कि इस रोल की तुलना कमल हासन के अप्पू राजा वाले रोल से नहीं की जाए क्योंकि दोनों ही किरदार काफी अलग हैं. गौरतलब है कि भले ही वो फिल्म शानदार रही हों, पर बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं थीं. फिल्म में कमल हासन भी सर्कस में काम करने वाले एक बौने के रूप में नज़र आए थे. लेकिन शाहरुख ने कहा कि उनका किरदार एकदम अलग है. फिल्म के बारे में एक और उड़ती ख़बर ये है कि फिल्म में शाहरुख खान एक बौने का किरदार निभा रहे हैं, जिसे एक हीरोइन से प्यार हो जाता है. इसीलिए फिल्म का नाम कैटरीना मेरी जान रखा गया था. बार–बार बौने आदमी की कहानी कहने से फिल्म का फोकस हट जा रहा है. कई ऐसी फिल्में हैं, जो फैन और स्टार का बॉन्ड दिखा चुकी हैं.

आनंद एल राय ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा कि ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रेम कहानी है. जैसी मेरी फिल्म तनु वेड्स मनु या रांझणा में थी. शाहरुख खान का किरदार बौना नहीं है, हां आप उसे छोटे आदमी की कहानी ज़रूर कह सकते हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

जब किंग कांग को दारा सिंह ने दी थी पटखनी

1947 में दारा सिंह ने *भारतीय स्टाइल* की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन त्रिलोक सिंह को हराकर कुआलालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप जीती. पांच साल तक फ्री स्टाइल रेसलिंग में दुनिया भर के पहलवानों को चित्त करने के बाद दारा सिंह भारत आकर 1954 में भारतीय कुश्ती चैंपियन बने.

पिछले साल 2016 में आई सलमान खान की फिल्म *सुल्तान* और साल के अंत में आमिर खान की *दंगल* बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. दोनों ही फिल्में पहलवानी को लेकर बनाई गई थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया. पहलवानी की बात की जाए तो सबसे पहले दारा सिंह का नाम आता है, जिन्होंने एक जमाने में अपनी पहलवानी से कुश्ती को वो मुकाम दिलाया था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. उस जमाने में दारा सिंह को रुस्तम–ए–हिन्द के नाम से जाना जाता था. दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को जाट–सिख परिवार में हुआ था. उनका पूरा नाम दारा सिंह रंधावा है.

पंजाब के अमृतसर जिले में जन्मे दारा सिंह ने अपने समय के बड़े–बड़े पहलवानों को अखाड़े की धूल चटाई थी. रुस्तम–ए–हिन्द दारा सिंह को रेसलिंग के इतिहास में कई मुकाबलों के लिए याद किया जाता रहेगा, लेकिन एक ऐसा भी मुकाबला था, जिसने इस खेल के इतिहास में ऐसी मिसाल बना दी जो कभी भूली नहीं जा सकती. 50 के दशक में एक मुकाबले में दारा सिंह ने अपने से कहीं ज्यादा वजनी ऑस्ट्रेलिया के किंग कांग को पहले तो रिंग में पटखनी दी और फिर उन्हें उठाकर रिंग के बाहर फेंक दिया. आपको बता दें कि तब दारा सिंह का वजन 130 किलो था, जबकि किंग कांग 200 किलो के थे.

बताया जाता है कि 1947 में दारा सिंह ने *भारतीय स्टाइल* की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन त्रिलोक सिंह को हराकर कुआलालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप जीती. पांच साल तक फ्री स्टाइल रेसलिंग में दुनिया भर के पहलवानों को चित्त करने के बाद दारा सिंह भारत आकर 1954 में भारतीय कुश्ती चैंपियन बने. इसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ देशों का दौरा किया और विश्व चैंपियन किंग कॉन्ग को भी धूल चटा दी. दारा सिंह की लोकप्रियता को देख कनाडा के विश्व चैंपियन जार्ज गार्डीयांका और न्यूजीलैंड के जॉन डिसिल्वा ने 1959 में कोलकाता में कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में उन्हें खुली चुनौती दे डाली.

यहां भी दारा सिंह ने दोनों पहलवानों को हराकर विश्व चैंपियनशिप का ख़िताब हासिल किया. वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाऊ थेज को 29 मई 1968 को पराजित कर फ्रीस्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए.

दारा सिंह रियल लाइफ में पहलवान थे और अखाड़ों में अन्य पहलवान उनके नाम से ख़ौफ खाते थे. कुश्ती के सारे दांव वे जानते थे और कई नामी पहलवानों को उन्होंने चित कर दिया. ऊंचे और भरे–पूरे दारा सिंह को फिल्म वालों ने हाथों–हाथ लिया क्योंकि जब वे परदे पर गुंडे और बदमाशों की पिटाई करते थे तो यह बात वास्तविक लगती थी. दारा सिंह अभिनय में तो कमजोर थे, लेकिन एक्शन सीन में जबरदस्त. यही वजह है कि उनकी एक्शन फिल्मों को पसंद करने वाला एक अलग ही दर्शक वर्ग था.

प्रमुख एक्शन फिल्में : किंग कॉन्ग, फौलाद, रुस्तम–ए–बगदाद, सैमसन, आंधी और तूफान, राका, डाकू मंगलसिंह, दादा, एलान–ए–जंग आदि शामिल हैं.

दारासिंह को 7 जुलाई 2012 को दिल का दौरा पड़ गया था. इसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में भर्ती कराया गया. सघन चिकित्सा के बावजूद लाभ न होता देख चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे. तब उनके परिजनों के आग्रह पर अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई थी और इसके बाद उन्हें मुंबई स्थित अपने निवास पर लाया गया. जहां उन्होंने 12 जुलाई 2012 की सुबह अंतिम सांस ली. उनके निधन की ख़बर सुनकर सारा देश स्तब्ध हो गया.■

फ्लैश बैक

दारा सिंह से जुड़ी कुछ ख़ास बातें

- दारा सिंह ने 500 से ज़्यादा पहलवानों को हराया और ख़ास बात ये कि ज्यादातर पहलवानों को दारा सिंह ने उन्हीं के देश में जाकर चित किया. उन्होंने सन् 1983 में कुश्ती से रिटायरमेंट ले लिया.
- सन् 1966 में दारा सिंह को रुस्तम–ए–पंजाब और 1978 में रुस्तम–ए–हिंद के ख़िताब से नवाजा गया.
- दारा सिंह ने करीब 36 साल तक अखाड़े में पसीना बहाया और अब तक लड़ी गई कुल 500 कुश्तियों में से दारा सिंह एक में भी नहीं हारे, जिसकी बदौलत उनका नाम ऑब्जर्वर न्यूजलेटर हॉल ऑफ फेम में दर्ज है.
- अपनी किशोर अवस्था में दारा सिंह दूध व मक्खन के साथ 100 बादाम रोज खाकर कई घंटे कसरत व व्यायाम में गुजारा करते थे.